राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

मोर्गन के छक्कों की बारिश में धुला अफगानिस्तान

>> 12

वर्ष 3 अंक 9

दैनिक जागरण

मूल्य ₹5.00, नई दिल्ली, बुधवार, 19 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

अयोध्या आतंकी हमले में चार को आजीवन कारावास

न्याय ▶ रामजन्मभूमि परिसर में हमले के मामले में आया फैसला, नैनी सेंट्रल जेल में सजा का एलान, 60-60 हजार जुर्माना भी लगा

2005 में लश्कर आतंकियों ने ग्रेनेड और एके-47 से किया था हमला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

अयोध्या के रामजन्मभूमि परिसर में पांच जुलाई, 2005 को हुए आतंकी हमले के मुकदमे में मंगलवार को फैसला आ गया। प्रयागराज की विशेष अदालत ने नैनी सेंट्रल जेल में सुनवाई के बाद चार दोषियों डॉ. इरफान, मो. नसीम, शकील अहमद और आसिफ इकबाल उर्फ फारुख को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुंछ निवासी मो. अजीज सुबूतों के आरोप में बरी हो गया।

> कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस घटना के एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा बरी किया गया है। सरकार इस संदर्भ में विधिक परीक्षण कराकर अपील करेगी।
>
> -योगी आदित्यनाथ, सीएम, उत्तर प्रदेश

विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र दोपहर लगभग ढाई बजे जेल पहुंचे और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा का एलान किया। मामले में 14 पुलिसकर्मियों समेत 63 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे। सभी आरोपितों पर हमले की साजिश रचने, आतंकियों की मदद करने, हथियार मुहैया कराने के आरोप थे। 2006 में हाई कोर्ट के आदेश पर पांचों आरोपितों को फैजाबाद से नैनी जेल भेज दिया गया था। सुरक्षा कारणों से जेल में ही मुकदमे की सुनवाई हुई।

ऐसे रची साजिश: सरकार वकील ने कोर्ट में बताया कि नसीम ने पाकिस्तानी आतंकी कारी के कहने पर मोबाइल फोन का सिम खरीदा था। अजीज ने दस्तावेजों का सत्यापन किया था। मोहम्मद शकील की गाड़ी (जेके 12-0267) से पांच जून, 2005 को हमले के लिए हथियार और विस्फोटक अलीगढ़ लाए गए थे। अलीगढ़ में हथियार रखने के बाद सात जून, 2005 को वाहन जम्मू भेज दिया गया था। आसिफ इकबाल मुख्य आरोपी था। आतंकी कारी ने नसीम द्वारा खरीदा गया सिम आसिफ इकबाल को दिया था।

ढेर कर दिए गए थे पांच आतंकी पेज>>6

इन आतंकियों को हुई उम्रकैद

- आसिफ इकबाल उर्फ फारुख पुत्र मो. बशीर निवासी सखी मैदान, थाना मेंडर जिला पुंछ, जम्मू।
- मो. नसीम पुत्र फिरोजदीन, निवासी डेरा मेंडर, थाना मेंडर, जिला पुंछ, जम्मू।
- शकील अहमद पुत्र नजीर अहमद, निवासी सखी मैदान, थाना मेंडर, जिला पुंछ, जम्मू।
- डॉ. इरफान पुत्र असलम खान, निवासी शेख जादगानान, कस्बा थाना तीतरो, सहारनपुर, उप्र।

आसिफ इकबाल | मु. नसीम | शकील अहमद | डॉ. इरफान

सभी फाइल फोटो जागरण

कब क्या हुआ

- पांच जुलाई, 2005 : सुबह नौ बजे अयोध्या अधिग्रहीत परिसर पर आतंकी हमला, मुठभेड़ के बाद पांच आंतकी ढेर
- पांच जुलाई, 2005 : दोपहर दो बजे के करीब अयोध्या के रामजन्मभूमि थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई
- 22 जुलाई, 2005 : लश्कर के आतंकवादियों के मददगार डॉ. इरफान की गिरफ्तारी
- 28 जुलाई, 2005 : अन्य चार अभियुक्तों आसिफ इकबाल, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अजीज और मोहम्मद नसीम की गिरफ्तारी
- 20 सितंबर, 2006 : मामले की सुनवाई फैजाबाद जिला सत्र न्यायालय से प्रयागराज विशेष न्यायालय में स्थानांतरित
- 11 जून, 2019 : दोनों पक्षों की बहस पर सुनवाई पूरी
- 18 जून, 2019 : विस्फोट के दोषियों को उम्रकैद की सजा

लोकतंत्र के प्रहरी
आपातकाल के 44 साल

पति गए जेल, पत्नी ने सब्जी बेचकर बच्चों को पाला

नई दिल्ली : आपातकाल के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा में रहने वाले लाल बिहारी तिवारी (78) को पुलिस ने रातों रात घर से उठाकर जेल में बंद कर दिया था। इस बीच घर की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गई कि उनकी पत्नी को परिवार चलाने के लिए सब्जियां तक बेचनी पड़ी। ● पेज 13

हमारी सरकार
थावरचंद गहलोत
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री

संघर्ष से हार न मानने की अकूत ताकत ● पेज 5

विश्वास. News

इंडियन ऑयल के नाम पर वायरल हो रही है फर्जी चेतावनी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 7

सरोकार

नक्सल प्रभावित गांवों की आवाज बनीं पत्रकार दीदियां

लातेहार : झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिलाएं विकास की नई इबारत लिख रही हैं। डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम ने गांव की महिलाओं को न सिर्फ जागरूक किया है, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है। इसके जरिये वह मोबाइल, टैबलेट व कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आजीविका का जरिया बना रही हैं। इस बदलाव की वाहक कुछ पत्रकार दीदियां बनी हैं। (पेज-13)

क्रिकेट महाकुंभ
न्यूजीलैंड vs द. अफ्रीका
दोपहर 3:00 बजे से
स्थान : बर्मिंघम
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

पुलवामा हमले का साजिशकर्ता अनंतनाग में साथी समेत ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पुलवामा हमले के मुख्य सूत्रधारों में शामिल जैश-ए-मुहम्मद के कुख्यात आतंकी सज्जाद अहमद बट को सुरक्षाबलों ने मंगलवार को उसके एक साथी के साथ मार गिराया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में हुई इस मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी भी शहीद हुआ है, जबकि तीन जवान जख्मी हो गए। इस दौरान शरारती तत्वों ने पथराव भी किया। तनाव को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि सज्जाद ने ही 14 फरवरी को पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुई मारुति कार खरीदकर वाहन बम बनाने के लिए उपलब्ध कराई थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे।

बिजबिहाड़ा के वागहामा गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना की तीन आरआर, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल ने तड़के तीन बजे घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। जवानों को देख आतंकियों ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान चार सैन्यकर्मी आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आकर जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सैन्यकर्मी अनिल जस्वाल शहीद हो गए। अनिल हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सरोह, चमियारी के निवासी थे।

- मुठभेड़ में मारा गया जैश कमांडर सज्जाद बट, हमले के लिए खरीदी थी कार
- आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सैनिक भी शहीद

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार को बिजबिहाड़ा में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों का ठिकाना बना मकान ध्वस्त हो गया। प्रेट्र

सुबह करीब आठ बजे आतंकियों की तरफ से अंतिम गोली चली। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में वहां छिपे दोनों आतंकी मारे गए। आतंकी ठिकाना बना मकान भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मारे गए आतंकियों की पहचान सज्जाद अहमद बट और तौसीफ अहमद के रूप में हुई है। दोनों ही मरहामा संगम, बिजबिहाड़ा के रहने वाले थे। मुठभेड़स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद भी मिला है।

दक्षिण कश्मीर में जैश का आत्मघाती माड्यूल खत्म : सेना की 15 कोर के जीओसी मेजर जनरल केजेएस ढिल्लो ने बताया कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हमले में इस्तेमाल कार का असली मालिक सज्जाद ही था। वह जैश के आत्मघाती दस्ते का सदस्य बन गया था। उसके साथ मारा गया आतंकी तौसीफ ही उसका हैंडलर था। तौसीफ पर सात लाख रुपये का इनाम था। इन दोनों के मारे जाने से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय जैश का स्थानीय आतंकियों का आत्मघाती मॉड्यूल भी लगभग समाप्त हो गया है।

कौन था सज्जाद बट : सज्जाद अहमद बट जैश के आत्मघाती दस्ते का सदस्य था। वह गत 14 फरवरी को लिथपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर वाहन बम हमले से चंद दिन पहले ही जैश का हिस्सा बना था। उसका कोड अफजल गुरु था। सज्जाद के पिता मोहम्मद मकबूल बट ने आतंकी बुरहान की मौत पर दक्षिण कश्मीर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह इसी सिलसिले में 2017 में पकड़ा गया था।

पुलवामा में आतंकियों ने थाने पर ग्रेनेड से किया हमला, आठ जख्मी पेज>>6

ओम बिरला होंगे लोकसभा के नए अध्यक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बतौर राजग प्रत्याशी दाखिल किया नामांकन, निर्वाचन पर आज मुहर
- बीजद, वाइएसआर कांग्रेस जैसे गैर राजग दलों ने भी किया समर्थन
- कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों से भी मिल गया समर्थन

राजस्थान के कोटा से दूसरी बार सांसद ओम बिरला अब लोकसभा के नए अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। फिलहाल इस पद के लिए अब तक सिर्फ उन्हीं का नामांकन हुआ है। ऐसे में उनका चयन तय है। बावजूद इसके उनके नाम की अधिकृत घोषणा बुधवार को इस पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी।

भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद के लिए ओम बिरला का नाम सुझाया है। इसके बाद पार्टी ने उनके नाम को अंतिम रूप दिया है। इस बीच, कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों से भी उन्हें समर्थन मिल गया है। लोकसभा अध्यक्ष पद के राजग के प्रत्याशी ओम बिरला के नाम का 12 सदस्यों वाले बीजू जनता दल (बीजद) ने भी समर्थन किया है। लोकसभा में बीजद के नेता पिनाकी मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बीजद को उपाध्यक्ष पद मिलने के सवाल को टालते हुए कहा, फिलहाल सत्ताधारी दल की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। प्रस्ताव आएगा, तो पार्टी अध्यक्ष विचार करेंगे।

तीन बार विधायक व दो बार सांसद : राजनीतिक गलियारों में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला का नाम भले ही चौंकाने वाला रहा है, लेकिन संसदीय अनुभव उनके पास है। 57 वर्षीय बिरला तीन बार (2003, 2008 और 2013) राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने संसदीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली है। वह लगातार दूसरी बार कोटा से जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस के रामनारायण मीणा को 2.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। बतौर सांसद उनकी सदन में उपस्थिति 86 फीसद रही। उन्होंने 671 सवाल पूछे और 163 संसदीय चर्चाओं में हिस्सा लिया। वर्ष 1991 से लेकर 12 सालों तक वह भाजयुमो के प्रमुख नेता रहे हैं। राज्य में वह भाजयुमो अध्यक्ष रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष का पद संभाला है। राजनीति के क्षेत्र में उन्हें सबको साथ लेकर चलने में माहिर माना जाता है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल में यातनाएं भोगीं। माना जा रहा है कि वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में विपक्षी दलों को भी साधने में कामयाब रहेंगे।

राजस्थान को अहमियत भी वजह : बिरला के चयन को लेकर संदेश ढूंढने की कोशिश होगी। अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो राजस्थान से पार्टी न सिर्फ सभी सीटें जीती बल्कि वोट भी करीब साठ फीसद था। फिलहाल राजस्थान से मोदी मंत्रिमंडल में तीन मंत्री हैं। ओम बिरला विजयी रहने पर आठ बार की सांसद और निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की जगह लेंगे। (पेज-3)

भाजपा सांसद ओम बिड़ला। प्रेट्र

अधीर रंजन होंगे लोकसभा में कांग्रेस के नेता

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बंगाल की बेहरामपुर सीट से पांचवीं बार सांसद बने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस के नेता पद के लिए नामित किया गया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई बैठक में उनके नाम पर फैसला हुआ। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सांसद होने के नाते उसे लोकसभा में 'विपक्ष के नेता' का पद नहीं मिला है। पार्टी को इस पद के लिए कम से कम 55 सीटों की दरकार थी। (पेज-4)

मिड डे मील के साथ अब सालाना जांची जाएगी बच्चों की सेहत भी

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य की अब साल में एक बार अनिवार्य रूप से जांच होगी। यह कवायद मिड-डे मील योजना के तहत संचालित होगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार के तहत अब इसे स्कूलों से भी जोड़ा जाएगा। मोबाइल हेल्थ टीम पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी करीब तीस तरह की गंभीर बीमारियों की जांच होगी। यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस जांच से एक भी बच्चा छूटे नहीं। स्कूली बच्चों में पढ़ाई के दौरान सामने आ रही तरह-तरह बीमारियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसकी शुरुआत प्राथमिक स्कूलों से होगी। बाद में इसे 12 तक के स्कूलों में भी विस्तार दिया जाएगा। इस पूरी योजना में सरकारी और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों दोनों ही शामिल किए गए हैं। बच्चों को रक्त की कमी से बचाने के लिए उन्हें नियमित रूप से आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाएंगी।

स्कूलों में अनिवार्य रूप से मनेगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस : स्कूलों बच्चों को कृमि (पेट के कीड़े) और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए स्कूलों में हर साल अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देश में हर साल 10 फरवरी को कृमि दिवस मनाया जाता है।

अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 15 अफसरों की छुट्टी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपित थे, तय समय से पहले रिटायर किए गए अधिकारी

एक हफ्ते पहले दर्जनभर आयकर अफसरों की छुट्टी करने के बाद सरकार ने अब भ्रष्टाचार का सामना कर रहे सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 15 अफसरों को जबरन सेवामुक्त कर दिया है। इन अफसरों में असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर प्रिंसिपल कमिश्नर तक शामिल है।

वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, फंडामेंटल रुल्स के रूल 56 (जे) के तहत सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के इन अफसरों को हटाया है। इनमें से कुछ पहले से ही निलंबित थे। कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं जबकि कई अन्य पर रिश्वतखोरी, वसूली और आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। सेवा से मुक्त किए गए अफसरों में दिल्ली में तैनात सीबीआइसी के प्रिंसिपल एडीजी (ऑडिट) अनूप श्रीवास्तव भी शामिल हैं। श्रीवास्तव के खिलाफ सीबीआइ ने 1996 में एक हाउसिंग सोसायटी को फायदा पहुंचाने के संबंध में आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया था। 2012 में भी अनूप के खिलाफ ड्यूटी चोरी के मामले में आयातक से घूस लेने का आरोप है। उन पर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, उत्पीड़न के भी आरोप है। संयुक्त आयुक्त नलिन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले दर्ज हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन अफसरों की आयु 50 साल हो गई है, इसलिए जनहित में इन्हें जबरन रिटायर किया गया है।'

कोलकाता में तैनात कमिश्नर संसार चंद भी कथित तौर पर रिश्वतखोरी में लिप्त था। चेन्नई के कमिश्नर जी. श्री हर्षा ने आय के ज्ञात स्रोतों से 2.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा कर रखी थी। दोनों अफसरों को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। निलंबन में चल रहे कमिश्नर रैंक के दो अधिकारी अतुल दीक्षित और विनय बृज सिंह को भी सेवा मुक्त किया गया है। हटाए गए अफसरों में दिल्ली जीएसटी जोन के डिप्टी कमिश्नर अमरेश जैन के पास आय से 1.55 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति है। सेवा मुक्त अन्य अफसरों में एडिशनल कमिश्नर अशोक महीदा (डीजी सिस्टम्स कोलकाता), एडिशनल कमिश्नर वीरेंद्र अग्रवाल, असिस्टेंट कमिश्नर एसएस पाबना (निलंबित), एसएस बिष्ट (भुवनेश्वर जीएसटी जोन), बिनोद सांगा (मुंबई जीएसटी जोन), राजू सेकर (विशाखापत्तनम जीएसटी जोन), मोहम्मद अल्ताफ (इलाहाबाद), डिप्टी कमिश्नर अशोक अस्वाल (लाजिस्टिक महानिदेशालय दिल्ली) शामिल हैं।

प्रख्यात वकील आनंद ग्रोवर के खिलाफ विदेशी चंदे के दुरुपयोग का केस दर्ज

- सीबीआइ ने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट मिलने के बाद की कार्रवाई

नई दिल्ली, आइएएनएस/प्रेट्र : सीबीआइ ने प्रख्यात अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और मुंबई स्थित उनके गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) 'लॉयर्स कलेक्टिव' के खिलाफ 'फॉरेन कांट्रिब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट' (एफसीआरए) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। ग्रोवर पर विदेशी चंदे को हासिल करने में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ज्ञात हो, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात आनंद ग्रोवर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के पति हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने 13 जून को गृह मंत्रालय से इस संबंध में रिपोर्ट मिलने के बाद आनंद ग्रोवर के खिलाफ एफसीआरए, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, ग्रोवर ने विदेशी चंदे का दुरुपयोग किया है। मंत्रालय की शिकायत के अनुसार, जो कि अब एफआइआर का भी हिस्सा है, एनजीओ ने वर्ष 2006-07 और 2014-15 के बीच 32.39 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा हासिल किया था। इसमें कई अनियमितताएं बरती गईं। उपलब्ध जानकारी व एनजीओ के रिकार्ड की जांच से पता चला है कि एफसीआरए, 2010 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। 19 से 23 जनवरी, वर्ष 2016 के बीच एनजीओ के दस्तावेजों और एकाउंट्स की जांच के बाद मंत्रालय से एनजीओ से सवाल भी किए लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिला।

हटेगी शर्त

ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के लिए शैक्षिक योग्यता की शर्त हटाएगी सरकार, रोजगार बढ़ाने व ड्राइविंग में दक्ष अनपढ़ों को लाइसेंस देना मकसद

अब अनपढ़ भी ले सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सड़क हादसों में मरने वालों की बढ़ती संख्या के बावजूद सरकार ट्रांसपोर्ट वाहन लाइसेंस हासिल करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाने पर विचार कर रही है। अभी केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम आठ के तहत ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए उम्मीदवारों का कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है। सरकार शीघ्र ही इसमें संशोधन की अधिसूचना जारी करने वाली है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त समाप्त करने के पीछे सरकार की ओर से दो कारण बताए गए हैं। इनमें एक कारण है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने का, जो कुछ हद तक सही नजर आता है। लेकिन जो दूसरा कारण बताया गया है वो हैरान करने वाला है। सरकार का कहना है कि ड्राइवरों के लिए शैक्षिक योग्यता खत्म करने का सुझाव हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि मेवात क्षेत्र में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो वाहन चलाना जानते हैं, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता। लिहाजा उनका डीएल बनवाने के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाया जाना जरूरी है।

कुछ शर्तें भी होंगी : बहरहाल, शैक्षिक योग्यता की शर्त हटने से ड्राइवरों की ड्राइविंग कुशलता पर प्रतिकूल असर न पड़े इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें जोड़ने का फैसला किया है। इनमें एक शर्त ये है कि उम्मीदवार को ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी होगा। यही नहीं, ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या प्रतिष्ठान को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर को रोड साइन पढ़ने तथा ड्राइवर लॉग बुक भरने के अलावा ट्रक और ट्रेलर की जांच करने तथा यात्रा से पहले और बाद जरूरी रिकॉर्ड भरना आता है। इतना ही नहीं, उसमें कागजात में खामियों की समझ के साथ ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा सुरक्षा संबंधी खतरों के बारे में सूचित करने का हुनर भी होना चाहिए।

सरकार का ये प्रस्ताव संशोधित मोटर वाहन बिल के प्रस्ताव को संसद में नए सिरे से पेश किए जाने से ठीक पहले फिर से सामने आया है। पिछली सरकार में भी इसे संशोधित मोटर बिल के जरिये लाया गया था। संसदीय समिति में भी इस पर चर्चा हुई थी और कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। विपक्ष के विरोध के कारण ही लोकसभा से पारित होने के बावजूद बिल राज्य सभा में जाकर अटक गया था और प्रवर समिति को भेजना पड़ा था। बाद में आम चुनाव की घोषणा होने के कारण बिल की वैधता खत्म हो गई थी। अब सरकार उस बिल को नए सिरे से संसद में पेश करने वाली है।

ट्रक चालकों की गलती से होते हैं सबसे ज्यादा सड़क हादसे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सबसे ज्यादा सड़क हादसे ड्राइवरों की गलती से होते हैं। यही वजह है कि परिवहन विशेषज्ञों ने ड्राइवरों के लिए शैक्षिक योग्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि जिस तरह देश में गंभीर हादसे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार को ऐसे कदमों से बचना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता खत्म करने के सरकार के प्रस्ताव पर इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अध्यक्ष केके कपिला ने कहा कि सरकार को संयुक्त राष्ट्र में किए वादे के अनुसार सड़क हादसों और मौतों में कमी लाने के लिए ठोस उपाय करना चाहिए। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के संयोजक एसपी सिंह ने भी सरकार के प्रस्ताव को विपरीत दिशा में उठाया गया कदम बताया है। उनके मुताबिक चूंकि गाड़ियों के मैकेनिज्म के साथ कागजी प्रक्रियाएं जटिल व डिजिटल हो गई हैं। ऐसे में ड्राइवरों का पर्याप्त शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए सरकार को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के साथ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट को भी लागू करना चाहिए, ताकि ड्राइवरों का वेतन बढ़े। इससे पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा इस क्षेत्र में आने को प्रेरित होंगे।

ड्राइवरों की चूक से सर्वाधिक हादसे : वर्ष 2017 में देश में कुल 4,64,910 सड़क हादसों में 1,47,913 लोग मारे गए थे और 4,70,975 लोग घायल हुए थे। सबसे ज्यादा 84 फीसद सड़क हादसे ड्राइवरों खासकर वैध लाइसेंसधारी ड्राइवरों की गलती से होते हैं। इनमें भी 21 फीसद हादसों का संबंध ट्रक, टेंपो और ट्रैक्टर चालकों से होता है। दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना है। बढ़िया सड़कों और तुरंत स्पीड पकड़ने वाली गाड़ियों के कारण ऐसे हादसे तेजी बढ़ रहे हैं।

YOUR DREAM, OUR MISSION
YOUTH DESTINATION
IAS • PCS
सामान्य अध्ययन
निःशुल्क कार्यशाला से बैच प्रारंभ
21 June
ONLINE/ LIVE CLASS AVAILABLE
11:30 AM
"अपने सपनों को करें साकार, भारत के विशिष्ट एवं बेहतरीन अध्यापकों के साथ"
& YOUTH DESTINATION TEAM
वैकल्पिक विषय
इतिहास
By रजनीश राज सर
17 June 6:00 PM
24 June 8:30AM
लोक प्रशासन & ETHICS
19 June 9:00 AM
25 June 3:30 PM
By अभय कुमार सर
ONLINE/ LIVE CLASS AVAILABLE
9811334434, 9811334480
web : www.youthdestination.in | youtube: youthdestinationias | FB: youthdestinationias
639, DR. MUKHERJEE NAGAR, OPP. SIGNATURE APARTMENT, DELHI-110009

5 लाख से अधिक छात्र डीयू में स्नातक, परास्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर चुके हैं। करीब चार लाख छात्रों ने आवेदन शुल्क भी जमा कर दिया है। दाखिले के लिए आवेदन की तिथि 22 जून तक है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 19 जून 2019

ग्रामीण सेवा चालक पर दर्ज हैं पहले से चार केस

मुखर्जी नगर मामला ▶ फुटेज देखने व दोनों ओर से दर्ज हुए केसों का अध्ययन करने के बाद जांच शुरू करेगी क्राइम ब्रांच

पुलिस ने लोगों से मोबाइल से बनाए गए वीडियो सौंपने की अपील की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुखर्जी नगर में ग्रामीण सेवा के जिस चालक सरबजीत सिंह पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और उस पर कृपाण से हमला करने का आरोप है, उस पर पहले से भी चार केस दर्ज हैं। पुलिस को उम्मीद है कि उसके खिलाफ और भी केस दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में वह और जानकारी हासिल कर रही है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मुखर्जी नगर मामले में अगर किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाई है तो वे उक्त वीडियो उन्हें सौंप दें।

सरबजीत सिंह व पुलिस के बीच हुए झगड़े और मारपीट के बाद शुरू हुआ बवाल मंगलवार को तीसरे दिन शांत तो हो गया, लेकिन धार्मिक रंग देने के कारण यह मामला दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही भारी पड़ गया। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने फिलहाल जांच शुरू नहीं की है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी का कहना है कि पहले दर्ज दोनों केसों का अध्ययन किया जाएगा और वीडियो देखी जाएगी। उसके बाद जांच शुरू की जाएगी।

सोमवार को इस विवाद के बढ़ने पर पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर दो मामले दर्ज किए गए थे। पहला केस एएसआइ योगराज की शिकायत पर सरबजीत सिंह व अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया। सरबजीत द्वारा कृपाण से हमले में योगराज घायल हो गए थे। उनके सिर पर छह टांके आए हैं। उनकी शिकायत पर थाना पुलिस ने तीन धाराओं के तहत केस तो दर्ज किया, लेकिन हत्या के प्रयास की धारा नहीं लगाने पर पुलिसकर्मियों में गहरा रोष है। उधर, सरबजीत सिंह की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने दोनों केस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं।

सेवादार का हाथ तोड़ने का आरोप : थाना पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सरबजीत सिंह के खिलाफ मारपीट व झगड़ा करने के आरोप में पहले भी चार केस दर्ज हैं। बीते तीन अप्रैल को गुरदासपुर, पंजाब के रहने वाले मंगल सिंह ने संसद मार्ग थाने में सरबजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह गुरुद्वारा बंगला साहिब में सेवादार का काम करते हैं और वहीं पर रहते हैं। तीन अप्रैल को उनकी व शालू सिंह की सुबह आठ से रात आठ बजे तक ड्यूटी थी। शाम को सरोवर के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सरबजीत सिंह सोया हुआ था और उसका बेटा पास में बैठा हुआ था। जब उन्होंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो सरबजीत सिंह उनसे झगड़ पड़ा। मंगल सिंह का आरोप है कि सरबजीत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और हाथ मरोड़कर तोड़ दिया। पुलिस ने जब सरबजीत को गिरफ्तार कर पूछताछ की तब उसने अपना पता बुराड़ी का बताया था।

पुलिस का कहना है कि इसके अलावा 20 सितंबर 2006, 24 जुलाई 2011 व 27 जुलाई 2013 को भी सरबजीत सिंह ने कानून अपने हाथ में लेकर मारपीट की थी। उसके खिलाफ तिमारपुर समेत अलग-अलग थानों में झगड़ा, मारपीट व शांति भंग करने की धाराओं में केस दर्ज है।

भीड़तंत्र के आगे बेबस दिखी पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **समझाने गए एसीपी को दौड़ाकर पिटाई करते दिखे लोग**

मुखर्जी नगर बवाल में दिल्ली पुलिस प्रारंभ से ही भीड़तंत्र के आगे बेबस दिखी। सोमवार रात हंगामा कर रहे लोगों को समझाने गए दिल्ली पुलिस के एसीपी को भीड़ ने दौड़ा लिया। उन्हें मुखर्जी नगर थाने के गेट के पास खींचकर पीटा गया। भीड़ का शिकार सिर्फ पुलिस ही नहीं, आम जनता भी हुई। चालक सरबजीत की पिटाई के बाद इकट्ठा हुए आक्रोशित लोगों ने वहां से गुजर रहे वाहन चालकों से भी बदतमीजी की। कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, लेकिन पुलिस पूरी तरह से लाचार दिखी।

भीड़तंत्र के हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में लोग मुखर्जी नगर थाने में हंगामा करते दिख रहे हैं। यह वीडियो रविवार रात मुखर्जी नगर में ऑटो चालक पिता-पुत्र के पिटाई के ठीक बाद की है। इसमें भीड़ में शामिल लोगों के आगे डीसीपी बेबस दिख रही हैं। पहले भीड़ के दबाव में उन्होंने पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने की बात कही। फिर निलंबित करने का आश्वासन दिया। भीड़ इस पर भी नहीं मानी। डीसीपी को स्टेनो को बुलवाकर तत्काल आदेश टाइप कराना पड़ा, जिसके बाद लोग थाने से बाहर गए।

जाम मे जूझते रहे लोग : सोमवार देर रात भीड़ ने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर जाम लगा दिया। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों को दो घंटे तक जाम में जूझना पड़ा। घरों से निकले लोगों के घर वाले हंगामे की जानकारी पाकर परेशान हो गए। वे फोन कर अपनों का हाल लेते रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस भीड़ पर काबू पा सकी, जिसके बाद जाम खुला और लोग घरों को जा सके।

युवाओं के बीच बांटी गई थी तलवारें : सोमवार रात मुखर्जी नगर थाने के बाहर तलवार लेकर लोग पहुंचे थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें युवा गाड़ियों से तलवार निकालते दिख रहे हैं। तलवारों को युवाओं के बीच बांटा जा रहा है। भीड़ को कुछ लोग उकसाने का भी प्रयास करते दिख रहे हैं।

दूसरे राज्यों से भी आए थे लोग : मुखर्जी नगर थाने के बाहर जाम लगाने के लिए लोग हरियाणा, पंजाब व अन्य जगहों से भी आए थे। इसके लिए सोमवार को दिन में ही सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कर दिया गया था। इसे पिता-पुत्र की पिटाई को पुलिस का एक वर्ग विशेष के खिलाफ हमला बताकर वायरल किया गया। इसी का नतीजा रहा है कि सैकड़ों लोग थाने के बाहर पहुंचे गए। साथ ही भीड़ उग्र भी थी।

मुफ्त यात्रा योजना को 90 फीसद से ज्यादा महिलाओं का समर्थन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा मेट्रो व बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना को लेकर कराए गए जनमत संग्रह में 98.8 फीसद महिलाओं ने योजना का समर्थन किया है। जनमत संग्रह के परिणाम के बारे में दिल्ली प्रदेश संयोजक व दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आठ से 17 जून तक जनमत संग्रह कराया गया। आप के विधायकों, पार्षदों और महिला विंग ने सर्वेक्षण के माध्यम से शहर भर की महिलाओं से बातचीत की। इन 10 दिनों में, झुग्गी-बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों, हाउसिंग सोसायटी सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ लगभग 1120 बैठकें आयोजित की गईं। इस दौरान 71,552 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। इसमें 64,972 लोगों ने योजना का समर्थन किया। गोपाल राय ने कहा कि मुफ्त यात्रा योजना के संबंध में एकत्रित की गई यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अपनी अगली रणनीति बनाएगी।

मेट्रो से पहले महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर योजना लागू हो सकती है। सरकार चाहती है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। दिल्ली परिवहन निगम की ओर से इस बारे में प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा जा चुका है। गोपाल राय का कहना है कि इस बारे में कैबिनेट में ही फैसला किया जाएगा। मगर मेट्रो योजना में देरी होने पर बसों में योजना पहले शुरू किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

न्यूज गैलरी

हिंदू शरणार्थी कैंप के बच्चों को स्कूल में मिले दाखिला : आयोग

नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सदस्यों ने मजनू का टीला स्थित कैंप में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बिजली विभाग को यहां पर बिजली की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। एनसीपीसीआर के सदस्य यशवंत जैन व रोजी ताबा ने बताया कि शरणार्थी कैंप का निरीक्षण स्थानीय प्रशासन के साथ किया गया। इस दौरान देखने में आया कि लोग बिजली और शौचालय की समस्या को लेकर परेशान हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सिविल लाइंस के एसडीएम को इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए। (जासं)

दिल्ली सरकार ने लागू की मुख्यमंत्री आवास योजना

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जगह मुख्यमंत्री आवास योजना लागू कर दी है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा कुछ माह पहले भेजे गए प्रस्ताव पर दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में मुहर लगा दी है। अब इस योजना के तहत ही झुग्गी वालों को झुग्गी के बदले फ्लैट दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले तैयार हो चुके 18 हजार फ्लैट को शामिल किया जाएगा। इसे अगले कुछ दिनों में झुग्गी वालों को आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा जहां झुग्गी, वहीं फ्लैट देने की योजना के तहत भी फ्लैट दिए जाएंगे। पहले चरण में पांच झुग्गी बस्तियों को शामिल किया जाएगा। (जासं)

डीयू की छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की

नई दिल्ली : डीयू से संबद्ध पीजीडीएवी (मॉर्निंग) कॉलेज की दो छात्राओं ने एक शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में लाजपत नगर थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी गई शिकायत में छात्राओं ने कहा कि आरोपित शिक्षक उन्हें बहाने से अपने कमरे में बुलाता था और वहां अश्लील बातें करता था। विरोध करने पर वह करियर बर्बाद करने की धमकी देता था। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि वह कई बार बाहर घूमने चलने का भी दबाव बनाता था। पीजीडीएवी कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि मामले की शिकायत मिलते ही कॉलेज की आंतरिक जांच समिति ने जांच शुरू कर दी है। (जासं)

दिल्ली में बनेगा गुरु नानक बाग

नई दिल्ली : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली में एक विशेष बाग बनाने का फैसला किया है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस बाग का नाम गुरुनानक बाग रखा जाएगा। इसे लेकर कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख नेताओं का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पर्यावरण और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिला। (जासं)

आप सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि दिल्लीवासी भीषण गर्मी के दिनों में भी बिजली कटौती और पेयजल किल्लत से परेशान हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार इन समस्याओं से निजात दिलाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, बच्चे, महिलाएं और वृद्ध हैं। आलम यह है कि दिल्ली सरकार ने बिजली-पानी की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने तक की कोई योजना नही बनाई।

शीला संगम विहार विधानसभा क्षेत्र के रतिया मार्ग, संगम विहार एमबी रोड पर आयोजित धरने को संबोधित कर रही थीं। उनके साथ पूर्व सांसद रमेश कुमार, पूर्व विधायक शीश पाल, बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, जगप्रवेश कुमार भी मौजूद रहे। बिजली-पानी संकट के विरोध में मंगलवार को दिल्ली की ज्यादातर विधानसभाओं में धरना दिया गया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ, राजेश लिलोठिया और देवेंद्र यादव ने भी विभिन्न विधानसभाओं में आयोजित धरनों में हिस्सा लिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कुमार कोचर ने मालवीय नगर विधानसभा में गौतम नगर के धरने में शिरकत की। प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री रमाकांत गोस्वामी ने करोलबाग व राजेंद्र नगर विधानसभा के इंद्रपुरी क्षेत्र में आयोजित धरनों में हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल चांदनी चौक विधानसभा के धरने में शामिल हुए।

संगम विहार में बिजली और पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन के दौरान मटका फोड़कर विरोध जाहिर करतीं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित। जागरण

बिजली-पानी संकट पर पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करने के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी दिल्ली सरकार की नाकामियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ट्विटर पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत दिल्लीवासी पांच साल, दिल्ली बेहाल जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विफलताएं बता सकते हैं।

भाजपा उप्र की महंगी बिजली पर भी कुछ बोले : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली में देश में सबसे सस्ती बिजली जनता को उपलब्ध करा रही है। बिजली भी जनता को 24 घंटे दी जा रही है। फिर भी भाजपा उनकी सरकार के खिलाफ उल्टा-सीधा बोलती है। मगर हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बिजली दिल्ली की अपेक्षा बहुत महंगी है। वहां की सरकार बिजली के दामों में 25 फीसद की और बढ़ोतरी करने जा रही है। मगर भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती। इस मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के लोग दिल्ली में बिजली के दामों को लेकर तो प्रदर्शन करते हैं, परंतु जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां जनता का शोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विभाग को लिखा है कि नोएडा से लेकर पूरे प्रदेश में बिजली के दामों में 25 फीसद की बढ़ोतरी कर दी जाए। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी और ऊपर से सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश की जनता पर दोहरी मार है।

सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली में 200 यूनिट तक का मूल्य एक रुपये प्रति यूनिट है, जबकि इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में 150 यूनिट तक 4.90 रुपये प्रति यूनिट है। दिल्ली में 400 यूनिट तक 2.50 रुपये प्रति यूनिट मूल्य है, जबकि उत्तर प्रदेश में 400 यूनिट तक का मूल्य 6.20 रुपये प्रति यूनिट है।

भाजपा का कुनबा बढ़ाने को विस्तारक संभालेंगे मोर्चा

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

भाजपा का सदस्यता अभियान छह जुलाई से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पास अपना जनाधार मजबूत करने का यह अच्छा मौका है। इसे ध्यान में रखकर उसने तीन हजार विस्तारकों को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जो भाजपा का कुनबा बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सांसद व विधायक से लेकर मंडल स्तर के पदाधिकारियों को विस्तारक के तौर पर सदस्यता अभियान में अपना योगदान देना होगा।

इस अभियान के लिए दिल्ली भाजपा के महामंत्री कुलजीत चहल को प्रदेश सदस्यता प्रमुख तथा हर्ष मल्होत्रा को सह प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन के परामर्श से अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बुधवार को आइटी सेल की कार्यशाला होगी जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद प्रदेश में सदस्यता अभियान की तैयारी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सदस्यता प्रमुख 22 जून तक दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में सदस्यता प्रमुखों व सह प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे। प्रत्येक जिला सदस्यता प्रमुख 30 जून तक मंडलों में सदस्यता प्रमुखों व सह प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे, जिससे कि जमीनी स्तर पर अभियान चलाने में किसी तरह की परेशानी न हो। छह जुलाई से 11 अगस्त तक अभियान चलेगा, जिसमें पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता काम करेंगे।

> पार्टी का जनाधार बढ़ाने में दिल्ली के सभी नेता व कार्यकर्ता अपना योगदान देंगे। सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जनसंपर्क करने के साथ ही सोशल मीडिया व प्रचार के पारंपरिक तरीकों का भी सहारा लेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली के लोग भाजपा से जुड़ने को उत्साहित हैं।
> **–कुलजीत चहल, दिल्ली भाजपा के महामंत्री**

इस समय दिल्ली में पार्टी के लगभग 14 लाख सत्यापित सदस्यों (जिनसे कार्यकर्ता मिल चुके हैं) के साथ ही कुल 22 लाख सदस्य हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि वर्तमान सदस्यों की संख्या में 20 फीसद की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस लिहाज से दिल्ली में लगभग साढ़े चार लाख नए सदस्य जोड़े जाने हैं, लेकिन पार्टी ने 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे कि कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित हो सके।

सदर बाजार में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सदर बाजार के प्रेस गली और पान मंडी के नुक्कड़ पर स्थित चार मंजिला बिल्डिंग का एक हिस्सा मंगलवार की सुबह भरभरा कर गिरा गया। गनीमत रही कि घटना सुबह होने की वजह से बिल्डिंग के आसपास कोई मौजूद नहीं था। गली में दुकानें होने की वजह से दिन में यहां काफी चहल-पहल रहती है। ऐसे में यदि हादसा दिन में होता तो कई लोगों की जान को खतरा हो सकता था। घटना के बाद दमकल और बचाव दल ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन आस-पास की बिल्डिंग को खाली करवा दिया। वहीं, देर शाम तक भवन के जर्जर अन्य हिस्से को ढहाने का काम जारी था।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक बिल्डिंग करीब 70 वर्ष पुरानी है। एक साल पहले इस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया था। इसके बावजूद निगम प्रशासन ने इसे ध्वस्त नहीं कराया। हालांकि, बिल्डिंग की जर्जर हालत को देखते हुए मकान मालिक ने एक महीने पहले ही छत पर रहने वाले मजदूरों से कमरे खाली करा लिए थे। पुलिस के अनुसार यह इमारत राजपुर रोड निवासी सतीश नाम के व्यक्ति की है। करीब 100 गज जगह में बनी इस चार मंजिला बिल्डिंग के भूतल में करीब आठ दुकानें, जबकि ऊपर के हिस्से में कमरे बने हुए थे। दुकानों में राखी, किताबें और स्पोर्ट्स का सामान बेचा जा रहा था। ऊपर के कमरों का प्रयोग ऊन और अन्य सामान के गोदाम के रूप में किया जा रहा था। वहीं बिल्डिंग की छत पर बने अस्थाई कमरे में मजदूर रहते थे।

सदर बाजार क्षेत्र में इमरात ढहने के बाद घटनास्थल पर पड़ा मलबा। पारस कुमार

सदर बाजार में गिरने वाली बिल्डिंग की मरम्मत लंबे समय से नहीं कराई गई थी। दमकल अधिकारियों के मुताबिक हादसे की सूचना उन्हें मंगलवार की सुबह 6.25 बजे मिली थी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम मलबा हटा रही थी, इसी बीच करीब आठ बजे 50 गज में स्थित बिल्डिंग के भूतल को छोड़ ऊपर की मंजिलें भी ढह गईं।

स्टेशन पर युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर खुदकशी कर ली। युवक की पहचान बुराड़ी के जगतपुर निवासी नितिन सिंह (24) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक का अवसाद का इलाज चल रहा था। माना जा रहा है कि बीमारी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। घटना की वजह से यलो लाइन पर करीब आधे घंटे तक मेट्रो सेवा प्रभावित रही।

सीआइएसएफ के मुताबिक घटना दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। नितिन प्लेटफार्म संख्या-1 के पास चहलकदमी कर रहा था। जैसे ही मेट्रो प्लेटफार्म पर आई, वह उसके आगे कूद गया। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक नितिन मेट्रो की चपेट में आ चुका था। काफी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला जा सका। घटनास्थल से नितिन का बैग मिला है। उसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस व चिकित्सकीय दस्तावेज थे। नितिन के पिता मुनिपाल ने बताया कि घटना से करीब डेढ़ घंटे पहले वह घर से निकला था। जसराम अस्पताल में दो साल से उसका अवसाद का इलाज चल रहा था। इलाज के बावजूद अवसाद की बीमारी कम नहीं हो रही थी।

लॉ फैकल्टी की प्रमुख ने कुलपति को सौंपा इस्तीफा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की लॉ फैकल्टी की प्रमुख व डीन प्रो. वेद कुमारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कुलपति प्रो. योगेश त्यागी को त्यागपत्र सौंप दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि डीयू की अनुशासनात्मक समिति ने उन छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने लॉ फैकल्टी के शिक्षकों को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाया है। कुलपति ने त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया है।

14 जून को दिए त्यागपत्र में उन्होंने लिखा कि दो सितंबर 2016 को तीन साल की अवधि के लिए लॉ फैकल्टी की डीन व प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्त हुई थी। 17 जून से वह अपनी सेवाएं समाप्त कर रही हैं। दो साल नौ महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लॉ फैकल्टी के हित में कई प्रयास किए, लेकिन विश्वविद्यालय अथॉरिटी से उन्हें कभी भी समर्थन नहीं मिला। उन मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जो नियमित तौर पर कक्षाओं में हाजिर रहे। वहीं, 31 फीसद हाजिरी वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने दिया गया। उन्हें ट्यूटोरियल कक्षाओं के अतिरिक्त हाजिरी के अंक दिए गए, जबकि ट्यूटोरियल कक्षाओं को आयोजित ही नहीं किया गया था। फर्जी रिकॉर्ड तैयार करते हुए ये अंक दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत पदोन्नति नहीं की गई। डीयू के उमंग भवन में शिक्षकों के लिए कई कक्ष नहीं खोले गए, जहां शिक्षक अपने बैग, किताबें, रजिस्टर रख सकते थे। उन्हें ऐसा कोई कक्ष नहीं दिया गया। शिक्षक वहां छात्रों से मिल सकते थे और शोध कार्य भी कर सकते थे। वहीं, सेक्शन ऑफिसर की सात महीने की सैलरी भी जारी नहीं की गई। लॉ फैकल्टी के डीन कार्यालय में रखे गए दो मेहनती पेशवरों की सैलरी भी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी गई, जिन्हें विज्ञप्ति एवं साक्षात्कार के जरिये रखा गया था। लॉ फैकल्टी की विभिन्न सिफारिशों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वीकृत नहीं किया। क्लीनिकल लीगल एजुकेशन विषय में लॉ फैकल्टी के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अनुभवी शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया गया।

इस्तीफे की यह भी वजह बताई : प्रो. वेद कुमारी ने फैकल्टी की एक सदस्य के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने त्यागपत्र में लिखा कि उनके अवैध कार्यों के कारण भी वह इस्तीफा दे रही हैं। फैकल्टी की सदस्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है।

कुलपति ने नहीं दिया जवाब : प्रो. वेद कुमारी के त्याग पत्र के मामले में डीयू के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी से उनका पक्ष जानने के लिए मैसेज व फोन किए गए, लेकिन उन्होंने मैसेज व फोन का कोई जवाब नहीं दिया।

एनएसयूआइ ने त्यागपत्र पर उठाए सवाल

एनएसयूआइ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने लॉ प्रो. वेद कुमारी के त्यागपत्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लॉ फैकल्टी की डीन को दो साल और नौ महीने बाद यह याद आया कि वह यह पद नहीं संभाल सकती हैं। दो साल में लॉ फैकल्टी का बुनियादी ढांचा खस्ता हो चुका है। छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। लाकड़ा ने कहा कि उनके और कैंपस लॉ सेंटर की प्रोफेसर इंचार्ज के बीच हुई नोकझोंक से छात्रों का भविष्य अंधकार की तरफ चला गया है।

सामने आई जानकारी

आरटीआइ से पता चला, तिहाड़ में कैदियों को लोकल के लिए एक रुपये तो एसटीडी कॉल के लिए देने पड़ते हैं दो रुपये

देश में सबसे महंगी है तिहाड़ की कॉल सुविधा

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली

लोकल व एसटीडी कॉल की अलग-अलग दरें अब गुजरे जमाने बात हो गई है, लेकिन देश की सबसे बड़ी जेल में आज भी कैदियों से लोकल व एसटीडी कॉल के लिए अलग-अलग दरें वसूल की जाती हैं। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि टेलीकॉम कंपनियों में भले ही कॉल रेट सस्ती करने को लेकर होड़ मची है, लेकिन तिहाड़ में कैदियों को लोकल के लिए एक रुपये तो वहीं एसटीडी कॉल के लिए दो रुपये देने पड़ते हैं। महंगे कॉल रेट के बाबत जेल प्रशासन का अपना अलग तर्क है। जब उनसे पूछा जाता है कि लोकल व एसटीडी कॉल के लिए अलग-अलग दरें क्यों तो वह इसका उत्तर देने से कतराने लगते हैं।

कैदी परिजनों से बात कर सकें इसके लिए मार्च 2010 में तिहाड़ जेल प्रशासन ने टेलीफोन सुविधा शुरू की थी। इस सुविधा को शुरू करने का उद्देश्य परिजनों को कैदियों से मुलाकात के लिए जेल आने व यहां से घर जाने में होने वाली असुविधा व समय की बर्बादी से बचाना था, लेकिन इस सुविधा के एवज में जेल प्रशासन कैदियों से मोटा शुल्क भी वसूल रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह शुल्क समय के साथ घटने के बजाय बढ़ रहा है। जब इस सुविधा की शुरुआत हुई थी तब लोकल कॉल के लिए 50 रुपये महीने व एसटीडी कॉल के लिए 100 रुपये महीने का शुल्क निर्धारित था। तब कैदी सप्ताह में एक बार पांच मिनट के लिए टेलीफोन पर परिजनों से बात कर सकते थे। वर्ष सितंबर 2010 में यह शुल्क बढ़ाकर लोकल कॉल के लिए सौ रुपये व एसटीडी कॉल के लिए 200 रुपये कर दिया गया। हालांकि बातचीत की अवधि भी बढ़ा दी गई। वर्ष 2016 में इस शुल्क को एक बार और बढ़ाया गया। अब लोकल कॉल के लिए 150 रुपये प्रति माह व एसटीडी कॉल के लिए 300 रुपये प्रति माह का शुल्क निर्धारित कर दिया गया। कादीपुर निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने इस बाबत सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए जेल प्रशासन से कॉल की दरों के बारे में पूछा। इस वर्ष अप्रैल में दिए गए अपने जवाब में जेल प्रशासन ने इन्हें बताया कि वर्तमान में 150 रुपये लोकल और 300 रुपये एसटीडी शुल्क कैदियों से प्रति महीने लिए जाते हैं। इस शुल्क के एवज में कैदियों को प्रतिदिन पांच मिनट टेलीफोन पर बात करने की सुविधा मिलती है। ऐसे कैदी जो हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद हैं उनके लिए यह सुविधा सप्ताह में केवल दो दिनों के लिए ही उपलब्ध है।

> सुरक्षा कारणों से जेल में टेलीफोन पर ही गई तमाम बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है, जिसके लिए टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को अलग से शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिस कारण कॉल रेट महंगे हो जाते हैं। जहां तक लोकल व एसटीडी कॉल के लिए अलग–अलग दरों का प्रश्न है तो मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगा।
> **–राजकुमार, अतिरिक्त महानिरीक्षक, तिहाड़ जेल प्रशासन**

झमाझम बारिश ने बदली फिजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मंगलवार अलसुबह हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली की फिजा ही बदल दी। बारिश की वजह से दिन भर गर्मी के तेवर नरम रहे। आंशिक रूप से बादल छाए रहे और तापमान भी सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह गर्मी से राहत ही रहेगी। बीच-बीच में बारिश का दौर भी चलता रहेगा।

मंगलवार तड़के तीन बजे के आसपास दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि बाद में मौसम साफ हो गया, लेकिन सूरज और बादलों के बीच आंखमिचौली का दौर तब भी दिन भर चलता रहा। बीच-बीच में हवा भी चलती रही। यही वजह रही कि सोमवार की तुलना में आंशिक वृद्धि के बावजूद मंगलवार को भी तापमान कम रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम 35.0 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से सात डिग्री कम 20.6 डिग्री सेल्सियस पर सिमटकर रह गया। रिज में न्यूनतम तापमान महज 19 डिग्री और आया नगर में 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की प्राप्ति रसीद दिखाने पर ही मिल जाएगा दाखिला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

डीयू में दाखिला

▶ **दाखिला प्रक्रिया खत्म होने के बाद कॉलेज मूल दस्तावेज दिखाने के लिए कहेंगे**

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को बड़ी राहत दी है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की प्राप्ति रसीद दिखाने पर भी उनका दाखिला हो जाएगा। दाखिला प्रक्रिया खत्म होने के बाद कॉलेज प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहेगा।

कई छात्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। वे डीयू प्रशासन से बार-बार पूछ रहे थे कि उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तैयार नहीं हुआ है तो क्या वे दाखिला पोर्टल पर इसकी प्राप्ति रसीद अपलोड कर सकते हैं। डीयू प्रशासन ने कहा था कि रसीद अपलोड कर सकते हैं। वहीं, अब डीयू प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सभी कटऑफ निकलने तक जिन छात्रों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनकर तैयार नहीं होता है तो भी वे प्राप्ति रसीद की फोटोकॉपी के जरिये प्रोविजनल तौर पर कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे।

डीयू के अकादमिक परिषद के सदस्य प्रोफेसर रसाल सिंह ने बताया कि कई प्रदेशों खासकर दिल्ली में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने में देरी की वजह से कई आवेदकों को प्रमाण पत्र नहीं मिल सके हैं इसलिए डीयू ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज दाखिला लेते समय ऐसे छात्रों से शपथ पत्र देने को कहेंगे। दाखिला प्रक्रिया जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो उसके एक हफ्ते बाद छात्रों से सभी मूल दस्तावेज मांगे जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। इसी समय छात्रों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बयान जारी कर कहा कि डीयू के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को अब आसानी से दाखिला मिलेगा।

5 लाख लीटर से अधिक पानी की खपत वाले रेलवे स्टेशनों और वर्कशॉप पर वाटर मीटर लगाए जाएंगे और ऑडिट कराया जाएगा। इसका मकसद पानी की बर्बादी को रोकना है।

विपक्षी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई

तैयारी ▶ एक राष्ट्र-एक चुनाव पर प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर हुई चर्चा

बिहार में बच्चों की मौत सहित जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने को लेकर हुई बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद के चालू सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को विपक्षी दलों के साथ मिलकर साझा रणनीति बनाई। एक तरफ जहां बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की होने वाली बैठक में रुख पर विचार हुआ वहीं बिहार में बच्चों की मौत सहित जनता से जुड़े दूसरे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने को लेकर चर्चा हुई है।

यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों के साथ हुई इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, एससीपी नेता सुप्रिया सुले, नेशनल कांफ्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला, भाकपा नेता डी.राजा, द्रमुक नेता कनीमोरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।

इससे पहले सोनिया गांधी के आवास पर प्रधानमंत्री की ओर से 19 जून को एक राष्ट्र-एक चुनाव के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि पार्टी ने अभी इसे लेकर अपना रुख रूख सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन सूत्रों की मानी जाए तो अधिकतर विपक्षी दलों की ओर से इसे अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया जाएगा। पहले भी कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध कर चुके हैं।

इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेने की जानकारी दी है।

सोनिया गांधी की फाइल फोटो।

मोदी के साथ पार्टी प्रमुखों की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण, नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के बाद अब तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के साथ राजनीतिक दलों के प्रमुखों की दिल्ली में बुधवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में भाग लेने से भी इन्कार कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी को मंगलवार को पत्र लिखकर सरकार को सलाह दी कि वह 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर 'जल्दबाजी' में फैसला लेने के बजाए इस पर एक श्वेत पत्र तैयार करे।

प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी दलों के प्रमुखों को 19 जून को बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जिनके लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य हैं। इस बैठक में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार, 2022 में आजादी के 75वें वर्ष के जश्न, महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष को मनाने समेत कई मामलों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 20 जून को सभी सांसद रात्रिभोज के समय बैठक करेंगे। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' जैसे संवेदनशील एवं गंभीर विषय पर इतने कम समय में जवाब देने से इस विषय के साथ न्याय नहीं होगा। इस विषय को संवैधानिक विशेषज्ञों, चुनावी विशेषज्ञों और पार्टी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श की जरूरत है।' 'मैं अनुरोध करूंगी कि इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाए, आप कृपया सभी सियासी दलों को इस विषय पर एक श्वेत पत्र भेजें जिसमें उनसे अपने विचार व्यक्त करने को कहा जाए। इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं, तभी हम इस अहम विषय पर ठोस सुझाव दे पाएंगे।' ममता ने पत्र में यह भी कहा, वह और उनका दल आजादी की 75 वर्ष पूरे होने और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष समारोहों में बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे, पर संसद की उत्पादकता में सुधार के तरीकों का मामला निचले सदन का है और संबंधित मंत्रालय को इससे निपटना चाहिए।

सत्र के दूसरे दिन संसद में गूंजे जय श्रीराम, अल्लाह हू अकबर के नारे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ भाजपा सांसदों ने लगाया जय श्रीराम का नारा, तो ओवैसी ने कहा अल्लाह हू अकबर

▶ सपा सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने बताया वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी

शपथ के दूसरे दिन लोकसभा में जय हिंद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्रीराम, अल्लाह हू अकबर और जय काली के नारे खूब गूंजे। भाजपा बेंच की तरफ से भारत माता की जय और जय श्रीराम की आवाज सुनाई देती रही। इसके जबाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह हू अकबर और तृणमूल मूल कांग्रेस के कई सांसदों ने जय काली का नारा लगाया। शपथ लेने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी ने आने वाले समय में सदन की कार्यवाही के दौरान होने वाले तीखी नोकझोंक का संकेत भी दे दिया।

वैसे तो शपथ लेने के दौरान नारेबाजी की शुरुआत भोपाल से सांसद बनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भारत माता की जय का नारा लगाकर दिया। लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह मंगलवार को पूरे दिन जारी रहा। शपथ लेने के लिए जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम पुकारा गया तो भाजपा बेंच से जय श्रीराम के नारे लगने लगे। इससे चिढ़े ओवैसी ने शपथ लेने के बाद 'जय भीम, जय मीम, अल्लाह हू अकबर, जय हिंद' का नारा लगाया। बाद में उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि मुझे देखने के बाद उन्हें ऐसी चीजें याद आती हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि उन्हें संविधान और मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत भी याद आती रहेंगी। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शपथग्रहण के बाद विवादस्पद बयान देते हुए कहा कि वे वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि यह इस्लाम के खिलाफ है। भाजपा सांसदों ने इसका तीखा प्रतिवाद किया। ध्यान रहे कि सत्र की समाप्ति के समय वंदे मातरम बजाया जाता है। खासकर चुनाव के दौरान तीखी लड़ाई वाले राज्यों के सांसदों में ज्यादा नारेबाजी देखी गई। चुनावी हिंसा से ग्रस्त पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसदों की ओर से भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगे, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जय काली का सहारा लिया। भाजपा की सहयोगी अन्नाद्रमुक को कड़े मुकाबले में अधिकांश सीटों पर पराजित करने में सफल रही द्रमुक के सांसदों की ओर से जय आंबेडकर, जय पेरियार जैसे नारे लगाते रहे।

हैदराबाद लोकसभा सीट से निर्वाचित असदुद्दीन ओवैसी ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। प्रेट्र

दूसरे दिन सोनिया, मुलायम एवं अन्य सदस्यों ने ली शपथ

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव एवं अन्य ने दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेता ने हिंदी में शपथ ली। विपक्षी बेंच की तरफ से उनके बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोबाइल से इस घड़ी को कैद करने में जुटे थे। कांग्रेस की तरफ से मेजें थपथपाकर स्वागत किया गया तो भजपा की ओर से भी सोनिया गांधी के हिंदी में शपथ लेने का स्वागत किया गया। उनके तुरंत बाद ही उनकी देवरानी और भाजपा सांसद मेनका गांधी को शपथ दिलाई गई। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। 79 वर्षीय बीमार मुलायम सिंह यादव अपने बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सदन में पहुंचे। उन्हें ह्वील चेयर पर लाया गया। उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें अपनी सीट से ही शपथ लेने की इजाजत दी गई। आजमगढ़ से जीतकर आए अखिलेश ने भी शपथ ली। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए राजग की ओर से नामित भाजपा सांसद ओम बिरला जैसे ही सदन में पहुंचे उनका जोरदार स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने भी शपथ ली। मथुरा से भाजपा सांसद हेमामालिनी शपथ लेने के बाद ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध अभिवादन 'राधे-राधे' करना नहीं भूलीं

गुजरात में रास चुनाव एक साथ कराने की मांग पर सुनवाई आज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ गुजरात कांग्रेस के नेता परेशभाई धणानी ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है याचिका

गुजरात में रिक्त हुई राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। गुजरात कांग्रेस के नेता परेशभाई धणानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दो सीटों के लिए जारी चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी है। उनके द्वारा अमित शाह और स्मृति इरानी द्वारा खाली की गई सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है। चुनाव आयोग से 15 जून को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गुजरात से राज्यसभा में खाली हुई दो सीटों पर पांच जुलाई को चुनाव होंगे।

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश कालीन पीठ के सामने वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने इसपर बुधवार को सुनवाई करने की हामी भरी।

कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धणानी ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग को दोनों उपचुनाव एक साथ कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। असल में गुजरात विधानसभा में भाजपा के100 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 75, वहीं सात सीटें इस समय खाली है। अगर दोनों सीटों को भरने के लिए एक साथ चुनाव हुए और विधायकों ने सिर्फ एक बार में वोट दिया तो कांग्रेस के पास एक सीट जीतने का मौका होगा। लेकिन अगर दोनों सीटों के लिए अलग-अलग वोटिंग हुई तो भाजपा दोनों सीटें जीत सकती है क्योंकि विधानसभा में वह बहुमत में है। संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए।

बता दें कि एक ही बैलट पर चुनाव से एक ही वोट डाला जाएगा। इस स्थिति में कांग्रेस एक सीट आसानी से निकाल लेगी क्योंकि उसके अकेले के पास 75 विधायक हैं। लेकिन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, विधायक अलग-अलग वोट करेंगे। ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा। इस तरह भाजपा के विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वे दो बार वोट कर दोनों उम्मीदवारों को जिता सकते हैं।

हर किसी के सुख-दुख के साथी का नाम है 'ओम बिरला'

मनीष गोधा, जयपुर

▶ क्षेत्र के सभी लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं उनके दरवाजे

▶ राजस्थान के दूसरे ऐसे नेता होंगे, जो पहुंचेंगे इतने बड़े संवैधानिक पद तक

देशभर में कोचिंग हब के नाम से पहचाने जाने वाले राजस्थान के कोटा शहर के साथ अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। यहां के सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कोटा में तो जश्न का माहौल है ही, प्रदेश के तौर पर राजस्थान के लिए भी यह एक बड़ी उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति रहे भैरोसिंह शेखावत के बाद ओम बिरला राजस्थान के दूसरे ऐसे नेता होंगे, जो इतने बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचेंगे। ओम बिरला के व्यक्तित्व की बात करें तो वह इतने सहज और सरल हैं कि सबके लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वह अपने क्षेत्र के लोगों के हर सुख-दुख में शामिल होते हैं। लोगों से लगाव और सादगी ही है, जिसके जरिये वह लोगों के दिलों पर राज करते हैं।

कोटा में ओम जी भाईसाब के नाम से पहचाने जाने वाले ओम बिरला तीन बार विधायक रह चुके हैं और अब दूसरी बार सांसद बने हैं। वर्ष 2003 में पहली बार उन्होंने कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। वर्ष 2013 में विधायक चुने जाने के बाद भी पार्टी ने 2014 में उन्हें कोटा-बूंदी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा दिया और वह सांसद बन गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनारायण मीणा को दो लाख 79 हजार वोटों से हरा दिया। राजस्थान की राजनीति में वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में उनके सबसे विश्वस्त लोगों में गिने जाते थे।

ओम बिरला भाजपा में माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के विशेषज्ञ माने जाते हैं। पार्टी के चुनाव प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बिरला को इसका प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाता है।

उनके पिता श्रीकृष्ण बिरला संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रहे हैं और इसीलिए ओम बिरला का भी शुरू से ही संघ और भाजपा से जुड़ाव रहा है। पांच भाइयों में ओम चौथे नंबर के हैं।

नई दिल्ली में मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए राजग प्रत्याशी बने ओम बिरला का मुंह मीठा कराते परिजन। वह राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद हैं। प्रेट्र

दो बार के सांसद बिरला पहले नेता नहीं हैं जो होंगे लोकसभाध्यक्ष

आमतौर पर माना जाता है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को चलाने के लिए काफी अनुभवी अध्यक्ष की जरूरत होती है। इस अहम जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऐसे राजनेता की दरकार होती है जो विधायी कार्यों, नियमों और कानूनों में सिद्धहस्त होता है। कोई नेता इसमें तभी पारंगत माना जाता है जब वह कई बार संसद के किसी सदन का सदस्य बन चुका होता है। 17वीं लोकसभा में राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर होंगे। अब तक वे सिर्फ दो बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोई कम संसदीय अनुभव वाले किसी राजनेता को इस पद पर बैठाया गया हो। आइए, जानें पूर्व के लोकसभाध्यक्षों के संसदीय अनुभवों को।

लोकसभाध्यक्ष	वर्ष	संसदीय अनुभव
जीवी मालवंकर	1952	एक बार
एमए अयंगर	1956	एक बार
सरदार हुकुम सिंह	1962	तीन बार
नीलम संजीव रेड्डी	1967	एक बार
जीएस ढिल्लन	1967	एक बार
बलिराम भगत	1977	चार बार
केएस हेगड़े	1977	एक बार
बलराम जाखड़	1980	दो बार
रवि रॉय	1989	एक बार
शिवराज पाटिल	1991	पांच बार
पीए संगमा	1996	तीन बार
सीएम बालयोगी	1996	एक बार
मनोहर जोशी	2002	एक बार
मीरा कुमार	2009	तीसरी बार
सुमित्रा महाजन	2014	सातवीं बार

(लोकसभाध्यक्षों का संसदीय कार्यकाल उनके पद पर बनने से पहले का है।)

डांस रियलिटी शो में बच्चों को अनुचित तरीके से दिखाने से बचें टीवी चैनल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनलों को डांस रियलिटी शो और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में बच्चों को अभद्र और अनुचित तरीके से दिखाने से बचने की सलाह दी है। दरअसल, मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कई डांस आधारित रियलिटी टीवी शो में छोटे बच्चों की नृत्य की ऐसी मुद्राएं दिखाई जाती हैं जो मूलरूप से फिल्मों में वयस्क कलाकारों द्वारा की जाती हैं। मंत्रालय ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण से बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि निजी टीवी चैनलों से उम्मीद की जाती है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता में निहित प्रावधानों का पालन करें। नियमों के मुताबिक बच्चों को बदनाम करने वाले कार्यक्रमों को टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए बने कार्यक्रमों में बुरी भाषा या हिंसा के दृश्य नहीं होने चाहिए।

नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस मौके पर नड्डा ने अपना पदभार संभाल लिया। फोटो सौजन्य : भाजपा

शांत क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों को फिर मुफ्त राशन मिलेगा

▶ केंद्र सरकार ने 2017 में वापस ले ली थी यह सुविधा, रोजाना 96 रुपये मिलता था राशन भत्ता

▶ अब सीएसडी से रियायती दर पर 12 लाख से ज्यादा महंगी कार नहीं मिलेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : शांत क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों को फिर से मुफ्त राशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सरकार सातवें वेतन आयोग के बाद इन क्षेत्रों में तैनात सैन्य अधिकरियों का राशन बंद कर इसके एवज में प्रतिदिन राशन भत्ता के तौर पर 96 रुपये दे रही थी। इसका काफी विरोध हो रहा था।

सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद 2017 में मुफ्त राशन की सुविधा खत्म कर दी थी। शांत क्षेत्र में जवानों और जूनियर कमिशंड ऑफिसर (जेसीओ) रैंक के अधिकारियों को ही मुफ्त राशन मिल रहा था। अधिकारियों को 96 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशन भत्ता दिया जा रहा था। हालांकि, फील्ड एरिया में तैनात अधिकारियों और जवानों को मुफ्त राशन की सुविधा जारी थी।

मुफ्त राशन सुविधा वापस लेने के सरकार के फैसले की बहुत आलोचना हो रही थी। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने इसे दोबारा बहाल करने का फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब शांत क्षेत्रों समेत सशस्त्र बलों के सभी अधिकारियों को मुफ्त राशन मिलेगा। मुफ्त राशन देने की व्यवस्था बहाल करने से सैनिक राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं, पिछले महीने सेना के क्वार्टर जनरल ब्रांच की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सेना में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी सीएसडी (कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट) से रियायती मूल्य पर 12 लाख से ज्यादा कीमत की कार नहीं खरीद सकेंगे। सीएसडी के जरिए 2,500 सीसी क्षमता और 12 लाख रुपये कीमत तक की कार ही उपलब्ध होगी।

'लोस में 350 से ज्यादा सांसद, सरकार कराए राम मंदिर का निर्माण'

मुंबई, एएनआइ : शिवसेना ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान राम का निर्वासन खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में मंगलवार को इस मुद्दे पर विचार किया है। इससे पहले 16 जून को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य और पार्टी के 18 सांसदों के साथ अयोध्या में अस्थायी मंदिर में भगवान का दर्शन करने पहुंचे थे।

सामना के संपादकीय में कहा गया है, 'उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमसे एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे। महंत नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी में मौर्य ने कहा था राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए दो विकल्प उपलब्ध है। मुस्लिम पक्ष से बातचीत और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यदि ये दोनों विकल्प विफल रहते हैं तो अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाया जा सकता है।'

पार्टी ने कहा, 'बातचीत के लिए सभी विकल्प विफल हो गए हैं। इसलिए 350 सांसदों का बहुमत का जनादेश राम मंदिर के लिए है। मंदिर निर्माण की दिशा में सरकार बढ़े। अयोध्या से राम के निर्वासन का अंत हो।' सामना ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम उन लोगों के खिलाफ है जो राम मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। वे तबाह हो गए हैं।

राम मंदिर निर्माण पर चर्चा करने उद्धव के पास पहुंचे सुब्रमण्यम : भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मंगलवार को उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके मातोश्री निवास पर पहुंचे। दोनों नेता अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

कह के रहेंगे माधव जोशी

बदलाव

अब जलशक्ति मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय, भाजपा ने पानी से संबंधित सभी विषयों को एक साथ लाकर अलग मंत्रालय बनाने का किया था वादा

पर्यावरण मंत्रालय से हटा नदियों की सफाई का काम

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय से नदियों की सफाई का काम छीनकर जलशक्ति मंत्रालय को सौंप दिया है। अब तक जलशक्ति मंत्रालय के पास सिर्फ गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई का ही जिम्मा था लेकिन अब वह शेष नदियों के प्रदूषण को दूर करने का काम भी देखेगा।

कैबिनेट सचिवालय ने सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का नाम बदलकर जलशक्ति मंत्रालय करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का विलय भी जलशक्ति मंत्रालय में कर दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय में अब दो विभाग होंगे। पहला- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और दूसरा पेयजल और स्वच्छता विभाग। खास बात यह है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर अन्य नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और नदियों के प्रदूषण को दूर करने का जिम्मा अभी तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास था जिसे अब जलशक्ति मंत्रालय के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी अब जलशक्ति मंत्रालय का हिस्सा होगा जो अब तक पर्यावरण मंत्रालय के पास था।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में पानी से संबंधित सभी विषयों को एक जगह लाकर जलशक्ति मंत्रालय के गठन का वादा किया था। पार्टी ने कहा था, '' पानी बेहद महत्वपूर्ण संसाधन है लेकिन इसका प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर भी कई विभागों के माध्यम से होता है। हम जल के लिए नया मंत्रालय बनाएंगे। इस मंत्रालय का उद्देश्य जल प्रबंधन के मसले पर बेहतर सुनिश्चित प्रयास करना और इसे नई दिशा देना होगा।'' हालांकि माइक्रो इरीगेशन और वाटर शेड मैनेजमेंट जैसे जल से संबंधित विषय अब भी जलशक्ति मंत्रालय के दायरे से बाहर हैं। इसी तरह झीलों के संरक्षण से संबंधित विषय भी अभी पर्यावरण मंत्रालय के पास ही रहेगा। हाल में जल मंत्रियों की बैठक में भी केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्यों को उनके स्तर पर जल से संबंधित सभी विषयों को एक जगह लाने का आग्रह किया था।

गंगा नवंबर तक बनारस में होंगी सीवेज मुक्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा है कि नवंबर तक गंगा बनारस में सीवेज मुक्त हो जाएंगी। गंगा में मिलने वाले 23 नालों में से 20 बंद हो चुके हैं। नवंबर तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पहले चरण में बनारस में गंगा 26 घाटों का सुंदरीकरण हो रहा है। बीएचयू के साथ मिलकर गंगा मित्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें 66 लाख रुपये खर्च होंगे। गंगोत्री से गंगा सागर तक निर्मलीकरण हो रहा है। अब तक 1063 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उत्तराखंड और झारखंड में प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने को हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 87 में से 50 कार्य पूरे हो चुके हैं। दो साल में सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके बाद उद्गम से बंगाल की खाड़ी तक गंगा में एक बूंद भी दूषित पानी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, गंगा की निर्मलता के लिए अविरल प्रवाह जरूरी है। इसके लिए गंगा में ईको फ्लो बनाए रखना होगा। ऐसे में गंगा की सहायक नदियों का निर्मलीकरण भी किया जा रहा है। इसमें बनारस की असि भी शामिल है। फिलहाल, इसकी सफाई नगर निगम निजी संस्था के साथ मिलकर कर रहा है।

80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है कांग्रेस ने असम में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में। अभी यहां कांग्रेस के 25 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 61 और उसके सहयोगी असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के क्रमश: 14 और 12 सदस्य हैं। राज्य में विस की कुल 126 सीटें हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 19 जून 2019

हरियाणा में सैलजा और हुड्डा की जोड़ी को आगे लाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- दलितों को जोड़े रखने के लिए सैलजा को सौंपी जा सकती है हरियाणा कांग्रेस की कमान
- भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता संभव, तीन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे

हरियाणा के कांग्रेस दिग्गजों की गुटबाजी खत्म करने को हाईकमान नया प्रयोग करने की तैयारी में है। दलितों व जाटों को साधने की मंशा से प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा को संगठन की बागडोर सौंपी जा सकती है। कांग्रेस हाईकमान सभी धड़ों को एक डोर में बांधने की मंशा से तीन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर भी गंभीर है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वदेश लौटते ही प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने उनके साथ हरियाणा के मामलों पर चर्चा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी को पार्टी की गुटबाजी से वाकिफ करा दिया है। हाईकमान को बताया गया है कि यदि प्रदेश के प्रमुख पार्टी नेताओं का विवाद इसी तरह बढ़ता रहा तो लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की फजीहत होने से नहीं रोकी जा सकेगी।

हरियाणा चूंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा प्रदेश है, इसलिए यहां की राजनीतिक गतिविधियों का दिल्ली की राजनीति का पूरा असर रहता है। हुड्डा समर्थकों ने हाईकमान को दो टूक कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्हें अशोक तंवर स्वीकार नहीं है। तंवर दलित हैं। ऐसे में हाईकमान को लगता है कि तंवर को हटाने के बाद राज्य के दलित कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं। इसलिए बीच का रास्ता निकालने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपने का पासा फेंका गया है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा जागरण आर्काइव

कुमारी सैलजा जागरण आर्काइव

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के राजनीतिक रिश्ते अब पहले से काफी मधुर हैं। हुड्डा को राजनीति में बड़ा ब्रेक दिलाने में कुमारी सैलजा का कहीं न कहीं योगदान रहा है। सैलजा भी हुड्डा की काफी कद्र करती हैं। हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। इससे जाटों को खुश करने में मदद मिलेगी और हुड्डा समर्थकों की मायूसी भी दूर हो सकेगी।

इन नामों को भी आगे लाने के संकेत : हुड्डा कैबिनेट में अहम मंत्रालय चला चुके लालू यादव के समधि कैप्टन अजय सिंह यादव का दक्षिण हरियाणा में अच्छा प्रभाव है। उन्हें कार्यकारी प्रधान बनाया जा सकता है। युवाओं को साधने की मंशा से रोहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कार्यकारी प्रधान बनाए जाने की योजना है। गैर जाट नेता कुलदीप बिश्नोई और राहुल गांधी के एक कामन दोस्त की वजह से दो दिन पहले ही उनकी मीटिंग हुई है। बांगर बेल्ट को साधने के लिए कुलदीप बिश्नोई को तीसरा कार्यकारी प्रधान बनाने की योजना पर मंथन चल रहा है।

तंवर के लिए अलग तैयारी : मौजूदा अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है। कांग्रेस विधायक दल की मौजूदा नेता किरण चौधरी अपने ढंग की राजनीति करती हैं। उनकी हाईकमान में मजबूत पकड़ हैं। लिहाजा उन्हें भी एडजेस्ट करने के तरीके पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला की गिनती राहुल गांधी की कोर टीम में होती है। उनके जरिये राहुल गांधी जहां हरियाणा के मामलों पर निगाह रखेंगे, वहीं राष्ट्रीय राजनीति में सुरजेवाला का हस्तक्षेप पहले से अधिक बढ़ा दिया जाएगा।

रोहतक में तैयार होगी भाजपा के मिशन 75 की रणनीति

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के बाद अब भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। राज्य में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने को भाजपा ने रोहतक को चुना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के बाद भाजपा अब 29 जून को रोहतक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेगी। यह मिशन 75 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। प्रांतीय योग दिवस समारोह में 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसी दिन शाह रोहतक में पार्टी के प्रमुख नेताओं से संगठन और चुनाव पर औपचारिक चर्चा कर सकते हैं। शाह के गुरु मंत्र के बाद 29 जून को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी।

भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रांतीय प्रभारी डॉ. अनिल जैन, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और प्रांतीय संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की यह आखिरी बैठक होगी। इस बैठक में सभी विधायक, मंत्री, सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रधान और महामंत्री, प्रदेश सदस्य, बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैनों को भाग लेने के लिए कहा गया है।

उत्तर प्रदेश में सभी निजी विवि के लिए अब एक अधिनियम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक छतरी के नीचे लाकर उनकी स्थापना और संचालन में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकार ने एकल अधिनियम (अम्ब्रेला एक्ट) बनाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2019 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। सरकार इस अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश करेगी। प्रदेश में अभी 27 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। ये विश्वविद्यालय अलग-अलग अधिनियमों के तहत स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में अलग-अलग प्रावधान हैं।

राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय सभी निजी विश्वविद्यालयों पर लागू करने, उनसे सूचना और दस्तावेज हासिल करने, उनमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े मानकों को लागू करने और उनकी निगरानी के लिए अभी कोई प्रक्रिया तय नहीं है। लिहाजा सभी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन में एकरूपता लाने के लिए सरकार एकल अधिनियम की स्थापना की खातिर यह अध्यादेश लाई है। पहले से संचालित निजी विश्वविद्यालयों को एक साल के अंदर परिनियमों को अधिसूचित करने की छूट दी गई है।

सार्वजनिक होगी दाखिले की प्रक्रिया और शुल्क

अध्यादेश के तहत निजी विश्वविद्यालयों को छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया, प्रवेश का आरंभ व अंतिम तारीख तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को सार्वजनिक करना होगा। उन्हें न्यूनतम 75 प्रतिशत शिक्षकों की नियमित नियुक्ति विभिन्न संकायों में करनी होगी।

समान एकेडमिक कैलेंडर

सभी निजी विश्वविद्यालयों में समान रूप से एक एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा, ताकि प्रवेश और परीक्षाएं एक समय पर हों और परीक्षा परिणाम भी एक ही समय पर घोषित हों। मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रमों का एकेडमिक कैलेंडर नियामक संस्थाओं के अनुसार होगा।

दुर्बल वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसद सीटें

निजी विश्वविद्यालयों को दुर्बल वर्ग के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में 10 फीसद सीटों पर 50 प्रतिशत शुल्क के साथ प्रवेश देना होगा। ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें उपलब्ध सीटों का प्रतिशत एक से कम है, वहां ऐसे सभी कोर्स में समेकित रूप से चक्रानुक्रम में दुर्बल वर्ग के छात्रों को प्रवेश देना होगा।

पश्चिम बंगाल में एक और नपा पर भाजपा का कब्जा

ममता को झटका ▸ एक विधायक के साथ तृणमूल कांग्रेस के 12 पार्षद भाजपा में हुए शामिल

सोमवार को भी टीएमसी के एक विधायक और 12 पार्षदों ने थामा था भाजपा का हाथ

जागरण संवाददाता, कोलकाता

पश्चिम बंगाल में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी तृणमूल के एक विधायक एवं 12 पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तर 24 परगना जिलांतर्गत बनगांव उत्तर विधानसभा सीट के विधायक विश्वजीत दास ने दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बनगांव नगरपालिका के 12 तृणमूल पार्षदों ने भी भाजपा का झंडा थाम लिया।

इन पार्षदों के आने से अब बनगांव नगरपालिका पर भाजपा का कब्जा हो गया है। इस पालिका में कुल 22 पार्षद हैं, जिनमें से 12 भाजपा के हो गए हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रसेनजीत घोष भी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुकुल रॉय ने तृणमूल विधायक, पार्षद एवं कांग्रेस प्रवक्ता को भाजपा की सदस्यता दिलाई।

तृणमूल कांग्रेस विधायक विश्वजीत दास और 12 पार्षदों ने मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। एएनआइ

मुकुल रॉय बोले-पूरी फिल्म अभी बाकी : सोमवार को नोआपाड़ा के विधायक सुनील सिंह गारुलिया नगरपालिका के 12 पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सात चरणों में तृणमूल के लोग भाजपा में शामिल होंगे। अभी यह प्रथम चरण चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बंगाल में अराजकता एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार के कारण आज लोग भाजपा में आस्था जता रहे हैं। मुकुल रॉय ने कहा कि यह तो अभी तो यह ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है।

तृणमूल का कचरा बटोर रही है भाजपा : ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेताओं व जनप्रतिनिधियों का भाजपा से जुड़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच तृणमूल प्रमुख व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य के भर के नगर निकायों को वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की और कहा कि मुझे पार्टी में चोरों की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचारी व बागी चोर को लेकर भाजपा तृणमूल का कचरा बटोर रही है। कोलकाता में हुई बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कमजोर पार्टी नहीं है। मुझे परवाह नहीं है अगर 15-20 पार्षद पैसा लेकर पार्टी छोड़ते हैं। यदि कोई विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो वह छोड़ सकते है, ताकि हम विकास कार्यों को सुचारू रख सकें। हम अपनी पार्टी में चोर नहीं चाहते हैं। कोई एक पार्टी छोड़ता है तो मैं 500 कार्यकर्ता तैयार कर लूंगी।

चोरी कर दल बदलने से नहीं मिलेगी रिहाई : पार्षदों को आगाह करते हुए ममता ने कहा कि चोरी कर पकड़ में आने से ही पार्षद पार्टी छोड़ दूसरे दल में चले जा रहे हैं। बैठक के दौरान सीएम ने कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की अलग जांच होनी चाहिए और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल रामधनु पार्टी नहीं है कि जिसकी जो मर्जी वो वैसा करे। कई इलाके में ठीक से काम नहीं हुआ है, काम की जिम्मेदारी पार्षदों की है, पार्षद यदि ठीक से काम नहीं करते तो इससे पार्टी की बदनामी होती है।

ममता बनर्जी जागरण

कहा, पार्टी में नहीं चाहिए चोर और भ्रष्ट नेता-कार्यकर्ता

उन्होंने यह भी कहा कि मुझे सब पता है कि कैसे सरकारी संपत्ति को कई लोगों ने अपने नाम किया है, लेकिन सबकी जांच होगी और किसी को छूट नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी ने अपने पार्षदों को निर्देश दिया कि केवल प्रमोटिंग के काम पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा इलाके के विकास के लिए लोगों के साथ मिल कर काम करना होगा।

पश्चिम बंगाल में एक और भाजपा कार्यकर्ता की हत्या

जासं, कूचबिहार : बंगाल के कूचबिहार में एक और भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। मृतक की शिनाख्त आनंद पाल (30) के रूप में की गई है। शव के गले में धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। शरीर पर भी चोट के निशान पाए गए। घटनास्थल से एक बाइक बरामद हुई है। मृतक के बड़े भाई गोविंद पाल ने कहा कि उनके छोटे भाई पहले तृणमूल के कार्यकर्ता थे, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि, तृणमूल मृतक को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बता रही है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा रही हैं। कूचबिहार जिला भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव एनामुल हक ने कहा कि सोमवार रात को मोहल्ले में पिकनिक का आयोजन किया गया था। पिकनिक से आनंद और घर नहीं लौटा। उसी रात को उसकी हत्या कर दी गई होगी। मंगलवार सुबह आनंद के घर से तीन किमी दूर एक तालाब से उसका शव बरामद किया गया। उत्तर बंगाल विकास मंत्री तथा कूचबिहार जिला तृणमूल के पूर्व अध्यक्ष रवींद्रनाथ घोष ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी के कार्यकर्ता आनंद पाल की हत्या कर दी है।

कर्नाटक के बागी विधायक रोशन बेग को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित किया

बेंगलुरु, एएनआइ : कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक रोशन बेग को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह फैसला उस मांग के बाद आया है, जिसमें आइएमए पोंजी स्कीम के मुख्य आरोपित मुहम्मद मंसूर खान के साथ बेग के कथित संबंधों को देखते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव से की गई थी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए विधायक रोशन बेग के खिलाफ कार्रवाई के लिए कर्नाटक कांग्रेस द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।' पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष से वित्तीय धोखाधड़ी मामले में मंसूर खान की मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। बता दें कि आइएमए ज्वेल्स के संस्थापक खान ने आरोप लगाया था कि बेग ने उनसे 400 करोड़ रुपये लिए थे, जिसे उन्होंने नहीं लौटाया।

अधीर रंजन होंगे लोस में कांग्रेस के नेता

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल से सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता पद के लिए नामित किया गया है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह लेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के यह पद अस्वीकार करने के बाद यह जिम्मेदारी चौधरी को सौंपी गई है।

52 सांसदों वाली कांग्रेस का नेतृत्व लोकसभा में अधीर रंजन करेंगे। इस पद के लिए मनीष तिवारी, शशि थरूर और कोडिकुन्निल सुरेश के नामों की भी चर्चा हुई थी, लेकिन अंततः चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर से पांचवीं बार सांसद चौधरी का नामांकन कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई बैठक में हुआ। वह 1999 से जीतते आ रहे हैं। उन्हें जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। अपनी नियुक्ति पर चौधरी ने पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह लोकसभा में वह बढ़-चढ़ कर पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

नई दिल्ली में मंगलवार को संसद भवन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की अगुआई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के साथ सोनिया गांधी। द्रमुक सांसद कनिमोरी और राकांपा नेता सुप्रिया सुले भी इस मौके पर मौजूद रहीं। प्रेट्र

कांग्रेस को नहीं मिला विपक्ष के नेता का पद : मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास केवल 52 सांसद होने के नाते उसे लोकसभा में 'विपक्ष के नेता' का पद नहीं मिला है। पार्टी को इस पद के लिए कम से कम 55 सीटों की दरकार थी जोकि लोकसभा की कुल 545 सीटों का दस फीसद है। पश्चिम बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी को फाइटर माना जाता है। उन्होंने राज्य में तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी।

विपरीत परिस्थितियों में कभी 'अधीर' नहीं हुए रंजन

राजीव कुमार झा, कोलकाता

- कभी कांग्रेस नेता के प्रभाव को खत्म करने के लिए ममता ने भी झोंक दी थी पूरी ताकत
- पीएम मोदी ने भी पीठ थपथपा कर अधीर को कहा था फाइटर, 1999 से बेहरामपुर से हैं सांसद

पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर से पांचवीं बार सांसद चुने गए अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को अधीर को लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित किया। अधीर के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो उनकी छवि एक फायर ब्रांड नेता की है। वह जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। 1999 से लगातार पांचवीं बार उन्होंने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर सीट से जीत दर्ज की है। उनकी राह कभी आसान नहीं रहीं। बंगाल में कांग्रेस की लगातार खिसकती जमीन व ममता बनर्जी की कठिन चुनौती के बावजूद अधीर अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। 17वीं लोकसभा के प्रथम सत्र से पहले रविवार को अधीर रंजन चौधरी की खुद प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। सर्वदलीय बैठक के दौरान सबके सामने पीएम ने अधीर को फाइटर यानी योद्धा बताया था।

ममता के धुर विरोधी हैं अधीर : 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले में अधीर के प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सत्ता के प्रभाव में ममता ने एक-एक कर लगातार अधीर के कई करीबियों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया। हमेशा से कांग्रेस व अधीर का गढ़ रहे मुर्शिदाबाद में उन्होंने लगातार तृणमूल के विस्तार पर जोर दिया। अधीर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते उन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायकों को भी तोड़कर अपने साथ मिलाया। खासकर मुर्शिदाबाद से जीतकर आए उनके करीबी विधायकों को तोड़कर उन्होंने अधीर को लगातार कमजोर करने की कोशिश की।

किसी बड़े नेता ने नहीं किया प्रचार : पिछले साल कांग्रेस ने अधीर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और पार्टी की राज्य इकाई में भी वह अलग-थलग पड़े थे। इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो अधीर बंगाल से एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जिनके लिए न तो राहुल गांधी सहित कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने चुनाव प्रचार किया और ना ही प्रदेश नेतृत्व का उन्हें सहयोग मिला। उन्हें हराने के लिए ममता ने अधीर के ही पूर्व सहयोगी रहे अपूर्व सरकार को मैदान में उतारा था और खुद वहां जाकर जमकर प्रचार किया था। लेकिन, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अधीर अकेले योद्धा की तरह मैदान में ममता को न सिर्फ ललकारते रहे बल्कि गढ़ बचाने में भी कामयाब रहे।

पार्टी लाइन से अलग जाकर रखते हैं अपनी बात : जब भी मौका मिलता है वह ममता के खिलाफ बोलने से नहीं हिचकते। यहां तक कि कई बार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भी ममता की आलोचना कर चुके हैं। पिछले साल एनआरसी के मुद्दे पर जब पूरा विपक्ष एकजुट था और ममता इसका विरोध कर रही थी तब अधीर ने उन्हें अवसरवादी नेता और आदमखोर तक बता दिया था। अधीर ने कहा था कि 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठियों को समस्या बताने वाली ममता राजनीतिक फायदे के लिए एनआरसी का विरोध कर रही हैं। इसके बाद कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के मुद्दे पर भी अधीर ने पार्टी लाइन से अलग जाते हुए ममता के कदम को देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा करार दिया था। इतना ही नहीं उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग कर दी थी। वहीं, चिटफंड घोटाले को लेकर भी अधीर हमेशा ममता पर निशाना साधते रहे हैं।

बदला समय

चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन के दौर से गुजर रहे पूर्व सांसद, 1974 में पहली बार 26 साल की उम्र में जबलपुर सीट से जीतकर पहुंचे थे संसद

मझधार में नजर आ रहे शरद के सियासी सिद्धांत

अरविंद शर्मा, पटना

करीब पांच दशकों से देश की राजनीति में सक्रिय शरद यादव की सियासत अब सिमटती नजर आ रही है। राजद के टिकट पर बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़कर हारने के बाद शरद यादव भी तेजस्वी यादव की तरह आत्ममंथन कर रहे हैं। उनके करीबी बताते हैं कि शरद दिल्ली में हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों से परहेज कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी विधायक भोला यादव की बेटी की शादी में 10 जून को दिल्ली में दिखे जरूर थे, लेकिन अगले ही दिन लालू के जन्मदिन की पार्टी से दूर रहे। सोशल मीडिया से भी परहेज कर रखा है।

1974 में पहली बार 26 साल की उम्र में जबलपुर से सांसद बने और अभी तक कई सियासी बदलावों के मुख्य किरदार रहे शरद के सामने पर्दे के पीछे रहने की मजबूरी को समझा जा सकता है। जिस लालू प्रसाद को उन्होंने अपने प्रताप के जरिये 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बनवाया था और बाद में मधेपुरा से संसदीय चुनाव में हराकर सियासी सबक भी दिया था, अबकी उसी लालू की सरपरस्ती में चुनाव लड़ना पड़ा। विडंबना यह कि कामयाबी तब नहीं मिली। अपनी नई पार्टी और मुट्ठी भर सहयोगियों को छोड़कर राजद में आए शरद के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अब उन्हें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। हालांकि, लालू प्रसाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी बने रहेंगे, लेकिन जेल में रहने के कारण पार्टी के सारे फरमान 30 साल के तेजस्वी यादव के जरिये ही सुनाए जाएंगे। यह सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि 72 साल के स्वाभिमानी शरद पर तब कैसा गुजरेगा जब उनकी मौजूदगी वाले मंचों के मुख्य अतिथि तेजस्वी होंगे।

शरद यादव जागरण आर्काइव

शरद का कद राष्ट्रीय, तेजस्वी सीएम पद के प्रत्याशी : शरद के पुराने साथी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अर्जुन राय ऐसी स्थिति से इन्कार करते हैं। उनके मुताबिक शरद का कद राष्ट्रीय है और तेजस्वी बिहार के सीएम पद के प्रत्याशी हैं। राजद के अध्यक्ष लालू रहेंगे, जिनके साथ शरद पहले भी काम कर चुके हैं। गुरेज-परहेज जैसी कोई बात नहीं होगी। अर्जुन यह भी जोड़ते हैं कि शरद सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। नुकसान की परवाह नहीं करते। संविधान के रास्ते से अलग नहीं जाते हैं।

नहीं डाल पाए अपनी पार्टी में जान : जाहिर है कि शरद की इसी खासियत ने उन्हें आज सियासत के चौराहे पर खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के रास्ते से अलग होने के बाद अपने समर्थकों को साथ लेकर उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल (लोजद) नाम की नई पार्टी जरूर बनाई, किंतु उसमें जान डालने से पहले खुद लालू प्रसाद के हो गए। संघर्ष से मुंह मोड़कर सुविधा की राह पर निकल चले। लोकसभा जाने की बेताबी में लालटेन पकड़ ली। मधेपुरा में प्रचार के दौरान वोटरों को समझाया जा रहा था कि शरद का यह आखिरी चुनाव है। अगर यह सही है तो पराजय के बाद का संकेत क्या है, इसका इजहार आत्ममंथन के बाद खुद शरद ही कर सकते हैं।

जनसंख्या विस्फोट पर संजय झा और गिरिराज ट्विटर पर भिड़े

राज्य ब्यूरो, पटना : जनसंख्या वृद्धि के सवाल पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच ठन गई है। केंद्रीय मंत्री ने जनसंख्या वृद्धि पर एक ट्वीट के जरिए चिंता जाहिर की। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने रीट्वीट किया-केंद्र सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, उसकी चिंता करनी चाहिए। यह पहला अवसर है जब एनडीए के घटक दलों-भाजपा और जदयू के नेताओं के बीच ट्वीट वार हुआ है। तकरार की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या के संबंधित एक रिपोर्ट से हुई। इसका हवाला देकर गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया-बढ़ती जनसंख्या और उसके अनुपात में घटते संसाधन को कैसे झेल पाएगा हिन्दुस्तान? जनसंख्या विस्फोट हर दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान के लिए खतरनाक। भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़ बन जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। जवाबी ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा-देश की 130 करोड़ जनता ने राजग को विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट किया। जनसंख्या वृद्धि वास्तव में एक समस्या है और इसका ध्यान सबको है।

महाराष्ट्र के बजट में जल पर जोर

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- सूखे की मार से जूझ रहा है मराठवाड़ा और विदर्भ
- सिंचाई के साधनों के अभाव में बड़ी संख्या में किसान कर रहे आत्महत्या

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मंगलवार को राज्य का बजट पेश किया। इसमें कृषि क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी मराठवाड़ा क्षेत्र की पेयजल परियोजना के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत 2019-20 के लिए 2,720 करोड़ रुपये, बलीराजा जल संजीवनी योजना के लिए 1,531 करोड़ रुपये तथा 2014 से गांव के नजदीक के जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए चलाई गई जलयुक्त शिवार योजना के लिए 3300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र लगातार सूखे की समस्या से जूझता आ रहा है। खासतौर से मराठवाड़ा और विदर्भ में सिंचाई के साधनों का अभाव होने से किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए इस चुनावी वर्ष के बजट में अधिक जोर सिंचाई परियोजनाओं पर दिया गया है।

विपक्ष ने लगाया बजट लीक होने का आरोप

वित्त मंत्री के ट्विटर पर बजट लीक होने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अजीत पवार ने कहा कि प्रदेश में हमारी 15 सालों तक सरकार रही, लेकिन बजट के लीक होने जैसी कभी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट के प्रावधान वित्त मंत्री के ट्विटर हैंडल पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध थे। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री का ट्विटर अकाउंट संभालने वाली टीम को इसके बारे में पता था, जिसका साफ मतलब है कि बजट लीक हुआ है। इसके लिए वित्त मंत्री और सीएम को माफी मांगनी चाहिए।

67 रिवॉल्वर-पिस्टल को लूट लिया गया पंजाब स्थित जंडियाला के एचवी गन हाउस से। इसे पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी गन हाउस डकैती बताया जा रहा है। इससे पहले पंजाब की सबसे बड़ी गन हाउस डकैती 2009 में होशियारपुर में हुई थी। तब 100 पिस्टल व रिवॉल्वर लूटे गए थे।

हमारी सरकार थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री

संघर्ष से हार न मानने की अकूत ताकत

ऋषि पाण्डे • भोपाल

आज के दौर में जब पार्षद बनते ही मोहल्ला छाप नेताओं तक के दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाते हों, वहां थावरचंद गहलोत जैसे नेता भी हैं जो अभिमान से परे शुचिता और प्रामाणिकता से भरी राजनीति की डगर पर चलकर, उच्च सदन के नेता जैसे बड़े पद पर पहुंचते हैं। पद के लिए पराक्रम से ज्यादा परिक्रमा की अहमियत वाले मौजूदा कालखंड में ये बातें अचरज में डालती हैं कि एक ऐसा शख्स जो नाले किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी में रहा हो, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ा हो,साइकिल के पंक्चर और मिल में मजदूरी कर आजीविका चलाता रहा हो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉप टेन मंत्रियों में शामिल होकर राज्यसभा का नेता बन जाए !

पर यह हकीकत है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य और मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज जो भी मुकाम पाया उसमें उनकी सहजता, सरलता और विनम्रता का बड़ा रोल रहा है। तीन बार विधायक और चार बार लोकसभा के चुनाव में सफल रहे गहलोत भाजपा संगठन में भी लंबे समय तक सक्रिय रहे। उसी दौर में उनकी नरेंद्र मोदी से निकटता हुई। दलित वर्ग से संबंधित होने के बावजूद वे किसी वर्ग के नेता के रूप में नहीं पहचाने जाते।

पारिवारिक पृष्ठभूमि: गुरबत-गरीबी और संघर्षों के बीच पले-बढ़े थावरचंद गहलोत के माता-पिता भी उज्जैन जिले के नागदा में बिड़ला की ग्रेसिम मिल में मजदूरी करते थे। माताजी मिल के बगीचे की देखरेख साफ सफाई और पौधों को पानी देती थीं। माताजी ने कुछ समय ईंट के भट्टों में भी मजदूरी की। गहलोत के साथी बताते हैं कि वे जिस झुग्गी बस्ती में रहते थे वहां बिजली नहीं थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पडती थी। 18-20 साल के हुए तो थावरचंद भी मिल में मजदूरी करने लगे। 1970 में हुए नागदा गोली कांड की वजह से उन्हें नौ माह जेल में बिताने पड़े। तब उनकी पत्नी और दो बच्चों की देखरेख माता पिता ने की। इसी दौरान भारतीय मजदूर संघ से जुड़ गए। आंदोलन में सक्रियता के चलते मिल की नौकरी भी छूट गई। इसके बाद उन्होंने आजीविका के लिए साईकिल की दुकान खोली। चूंकि दिमाग मैकेनिकल था लिहाजा पंचर बनाने से लेकर साईकिल सुधारने के तमाम कामों में वे दक्ष हो गए। 1968 में फैक्टरी में नौकरी के दौरान उन्हें केरल भेजा गया। केरल में कालीकट के पास माउर में एक नया प्लांट डाला गया जहां मशीनों की स्थापना के लिए गहलोत को भेजा गया। वे करीब चार माह तक मशीनों को स्थापित करने के बाद वापस नागदा लौटे।

नागदा आकर भारतीय मजदूर संघ के कामकाज और अन्य सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय हो गए। नागदा में जनसंघ के वरिष्ठ नेता मांगीलाल शर्मा के साथ गहलोत जुड़ गए। इसी दौरान क्षेत्रीय नेताओं के साथ थावरचंद और अब्दुल हमीद आदि भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे के पास मांगीलाल शर्मा के लिए विधानसभा का टिकट मांगने पहुंचे। ठाकरे थावरचंद गहलोत का कामकाज और स्वभाव देख चुके थे, उन्होंने आदेशात्मक लहजे में कहा कि तुम खुद आलोट से चुनाव लड़ने की तैयारी करो। गहलोत के बचपन के साथी अब्दुल हमीद बताते हैं कि उस वक्त उनके पास नामांकन पत्र के साथ जमा करने के लिए ढाई हजार रुपये भी नहीं थे। उन्होंने परेशानी बताते हुए मना भी किया लेकिन कुशाभाऊ ने कहा सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। इसके बाद तत्कालीन संगठन मंत्री बाबूलाल जैन ने नामांकन पत्र की औपचारिकता पूरी कराई। 15 दिन के लिए पार्टी ने एक जीप उपलब्ध कराई जिससे चुनाव प्रचार किया गया।

45 साल से थावरचंद गहलोत के अभिन्न मित्र जगदीश अग्रवाल कहते हैं कि आपातकाल के बाद जेल में हम दोनों साथ रहे। मैंने देखा स्वभाव में स्थिरता और शांति उनके स्थायी भाव हैं, गुस्सा बहुत कम आता है। यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें हमेशा संगठन के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे। सुंदरलाल पटवा जब मुख्यमंत्री बने तब बतौर राज्यमंत्री थावरचंद गहलोत उनकी टीम में शामिल थे।

यारों के यार

सैलाना निवासी 42 साल पुराने मित्र अशोक जैन बताते है कि थावरचंद यारों के यार हैं। 20 साल पहले दुर्घटना के चलते मैं बुरी तरह घायल हो गया था, तब थावरचंद ने हरसंभव मदद की। दिल्ली ले जाकर इलाज कराया। आज मैं उनकी बदौलत स्वस्थ हूं। दिल इतना बड़ा और उदार है कि पूरा नागदा नगर ही उनके लिए परिवार की तरह है।

ईमानदारी-सहजता ही पूंजी

ईमानदारी, सहजता-सरलता और मेहनत ही उनकी पूंजी है। आज भी नागदा में उनका छोटा सा मकान है, कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे। यही वजह है कि उनमें आलस्य नहीं है।

बैंक कर्ज धोखाधड़ी में लॉजिस्टिक कंपनी के 6,000 वाहन किए जब्त

ईडी ने की कार्रवाई ▶ जब्त किए गए वाहनों की कीमत करीब 1,610 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र/आइएएनएस : 1,590 करोड़ रुपये की बैंक कर्ज धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सूरत की सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड (एसवीएलएल) और इसके प्रवर्तकों (प्रमोटर्स) के छह हजार से अधिक वाहनों को जब्त कर लिया। इनकी कीमत करीब 1,610 करोड़ रुपये है।

ईडी ने एक बयान में बताया कि हालिया आदेश के तहत जब्त किए गए वाहनों की संख्या कुल 6,170 और कीमत 1609.78 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने बताया कि जून 2017 में भी कंपनी की 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई थीं। सीबीआइ द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। एजेंसी के अनुसार, 'जांच में पता चला कि एसवीएलएल ने कर्मचारियों व वाहन चालकों को अंधेरे में रखते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक कर्ज लिए थे। यह बात भी जांच के दौरान सामने आई कि कंपनी के निदेशक रूपचंद बैद्य ने कर्ज की राशि को कई संस्थाओं के खातों में घुमाया।' ईडी ने बताया कि कर्मचारियों तथा चालकों के नाम पर कंपनी ने 'चालक से मालिक' जैसी कई योजनाओं के तहत कर्ज हासिल किए। जिन काम के लिए कर्ज लिए गए थे, उनकी जगह पर राशि का इस्तेमाल पुराने कर्ज की अदायगी और दूसरे मदों में किया गया। एजेंसी ने दावा किया कि बैद्य इस बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले का मुख्य साजिशकर्ता है।

ईडी ने पीएमएलए के तहत जारी किया था जब्ती आदेश : ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एसवीएलएल और इसके निदेशक रूपचंद बैद्य के खिलाफ जब्ती आदेश जारी किया था। ईडी पूर्व में बैद्य को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 836.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार भी कर चुकी है।

मंसूर खान की तीन पत्नियों के घर छापे

आइएमए ज्वेल्स घोटाला

बेंगलुरु, एएनआइ : धर्म के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर अरबों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आइ मोनेटरी एडवाइजरी (आइएमए) ज्वेल्स के प्रबंध निदेशक मुहम्मद मंसूर खान की तीन पत्नियों के घरों पर केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने छापेमारी की। मंसूर खान अरबों रुपये लेकर फरार हो गया है।

सीसीबी ने मंसूर खान की पहली पत्नी के शिवाजी नगर स्थित आवास पर छापा मारा। उसकी दूसरी और तीसरी पत्नी के तिलक नगर स्थित आवास पर भी छापा मारा गया। इस छापेमारी में निवेश और खान के वित्तीय मामलों से संबंधित दस्तावेज के साथ ही 1.5 किलोग्राम सोना और 2.7 लाख रुपये नकद बरामद किया गया। मंसूर खान ने ज्यादा रिटर्न का लालच देकर हजारों लोगों से कंपनी में निवेश कराया था। निवेश करने वाले ज्यादातर

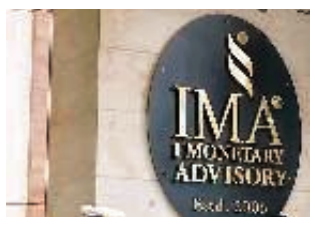

प्रतीकात्मक फोटो

- कसा शिकंजा-निवेश संबंधी दस्तावेज, 1.5 किलो सोना और 2.7 लाख रुपये नकद बरामद
- एसआइटी ने सीबीआइ से खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा

मुस्लिम हैं। लगभग दो हजार करोड़ रुपये के निवेश का अब तक पता चला है। इसमें 200 करोड़ रुपये तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं द्वारा निवेश किया गया है। आइएमए के खिलाफ अब तक 38 हजार निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है।

एसआइटी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को पत्र लिख कर मंसूर खान का पता लगाने के लिए इंटरपोल की मदद लेने को कहा है। एसआइटी के प्रमुख डीआइजी रविकांत गौड़ा ने कहा कि मंसूर खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। आइएमए मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 18 याचिकाएं दायर की गई हैं। कंपनी में निवेश करने वालों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। इस मामले में आइएमए के सात निवेशकों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। मंसूर खान की पुलिस को तलाश है। आइएमए पर अपने निवेशकों को पिछले तीन महीने से ब्याज का भुगतान नहीं करने का आरोप है।

डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पर सुनवाई टली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोर्ट ने कहा कि हड़ताल वापस हो चुकी है इसलिए मामले पर तत्काल सुनवाई की नहीं है जरूरत
- डॉक्टरों की सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर छुट्टियों बाद अदालत करेगी विचार

डॉक्टरों की हड़ताल और सुरक्षा का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल व अन्य जगह पर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने माना कि डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है और उस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। कोर्ट ने मामले को छुट्टियों के बाद उचित पीठ के समक्ष लगाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाशकालीन पीठ ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर फिलहाल केंद्र को नोटिस जारी नहीं कर रहा है। लेकिन उसका मानना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर समग्र रूप से विचार होना चाहिए। यह गंभीर मुद्दा है, लेकिन अन्य नागरिकों की कीमत पर ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि वह डॉक्टरों को संरक्षण देने के विरोध में नहीं हैं।

श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें देश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए जाएं और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश तय करने का

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

आदेश दिया जाए। साथ ही कोलकाता में डाक्टरों पर हमला करने वालों पर पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश मांगा गया है।

आइएमए ने किया याचिका का समर्थन : इस बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर श्रीवास्तव की याचिका का समर्थन किया है और कोर्ट से देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। हस्तक्षेप अर्जी में आइएमए ने डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं का एक अध्ययन पेश करते हुए आंकड़े दिए हैं।

पश्चिम बंगाल में काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर, मरीजों को राहत

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सात दिनों की हड़ताल के बाद कोलकाता के एनआरएस समेत पश्चिम बंगाल के सभी 14 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डाक्टर मंगलवार से काम पर लौट आए। इस दिन सुबह से सभी सरकारी अस्पतालों के आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी), पैथोलॉजिकल यूनिट एवं अन्य विभागों में सामान्य तरीके से कामकाज शुरू हो गया। एक सप्ताह तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने के कारण समस्त सरकारी अस्पतालों के सभी विभागों के सामने मरीजों एवं उनके परिजनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। ज्वाइंट फोरम ऑफ जूनियर डॉक्टर्स के एक प्रवक्ता ने बताया, 'हमारे ज्यादातर सहकर्मियों ने मंगलवार सुबह से फिर से काम करना शुरू कर दिया है और नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सीनियर डॉक्टरों का सहयोग कर रहे हैं। चूंकि बहुत से जूनियर डॉक्टर सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्य सचिवालय में हुई बैठक में भाग लेने विभिन्न जिलों के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से आए थे, वे अपने-अपने अस्पताल पहुंचने के साथ ही ड्यूटी पर लग जाएंगे।' अस्पताल परिसरों में कड़ी सुरक्षा : राज्य प्रशासन की ओर से मंगलवार को अस्पताल परिसरों में डाक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की अस्पतालों में तैनाती की गई थी, जो पल-पल की स्थिति पर नजर रख रहे थे।

जानलेवा हमले के आरोप में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बेटा गिरफ्तार

नईदुनिया, नरसिंहपुर : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल को हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार दोपहर मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रह्लाद पटेल के भाई और मप्र के पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू संग 12 नामजद और आठ अन्य को आरोपित बनाया गया है। मोनू फरार है। विवाद में होमगार्ड सहित सात लोग घायल हुए हैं। एक युवक को गोली भी लगी है। सभी घायलों को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, कमोद गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद दोनों पक्षों के बीच बैलहाई मोहल्ले में रास्ते से निकलने को लेकर सोमवार रात विवाद हो गया। घायल हिमांशु राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि विवाद के दौरान शिवम को देखते ही प्रबल पटेल ने जान से मारने के लिए फायर किया, लेकिन शिवम ने गर्दन झुका ली। उसके बाद दोबारा फायर किया गया तो गोली मेरे दाहिने हाथ की हथेली पर लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर शिवम के पिता होमगार्ड सैनिक ईश्वर राय आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई और घायल हालत में सड़क के किनारे फेंक दिया गया।

सरकारी तंत्र की निगरानी में होगी औली में शादी, तीन करोड़ रुपये करने होंगे जमा

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- डीएम होंगे जिम्मेदार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा शादी की वीडियोग्राफी
- जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन

चमोली जिले के औली में उद्योगपति गुप्ता बंधुओं के बेटों विवाह समारोह सरकारी तंत्र की निगरानी में होगा। नैनीताल हाई कोर्ट ने यहां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन रोकने के लिए चमोली के डीएम को जवाबदेह बनाया है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आयोजन की मॉनिटरिंग और वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी दी गई है। समारोह खत्म होने के बाद डीएम सात जुलाई को शपथ पत्र के साथ अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने गुप्ता बंधुओं को तीन करोड़ रुपये सिक्योरिटी के रूप में 21 जून तक दो किश्तों में जमा करने का आदेश दिया है। पर्यावरण को नुकसान होने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जाएगी। आठ जुलाई को कोर्ट इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई करेगा।

सरकार ने कहा बुग्याल चार किलोमीटर दूर : एक रोज पहले कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में कई सवालों के जवाब मांगे थे। मंगलवार को राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शादी की मॉनिटरिंग के लिए टीम औली भेजी जा चुकी है। जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वीडियोग्राफी करेगी। वहीं, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिस स्थान पर शादी हो रही है, वहां से बुग्याल चार किमी दूर है। इसके अलावा इवेंट कंपनी ने अदालत को टैंट, कुकिंग गैस, लैंडस्केप सुधार, रूम हीटर, जनरेटर, स्टाफ इत्यादि की जानकारी दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शादी पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई, लेकिन इस पर सरकारी निगरानी बैठा दी है।

समय से याचिका मिलती तो नहीं देते अनुमति : सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याची से कहा कि याचिका दायर करने में उन्होंने देर कर दी। अब तो शादी का कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, अगर एक हफ्ते पहले याचिका दायर करते तो नहीं देते शादी के आयोजन की अनुमति।

22 जून तक चलेंगी शादी की रस्में : दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के उद्योगपति अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता के बेटों की शादी औली में 22 जून तक चलेगी। लगभग 200 करोड़ की लागत से हो रही इस शादी में बॉलीवुड की हस्तियों के साथ ही देश-विदेश के विशिष्ट मेहमानों के आने की सूचना है।

कोर्ट की व्यवस्था

- लाइव बैंड और आर्केस्ट्रा की ध्वनि निर्धारित सीमा से अधिक न हो
- लैंडस्केप को जेसीबी मशीन लगाकर नहीं बदला जाए
- पर्यावरणीय मानकों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो
- पर्यावरण के मानकों के उल्लंघन पर डीएम और पीसीबी होंगे जिम्मेदार
- आयोजन की मॉनिटरिंग व वीडियोग्राफी करें
- सात जुलाई को डीएम शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करेंगे
- आठ जुलाई को रिपोर्ट के आधार पर होगी सुनवाई

गुजरात में योगाभ्यास...

गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार को योगाभ्यास सत्र में हिस्सा लेती मुस्लिम छात्राएं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर देश-दुनिया में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। योगाभ्यास के विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। योग दिवस 21 जून को है। रायटर

आदेश

राज्य अतिथियों की सूची-एक को छोड़ अन्य किसी को नहीं मिलेगा वीआइपी ट्रीटमेंट, पार्क में सफारी व ठहरने के अफसरों के सिफारिशी पत्रों तो तुरंत वापस लौटाया जाएगा

कार्बेट नेशनल पार्क में खत्म हुआ वीआइपी राज

केदार दत्त, देहरादून

केंद्र सरकार द्वारा वीआइपी कल्चर पर किए गए कड़े प्रहार का असर उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क पर भी पड़ा है। पार्क में वीआइपी राज समाप्त हो गया है। अब उत्तराखंड राज्य अतिथि नियमावली की सूची-एक में शामिल संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को छोड़ अन्य किसी को वीआइपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इस संबंध में पार्क निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिए हैं। पार्क में सफारी व ठहरने के लिए अफसरों और ऊंची पहुंच वाले लोगों के सिफारिशी पत्रों को तुरंत वापस लौटाया जाएगा। यही नहीं, अफसरों के पत्रों के बारे में उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा कि वे व्यक्तिगत कार्यों के लिए किस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

वर्ष 1936 में स्थापित किए गए देश के सबसे पुराने कार्बेट नेशनल पार्क का प्रबंधन लंबे अर्से से वीआइपी दौरों से परेशान था। सरकारी तंत्र से लेकर राजनीतिज्ञों की ओर से अक्सर कार्बेट पार्क में सफारी के साथ ही वन विश्राम गृहों में ठहरने समेत अन्य व्यवस्थाओं की मांग की जाती रही। खुद के साथ ही नाते-रिश्तेदारों तक के लिए पत्राचार हो रहा था। सूरतेहाल, वीआइपी के लिए व्यवस्थाएं जुटाने को पार्क के अमले को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी, जबकि इसका सरकारी कार्मिकों के दायित्व निर्वहन से कोई वास्ता नहीं है। वह भी तब, जबकि पार्क में कार्मिकों की कमी है।

अब पार्क में वीआइपी राज खत्म हो गया है। पार्क के निदेशक संजीव चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, पार्क प्रबंधन की जिम्मेदारी वासस्थल विकास और सुरक्षा की है। फिर पार्क में ठहरने को पारदर्शी व्यवस्था है। इसके तहत देश के नागरिक अथवा विदेशी मेहमान वन विश्राम गृह के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। पार्क से बाहर कई होटल व रिजॉर्ट्स हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार इनका उपयोग कर सकता है। आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने राज्य अतिथियों के लिए नियम बनाए हैं। राज्य अतिथि नियमावली की सूची-एक में साफ है कि देश के कौन-कौन से संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति राज्य अतिथि होंगे। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत चुनिंदा नाम हैं। इसके अलावा सूची-दो में उन लोगों को राज्य अतिथि माना गया है, जो सरकारी कार्य से उत्तराखंड आते हैं।

कार्बेट नेशनल पार्क की फाइल फोटो।

क्या कहा गया है आदेश में

आदेश में कहा गया है कि कार्बेट पार्क में सफारी और ठहरने के लिए उन पदों के लिए पत्राचार होता है, जो कि राज्य अतिथि सूची से बाहर के हैं। स्पष्ट किया गया है कि अब राज्य अतिथियों की सूची-एक को छोड़ अन्य किसी को वीआइपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि सफारी व ठहरने को कोई अधिकारी अथवा अन्य कोई पत्राचार करता है तो इसे पद का दुरुपयोग मानते हुए तुरंत वापस लौटाया जाएगा। ऐसे मामलों में उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

एएन-32 विमान में सवार जवानों के शव लाने की कोशिशें तेज

- गरुण कमांडो, पोर्टर और शिकारियों के दल को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया
- खराब मौसम और घने बादलों के चलते शवों को निकालने में रुकावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय वायु सेना के दुर्घटनाग्रस्त विमान एएन-32 में सवार 13 जवानों के शवों को निकालने का प्रयास तेज कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में गहरी खाई से शवों को बाहर निकालने के लिए गरुण कमांडो, पोर्टर और शिकारियों के एक दल को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है।

शिलांग स्थित वायु सेना के प्रवक्ता विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने कहा कि इस दल का पहला जत्था सोमवार को रवाना हुआ था, जिसके हादसा वाले जगह पर मंगलवार तक पहुंच जाने की संभावना थी।

उन्होंने कहा कि खराब मौसम के चलते मंगलवार को शवों को बाहर निकालने का काम नहीं हो सका। दुर्घटना वाले क्षेत्र में किसी ऐसी खुली जगह की तलाश की जा रही है जहां हेलीकॉप्टर भेजा जा सके, लेकिन अभी ऐसी कोई जगह नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि शवों को बाहर निकलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि शवों को निकालने की कोशिश में एमआइ 17, चीता और एएलएच जैसे हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, लेकिन खराब मौसम और दुर्घटनास्थल के ऊपर घने बादलों के चलते अभी कोई सफलता नहीं मिल पाई है।

एमआइ 17 हेलीकॉप्टर ने 11 जून को विमान के मलबे को ढूंढा था। उसके बाद 15 पर्वतारोहियों की टीम को वहां उतारा गया था। बाद में तीन और पर्वतारोहियों को भी वहां भेजा गया था। घने जंगलों के बीच गहरी खाई में गिरे हेलीकॉप्टर के मलबे से शवों को निकालकर पैदल ही बाहर लाया जा सकता है।

42 वन अधिकारी मिले हैं देश के सात राज्यों को। ये अधिकारी केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा देहरादून के वर्ष 2017-18 बैच के हैं। गत दिवस इन प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों का दीक्षांत समारोह किया गया। इनमें 10 महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 19 जून 2019

दोषियों को फांसी की सजा चाहते हैं पीड़ितों के आश्रित

भरे नहीं जख्म ▶ अपनों को खोने के बाद पीड़ितों का एक-एक पल हत्यारों की फांसी की चाहत में बीता

आतंकियों को सजा से रामनगरी के जख्म पर लगा मरहम

रघुवरशरण, अयोध्या

रामजन्मभूमि परिसर में पांच जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले के चार गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा रामनगरी के जख्म पर मरहम लगाने वाली भले हो लेकिन पीड़ितों के आश्रित उन्हें फांसी होते देखना चाहते हैं। उनके कलेजे को पूरी तरह ठंडक नहीं मिली है।

आतंकी भले ही अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उनकी गोलाबारी और फायरिंग में रमेश पांडेय नामक स्थानीय गाइड की मौत हो गई थी। एक महिला सहित दो नागरिक एवं आधा दर्जन से अधिक पीएसी व सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए थे। ज्यादातर के जख्म तो भर गए लेकिन गाइड रमेश पांडेय की पत्नी सुधा एवं बेटी अंशिका के जख्म नहीं सूखे हैं। अंशिका प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर मां की संबल बनने की इच्छा रखती है, लेकिन 14 वर्ष पूर्व वह छोटी थी। पति को खो देने के बाद पहाड़ जैसी जिंदगी से पार पाने का जिम्मा अकेले सुधा पर था। उनका एक-एक पल पति के हत्यारों की फांसी की चाहत में बीता। ऐसे में आजीवन कारावास की सजा भले ही उनकी चाहत के माकूल नहीं हो पर मां-बेटी के लिए यह खबर जख्म पर मरहम जैसी थी।

61 वर्षीय रामचंदर यादव को उम्र के जिस दौर में पत्नी शांतिदेवी की सर्वाधिक जरूरत थी, उस उम्र में वह विस्फोट की चपेट में आकर उनका साथ छोड़ गईं। 21 दिनों तक चली सघन चिकित्सा के बाद भी ठीक नहीं हो सकीं। इसके बाद रामचंदर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पत्नी, पांच पुत्रियों, दो पुत्रों एवं मां से युक्त रामचंदर के 10 सदस्यीय परिवार में पांच सदस्य पिछले 14 वर्ष के दौरान काल-कवलित हो चुके हैं। चाय की दुकान चलाकर अविवाहित बची बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी में लगे रामचंदर की चाहत थी कि सभी दोषियों को फांसी हो, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आजीवन कारावास की सजा पर वह गहरी श्वास छोड़ते हैं, जैसे यह बताने की कोशिश कर रहे हों कि उनके जीवन का खोया बसंत लौट के नहीं आने वाला।

मुकुट बनाने का काम करने वाले कृष्णस्वरूप भी आतंकी हमले में हुए विस्फोट से जख्मी हो गए थे। उनका इलाज नौ वर्ष तक चला पर वह अपने पैरों पर खड़े हुए बिना दुनिया से कूच कर गए।

आतंकी हमले के फैसले को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा रखी थी। इस दौरान अयोध्या के प्रवेश द्वार पर वाहनों की चेकिंग करती पुलिस। जागरण

डॉ. इरफान की एसटीडी से आतंकियों को की गई थी कॉल

जासं, सहारनपुर : अयोध्या में हुए आतंकी हमले के सूत्रधार के रूप में पकड़े गए सहारनपुर स्थित तीतरों के डॉ. इरफान को भी उम्रकैद की सजा हुई है। सजा का पता लगा तो यहां उसकी मां व भाई ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय जाने की बात कही। पांच जुलाई 2005 की सुबह राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के आठ दिन बाद एसटीएफ ने तीतरों में दबिश डालकर डॉ. इरफान को गिरफ्तार कर लिया था। इरफान तभी से इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है। मंगलवार को सजा सुनाए जाने के बाद इरफान की मां जेबुनिशा ने कहा कि षड्यंत्र रचकर मेरे बेटे को फंसाया गया है। आतंकी हमले से पहले डॉ. इरफान कई साल तक दिल्ली में रहा था। वहीं पर उसका संपर्क आतंकियों से हुआ था।

ढेर कर दिए गए थे पांच आतंकी

प्रथम पृष्ठ से आगे

लश्कर-ए-तैयबा के पांच आतंकियों ने पांच जुलाई, 2005 की अलसुबह रामजन्मभूमि परिसर की बाहरी बेरीकेडिंग पर विस्फोट करने के बाद अंदर घुसने का प्रयास किया। जहां सीआरपीएफ की 33 वीं बटालियन के जवान तैनात थे। गर्भगृह में प्रवेश करने का खतरनाक मंसूबा पाले आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके। करीब डेढ़ घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मुख्य साजिशकर्ता मो. अरशद सहित पांचों आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया था। इस दौरान दो स्थानीय लोग रमेश कुमार पांडेय व शांति देवी मारे गए थे और सीआरपीएफ के सात जवान जख्मी हो गए थे।

नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे आतंकी : सभी आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे। आतंकी टाटा सूमो से राम भक्त बनकर दर्शन के बहाने परिसर में पहुंचे थे और पूरे इलाके की रेकी की थी। आतंकियों ने राममंदिर के दर्शन भी किए थे।

जब गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम गई थी अयोध्या

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

2005 की पांच जुलाई की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से रामनगरी सहम उठी थी। पहले तो लोगों को यह समझ में ही नहीं आया कि माजरा क्या है? लेकिन जब तड़तड़ाहट थमी तो खौफनाक मंजर था। सुबह करीब नौ बजे सब कुछ सामान्य चल रहा था। इसी दौरान विवादित परिसर के पिछले हिस्से में उनवल मंदिर बैरियर से एक सफेद रंग की जीप परिसर की तरफ बढ़ी। बैरिकेडिंग के पास पहुंचते ही कुछ लोग हाथ में बैग लिए जीप से बाहर कूदे थे। गाइड रमेश पांडेय श्रद्धालुओं का वाहन समझकर गाड़ी के पीछे पहुंचे ही थे कि जीप जाकर बैरिकेडिंग से जा टकराई। तेज धमाके के साथ जीप के परखचे उड़ गए। रमेश पांडेय की भी मौत गई। फिर आधुनिक हथियारों और विस्फोटकों से लैस आतंकी परिसर में दाखिल होते हुए लगातार गोलियां चलाने लगे। सभी रामलला के मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए सिविल पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से भी गोली चलाई जा रही थी। करीब एक घंटे तक गोलियां चलती रहीं। आतंकी अधिगृहीत परिसर में कुछ ही कदम आगे बढ़ पाए थे कि जवानों की गोलियों से छलनी होना पड़ा। हमले में घायल शांति देवी की 21वें दिन मौत हुई थी।

फैसले की घड़ी पर कड़े पहरे में रही रामनगरी : अधिगृहीत परिसर में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रयागराज में विशेष अदालत का फैसला आने के दिन रामनगरी भी कड़े पहरे में रही। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर थी। कुछ दिनों पहले आतंकी वारदात संबंधी इनपुट मिला था, इस वजह से सुरक्षा व निगरानी का घेरा काफी सख्त रहा। वैसे मंगलवार होने की वजह से आम दिनों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी। उन्हें चेकिंग और रोक-टोक के बीच आराध्य की चौखट तक पहुंचना पड़ा।

पैरामिलिट्री फोर्स व पीएसी की अतिरिक्त कंपनियों ने आमद पहले ही करा ली थी। आर्मी के साथ सीआरपीएफ इंटेलीजेंस के अधिकारी भी अयोध्या में पल-पल की टोह लेते रहे। सुरक्षा व निगरानी को लेकर खुफिया एजेंसियों ने पहले से ही डेरा डाल दिया था। एसएसपी आशीष तिवारी ने मंगलवार सुबह ही अयोध्या पहुंच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को सचेत रहने की हिदायत दी। चेकिंग के बाद ही वाहनों को रामनगरी में प्रवेश दिया गया। हनुमानगढ़ी व कनक भवन सहित प्रमुख मंदिरों को खंगाला गया।

पुलवामा में वाहन बम हमले में घायल दो जवानों शहीद हुए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पुलवामा में सोमवार को हुए वाहन बम हमले में घायल एक और सैनिक ने मंगलवार सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हमले में शहीद होने वाले सैन्यकर्मियों की संख्या दो हो गई है। अस्पताल में उपचाराधीन अन्य 17 घायल सैनिकों में एक और की हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलवामा जिले के अरिहाल इलाके में आतंकियों ने सोमवार शाम को विस्फोटकों से भरे एक वाहन से सेना की 44 आरआर के जवानों को लेकर गुजर रहे एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया था। इस दौरान सैन्य चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया था, जिससे सैन्य वाहन को न्यूनतम नुकसान हुआ। इस हमले में 19 सैन्यकर्मी घायल हो गए। इनमें सैन्य चालक और उसके साथ वाहन के अगले हिस्से में बैठे दो अन्य जवान बुरी तरह घायल हो गए। विस्फोटक स्थल के पास ही खेतों में काम कर रहे दो ग्रामीण भी इस हमले में जख्मी हुए थे। धमाके के बाद पास ही छिपे आतंकियों ने क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकल रहे जख्मी जवानों पर फायरिंग भी की, लेकिन जवानों ने तुरंत जवाबी फायर कर आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। हमले में घायल एक जवान ने देर रात ही शहीद हो गया था। जबकि दूसरे ने मंगलवार सुबह शहादत पाई।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि शहीदों की पहचान नायक अजीत कुमार साहु निवासी बडासुआनलो, तहसील कामख्या, जिला धेनखल, ओडिशा और अमरजीत कुमार निवासी गांव दिगवालिया, जिला सिवान, बिहार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अन्य घायल सैनिकों की स्थिति स्थिर बनी हुई है।

अजीत कुमार साहू।

अमरजीत कुमार।

- अन्य 17 घायल सैनिकों का उपचार जारी, एक की हालत अब भी नाजुक
- आतंकियों ने पुलवामा में वाहन बम से सेना को बनाया था निशाना

पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला, आठ घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार को आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में आठ लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल, किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे आतंकियों ने पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन निशाना चूकने से ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के गेट के पास सड़क पर गिरकर फटा। ग्रेनेड फटने से वहां से गुजर रहे आठ नागरिक घायल हो गए। धमाके के बाद वहां अफरातफरी फैल गई। इस बीच, पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दो ग्रामीणों को गंभीर चोट पहुंची है। उन्हें उपचार के लिए श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि सोमवार की शाम आतंकियों ने पुलवामा के अंतर्गत त्राल स्थित सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी के शिविर और काकपोरा पुलिस स्टेशन पर अलग-अलग ग्रेनेड हमले किए थे। इन हमलों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था।

अनंतनाग मुठभेड़ स्थल से युवक का शव मिलने से तनाव

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को उस समय तनाव फैल गया जब बड़ूरा में स्थानीय लोगों ने एक युवक को गोलियों से छलनी शव बरामद किया। यह शव उसी जगह पड़ा था जहां सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लोगों ने युवक की मौत के लिए सुरक्षाबलों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने इससे इन्कार करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। युवक का शव मिलने के साथ ही इस मुठभेड़ में मरने वालों की तादाद तीन हो गई है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था, जबकि सेना के मेजर केतन शर्मा शहीद हो गए थे।

स्थानीय लोगों ने सुबह जब मुठभेड़ के दौरान नष्ट हुए मकान की सफाई शुरू की तो उन्हें पास के बाग में युवक का शव मिला। उसकी पहचान चक्की अच्छाबल निवासी नासिर अहमी मीर पुत्र फैयाज अहमद मीर के रूप में हुई है। वह बीए पार्ट वन का छात्र था। नासिर का शव मिलने के साथ ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोगों ने नासिर के शव को लेकर जुलूस भी निकाला। उन्होंने दोषी सैन्य कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की।

कश्मीर में जेहाद के रास्ते से लौटे दो युवा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जेहाद के रास्ते से दो युवकों को वापस लाने के पुलिस के दावे के कुछ घंटे बाद ही लश्कर-ए-तैयबा ने पुलवामा के तीन युवकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर उनके जेहादी बनने का एलान किया है। इस साल 50 से ज्यादा स्थानीय युवकों ने आतंकी संगठनों का दामन थामा है। इनमें से ज्यादातर पुलवामा से हैं। गौरतलब है कि 2016 में आतंकी बुरहान की मौत के बाद से ही आतंकी संगठनों में स्थानीय युवकों की भर्ती की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। युवकों को आतंकी बनने से रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों के जरिए कई योजनाएं शुरू की हैं। राज्य पुलिस के मुताबिक करीब तीन दर्जन युवकों को आतंकी बनने से रोका गया है।

किसी पर दर्ज नहीं किया केस : पुलिस ने मंगलवार सुबह कहा कि इन दोनों युवकों को आतंकवाद छोड़ मुख्यधारा में शामिल कराने में परिजनों और दोस्तों ने पूरी मदद की है। इन युवकों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अलबत्ता, इन युवकों को काउंसिलिंग प्रदान की जा रही है।

रंजना अग्रवाल बनीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की निदेशक

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉ. रंजना अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (सीएसआइआर-एनआइएसटीएडीएस) नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया है।

इस संस्थान के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन हैं। डॉ. रंजना अग्रवाल की नियुक्ति छह वर्ष के लिए की गई है। यह संस्थान केंद्र सरकार के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रमुख अनुसंधानों में एक है। यह प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञान, समाज और राज्य के बीच संवाद के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच निरंतर जुड़ाव की संभावनाओं की खोज करता है। डॉ. रंजना अग्रवाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीएससी, एमएससी तथा पीएचडी की डिग्री उत्तीर्ण करने के उपरांत कैंब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से एरिथ्रोमाइसिन बायोसिंथेसिस पर पोस्ट डॉक्टरल शोध किया है।

विदेश मंत्री जयशंकर को आवंटित हो सकता है मनोज सिन्हा का बंगला

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का नया ठिकाना पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का 12, तुगलक रोड स्थित बंगला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ववर्ती सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे सिन्हा इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चुनाव हार गए हैं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 27, सफदरजंग रोड बंगले में जा सकते हैं। यह बंगला पहले कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवंटित था, लेकिन वह इस बार चुनाव हार गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला व खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी को 10, अकबर रोड स्थित बंगला आवंटित किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री महेश शर्मा रहते थे।

सूत्र बताते हैं कि पहली बार मंत्री बने प्रताप सारंगी को दिल्ली भाजपा कार्यालय के निकट 10, पंडित पंत मार्ग बंगला आवंटित किया गया है। यहां भाजपा के पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव रहते थे। ओडिशा के बालासोर से सांसद सारंगी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग तथा पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग के राज्यमंत्री हैं। सूत्रों का कहना है कि बंगलों का आवंटन नेताओं द्वारा खाली किए जाने पर निर्भर करता है।

मुंबई में केरल के माकपा नेता के पुत्र पर दुष्कर्म का मामला दर्ज

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई पुलिस ने केरल की माकपा इकाई के सचिव कोडिएरी बालकृष्णन के पुत्र बिनोय विनोदिनी बालकृष्णन के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पूर्व बार डांसर और बिहार निवासी महिला की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनका एक बच्चा भी है। उधर, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। माकपा नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने जहां इस मामले में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इन्कार किया, वहीं भाजपा की केरल इकाई ने मामले की गहनता से जांच कराने की मांग की है।

ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेश पसलवाड ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला आरोपित से दुबई में मिली थी, जहां वह एक बार में डांसर थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि बिनोय डांस बार में अकसर आता था, जिसके चलते दोनों के बीच संबंध हो गए। आरोपित ने उससे शादी का वादा करके डांस बार की नौकरी छोड़ने को कहा। महिला ने यह भी दावा किया कि 2010 में आरोपित ने उसे एक घर किराए पर लेकर दिया, जहां पर वह अकसर आता-जाता था। महिला ने कहा कि उसे पिछले साल ही पता चला कि आरोपित पहले से ही शादीशुदा है।

- दुबई में हुई थी दोनों की जान-पहचान, शिकायतकर्ता वहां थी बार डांसर
- भाजपा की केरल इकाई ने मामले की गहनता से जांच कराने की मांग की है

शिकायतकर्ता मुझे ब्लैकमेल कर रही : आरोपित : आरोपित ने महिला से पहचान की बात स्वीकार की है, लेकिन आरोपों को निराधार बताया है। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में उसने कहा कि शिकायतकर्ता मुझे ब्लैकमेल कर रही है। छह महीने पहले उसने पत्र भेजकर पांच करोड़ रुपये मांगे थे। इसके खिलाफ उसने कन्नूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। उसने कहा कि मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज करने से पहले उससे कोई संपर्क भी नहीं किया।

मुठभेड़ में मारी गई आठ लाख की इनामी महिला नक्सली कमांडर

नईदुनिया, धमतरी: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाके कट्टीगांव और सिंघनपुर के बीच घने जंगल में मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ में जवानों ने नक्सल संगठन सीतानदी दलम की कमांडर सीमा मंडावी को मार गिराया। अन्य नक्सली जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर भाग गए। सीमा पर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था।

जानकारी के अनुसार बोराई थाना क्षेत्र के कट्टीगांव व सिंघनपुर इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम मंगलवार अलसुबह सर्चिंग पर निकली थी। जंगल में पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी।

जवानों ने भी मोर्चा संभालकर जवाबी फायर किए। करीब घंटे भर की फायरिंग के बाद नक्सली भाग निकले। मौके की सर्चिंग करने पर एक वर्दीधारी महिला नक्सली का शव बरामद हुआ। उसकी शिनाख्त सीमा मंडावी के रूप में की गई है। मौके से एक इंसास रायफल, दो मैग्जीन, पिट्ठू बैग, नक्सली साहित्य, दवाइयां और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है।

मेजर केतन शर्मा को रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली में मंगलवार को पालम हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद मेजर केतन शर्मा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को श्रद्धांजलि दी। 29 वर्षीय मेजर शर्मा अनंतनाग जिले में सोमवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। एक जगह छिपे आतंकियों ने सैन्य दल पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इसमें एक आतंकी भी मारा गया था।

मेजर शर्मा का पार्थिव शरीर मंगलवार को दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचा था। जहां रक्षा मंत्री सिंह और सेना प्रमुख जनरल रावत ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिंह ने ट्वीट किया, 'जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर केतन शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर शर्मा ने सच्चे सिपाही की तरह आतंकियों से मुकाबला किया। मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है।' बाद में मेजर शर्मा के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर मेरठ ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया।

हालात

पीढ़ियां गुजर गईं अब तो मिल जाए इंसाफ, न्याय की आस में लोगों को मिल रही सिर्फ तारीख पर तारीख

उप्र में 30 वर्ष से लंबित हैं 32 हजार मुकदमे

आलोक शर्मा, कानपुर

प्रदेश में लंबित उन मुकदमों की तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जिनमें पीड़ित इंसाफ की आस में तारीख पर तारीख ले रहे हैं। मुकदमा लड़ते-लड़ते पीढ़ियां गुजर गईं। अधिवक्ता भी बदल गए, न्याय की चाहत में कोर्ट जाने वाले उम्र पूरी कर दुनिया से चले गए। अब उनकी पीढ़ियां तारीख ले रही हैं और हर तारीख पर इस उम्मीद से कोर्ट पहुंचती हैं कि शायद अब फैसला हो जाए। अकेले कानपुर में ही ऐसे 927 मुकदमे हैं, जो 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय से लंबित हैं। इतनी लंबी अवधि तक लंबित मुकदमों का प्रदेश का आंकड़ा 32,871 है।

केस-1

कानपुर में वर्ष 1965 में माया देवी ने अपने ससुर खजांची लाल पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमा किया था। दोनों की मौत हो चुकी है। मुकदमा दाखिल करने वाले अधिवक्ता आरके वाजपेयी की भी मौत हो गई है। अब माया के बेटे आशीष जैन और खजांची लाल के भतीजे अनिल जैन मुकदमा लड़ रहे हैं। अब अधिवक्ता आरके वाजपेयी के बेटे इंदीवर वाजपेयी हैं।

प्रतीकात्मक

सिविल के मुकदमों की सुनवाई में सुधार हुआ है। ज्यादा पुराने मामलों में सप्ताह भर की तारीख पड़ रही है। हालांकि नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक 32 हजार से ज्यादा मामले 30 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित हैं, यह चिंता का विषय है।

-इंदीवर वाजपेयी, पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन, कानपुर

केस-2

कानपुर में कोतवाली क्षेत्र की सरला मेहरोत्रा और एचपीसीएल ने एक दूसरे पर वर्ष 1985 में मुकदमा किया था। सरला के पति हरिहर नाथ ने काल टैक्स इंडिया को पेट्रोल पंप चलाने के लिए 30 वर्षों की लीज पर जमीन दी थी। कंपनी का एचपीसीएल में विलय हो गया तो यहां एचपीसीएल आ गई। लीज खत्म होने पर सरला ने बेदखली के लिए जबकि कंपनी ने स्टे की अपील की।

प्रदेश में लंबित

वर्षवार लंबित	केस की संख्या
30 वर्ष से अधिक	32,871
20 से 30 वर्ष	1,02,147
10 से 20 वर्ष	4,52,205
5 से 10 वर्ष	11,72,325

कोलकाता में पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स से छेड़छाड़, कार पर पथराव

जागरण संवाददाता, कोलकाता : महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस कितनी सक्रिय है, इसका नजारा सोमवार रात देखने को मिला। कोलकाता में सरेराह मनचलों के एक झुंड ने कार रोककर पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स व अभिनेत्री ऊषोशी सेनगुप्ता के साथ छेड़छाड़ की। कार पर पथराव करने के साथ ही उनका मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। मदद के लिए भागकर थाने पहुंची पीड़िता को पुलिस ने सीमा क्षेत्र का हवाला देकर टरका दिया। घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ऊषोशी बांग्ला, हिंदी समेत दक्षिण भारत की कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि रात को वह अपनी महिला दोस्त के साथ बाइपास स्थित एक पांच सितारा होटल से टैक्सी से घर लौट रही थीं। मैदान थाने के पास एक्साइड मोड़ से बाएं तरफ कार के मुड़ते ही एक बाइक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 15 युवक वहां पहुंच गए मारपीट, छेड़छाड़ की।

जंगल में आग गंभीर मामला बारिश के लिए प्रार्थना करें

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में आग से वन, वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर 24 जून को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मंगलवार को अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, हम इस पर 24 जून को सुनवाई करेंगे, तब तक आप आप बारिश के लिए प्रार्थना करें।

वकील ऋतुपर्ण उनियाल ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि जंगल में आग से हर साल वन संपदा, वन्य जीव और पक्षियों को भारी नुकसान होता है। आग हर साल बढ़ती ही जा रही है और इससे पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है।

याचिका में आग से बचाव के लिए पहले से कदम उठाने के लिए केंद्र, उत्तराखंड सरकार और राय के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश देने की मांग की गई है। जंगली आग को रोकने के लिए एक नीति बनाने की मांग भी की गई है।

याचिका में जंगल में आग के मामलों की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही एक जीवित व्यक्ति के अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक अलग व्यक्तित्व वाले कानूनी संस्थाओं के रूप में पशु साम्राज्य की घोषणा करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए की टिप्पणी
- वन संपदा व वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग

याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देश का एक प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र है, लेकिन संबंधित विभागों ने जंगल की आग से निपटने के उपायों पर संबंधित विभागों ने इस केंद्र से कभी सलाह नहीं ली। इससे जंगल की आग के प्रति संबंधित विभागों के लापरवाह रवैया का पता चलता है। जंगलों में बीते काफी दिनों तक आग लगी रही। इससे वन्य जीवों की मौत के साथ ही वन संपदा को भी नुकसान पहुंच रहा है।

39 मजदूर सऊदी अरब से स्वदेश लौट आए हैं। ये मजदूर एक साल से सऊदी में फंसे थे और बिना वेतन के काम कर रहे थे। सभी तेलंगाना के रहने वाले हैं। इनमें से अधिकांश करीमनगर, निर्माल, निजामाबाद और आदिलाबाद जिले के निवासी हैं।

न्यूज गैलरी

बीकानेर की गोशाला में जहरीला चारा खाने से 62 गायों की मौत

जयपुर : राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित दुलचासर गोशाला में जहरीला चारा खाने से 62 गायों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्रीडूंगरगढ़ तहसील में स्थित दुलचासर गोशाला में रविवार रात को गायों को जो चारा दिया गया था, उसमें जहरीला पदार्थ मिला होने के कारण गायों की तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलने के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन 62 गायों को बचाया नहीं जा सका। वेटरनरी यूनिवर्सिटी से भी पशु चिकित्सा विशेषज्ञों का दल मौके पर पहुंचा और बीमार गायों का उपचार किया, मगर उनको भी कामयाबी नहीं मिली। गोशाला में 300 से ज्यादा गायें हैं। (जासं)

ओलंपियन बॉक्सर रहे इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, होगी जांच

सिरसा : होटल प्रबंधक से दुर्व्यवहार करने के मामले में ओलंपियन बॉक्सर रहे इंस्पेक्टर जयभगवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अर्जुन अवार्डी जयभगवान के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के सिरसा में रविवार रात को अनाजमंडी स्थित एक होटल में कमरे को लेकर इंस्पेक्टर जयभगवान व होटल प्रबंधक के बीच विवाद हो गया था। विवाद की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले को लेकर सोमवार को होटल प्रबंधक एसएसपी डॉ. अरुण सिंह से मिले थे, जिसके बाद जयभगवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। हालांकि, इंस्पेक्टर जयभगवान ने आरोपों को झूठा बताया था। (जासं)

शिल्पा शेट्टी और गोविंदा के खिलाफ सुनवाई पांच को

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता की अदालत ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी व अभिनेता गोविंदा के मामले में अंतिम सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तिथि निर्धारित की है। हालांकि इस दौरान अदालत की ओर से दी गई अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। दोनों की ओर से निचली अदालत द्वारा जारी वारंट को चुनौती दी गई है। 1996 में रिलीज हुई फिल्म छोटे सरकार के गीत को लेकर एमएम तिवारी ने पाकुड़ की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि इस गाने की वजह से बिहार की बदनामी हुई है। इस पर अदालत ने इनको हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। (राब्यू)

बिहार में एईएस से आठ और बच्चों ने तोड़ा दम

थम नहीं रहा कहर ▶ अब तक 140 की जा चुकी है जान, 39 नए मरीज किए गए भर्ती

सिर्फ मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में 120 मासूम मरे

जागरण टीम, पटना

बिहार में एईएस (एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम) से मंगलवार को आठ और बच्चों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में चार, बेगूसराय में दो, सिवान और बांका में एक-एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में एईएस का कहर जारी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच 39 नए मरीजों को इलाज के लिए लाया गया। इनमें श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में 30 और केजरीवाल अस्पताल में नौ मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनमें आधा दर्जन से अधिक की हालत गंभीर है। मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में 120 बच्चों की मौत हो चुकी है। 443 बच्चों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है। पूरे बिहार में मंगलवार तक 140 बच्चों की मौत की सूचना है।

एसकेएमसीएच में बनेगा ढाई हजार बेड का हॉस्पिटल : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच का दौरा कर एईएस से पीड़ित सभी बच्चों का हाल लिया। उन्होंने यहां 2500 बेड वाला हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की। वर्तमान में यहां छह सौ बेड हैं। एसकेएमसीएच परिसर में फिलहाल बच्चों के लिए 50 बेड का पीडिएट्रिक आइसीयू है, जिसे बढ़ाकर सौ किया जाएगा। वहीं बुधवार से उन इलाकों में सर्वे का काम आरंभ किया जाएगा जहां एईएस से बच्चों की मौत हुई है। इस क्रम में संबंधित बच्चे के परिजनों की आर्थिक स्थिति, उनके आसपास का पर्यावरण और स्वच्छता आदि का आकलन होगा। यह निर्देश भी दिया कि निजी वाहन या प्राइवेट एंबुलेंस से भी बच्चे को अस्पताल लाने वाले को चार सौ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री व अन्य के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद : एईएस से मर रहे बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षबर्द्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सहित अन्य को आरोपित बनाया है।

आरोप लगाया गया है कि सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाएं केंद्रीय व राज्य प्रयोगशालाओं से जांच रिपोर्ट मिले बिना ही मरीजों को दी जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवाओं की आपूर्ति की जाती है। इसकी पोटेंसी सामान्यतः छह माह होती है। जबकि, इसका उपयोग एक से दो साल तक किया जाता है। आरोप लगाया गया है कि यह आम लोगों के जीवन के लिए घातक है।

एसकेएमसीएच में एईएस पीड़ित बच्चे को देखते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व अन्य। जागरण

बिहार में बुखार से बच्चों की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बिहार में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से हो रही बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दाखिल हुई, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार को बच्चों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम करने संबंधी निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। इस याचिका पर बुधवार को कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग भी हो सकती है।

याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार बीमारी को फैलने से रोकने में नाकाम रही है। इसलिए, कोर्ट और केंद्र सरकार मामले में दखल दे। कोर्ट से आग्रह किया गया है कि राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे प्रभावितों के इलाज के लिए बिहार में करीब 500 आइसीयू और मोबाइल आइसीयू की व्यवस्था करें। साथ ही बिहार सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह निजी अस्पतालों को बीमार बच्चों का मुफ्त में इलाज करने करने का आदेश जारी करे। यह भी मांग की गई है कि इस बीमारी से जिन बच्चों की मौत हो गई है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

मालूम हो कि बिहार में एईएस ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसके कारण अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है।

लीची को बदनाम करने की साजिश नहीं है एईएस से कोई संबंध

जासं, मुजफ्फरपुर

- चिकित्सकों ने कहा, लीची से इस बीमारी का कोई लेना-देना नहीं
- एसकेएमसीएच के रिकॉर्ड में भी लीची पर नहीं उठ रही उंगली

लीची मुजफ्फरपुर की पहचान है। यहां इसका इतिहास लगभग दो सौ साल पुराना है। पिछले 16-17 सालों से एईएस सामने आ रहा है। ऐसे में एईएस का लीची कनेक्शन हो, यह किसी के गले नहीं उतर रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ व मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जेपी मंडल कहते हैं कि लीची से इस बीमारी का कोई संबंध नहीं है। यह बीमारी लीची में फल आने से दो-तीन माह पहले व फसल समाप्त होने के दो माह तक सामने आती है। ऐसे में लीची को दोष देना कहां तक उचित है। यह वायरल डिजीज है। हो सकता है कि लीची या इसके आसपास के बगीचों में किसी खास समय इसके वायरस पनपते हों। अभी तक इसकी पहचान नहीं की गई है। दूसरे जिले में भी तो लीची के बगीचे हैं और वहां भी तापमान इतना ही रहता है। ऐसे में इसे दावा के साथ नहीं कहा जा सकता है। मुजफ्फरपुर स्थित केजरीवाल अस्पताल के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. चैतन्य कुमार कहते है कि बीमार बच्चों की केस हिस्ट्री में किसी ने भी लीची खाने की बात नहीं बताई।

मैंगो लॉबी की साजिश : जिले के प्रमुख लीची उत्पादक किसान भोलानाथ झा आरोप लगाते हैं कि सब मैंगो (आम) लॉबी की साजिश है। दूसरे प्रदेशों के बाजार में आम 10 से 15 रुपये किलो बिकता है। वहीं, लीची 200 से 250 रुपये किलो। इसके जूस दुनिया भर में बिकते हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। लीची की खेती व व्यवसाय को हतोत्साहित करने के लिए एक साजिश के तहत भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देहाती क्षेत्र से ज्यादा शहरी क्षेत्र के लोग लीची खाते हैं, लेकिन बीमार में सब के सब देहाती क्षेत्र के हैं। वह कहते हैं कि लीची चीन, थाइलैंड व अमेरिका सहित कई अन्य देशों में उत्पादित होता है। अगर इससे एईएस होता तो वहां भी यह बीमारी सामने आती। मुजफ्फरपुर की लीची देश के विभिन्न भागों में बेची जाती है। वहां खाने वाले बच्चे भी तो बीमार होते।

जांच में भी सही पाई गई लीची : राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विशालनाथ कहते हैं कि जांच में लीची पूरी तरह सही निकली। इसमें बीमारी का कोई तत्व नहीं मिला है। यहां की लीची काफी बेहतर व स्वास्थ्यवर्द्धक है। इसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।

छोड़ रहे गांव... ताकि जिंदा रह सकें नौनिहाल

अजय पांडेय, मुजफ्फरपुर

- वैशाली के भगवानपुर-हरिवंशपुर गांव में पसरा सन्नाटा, अधिकतर लोगों ने छोड़ा गांव

सन्नाटा, वीरानी और खामोश चहारदीवारी। हर राह पर मौत की पहरेदारी। न कोलाहल, न ही किलकारी। आंखों में गम, खौफ और 'पानी'। कभी नौनिहालों से गुलजार थीं गलियां, अब शेष हैं उनकी निशानी। वैशाली के भगवानपुर-हरिवंशपुर का यह मंजर, गांव की पीड़ा बयां करता है। एईएस ने इस कदर कहर बरपाया कि लोग घर-बार तक छोड़ने को विवश हो गए। इस मौसम में एक के बाद एक कर 10 से अधिक बच्चों की मौत से गांव के लोग सदमे में हैं। कब क्या हो जाए, क्या पता...। हर किसी के चेहरे पर बीते कल का दर्द, आज का खौफ और आनेवाले कल की चिंता। क्योंकि, बीमारी गांव की दहलीज पर कुंडली मारे बैठी है।

दस जून को सात साल की बेटी रूपा कुमारी को खो चुके राजेश सहनी कहते हैं कि गांव के लोग डरे-सहमे हैं। जिनके बच्चे बीमारी से उबर गए या पहले से ठीक हैं, वे गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहां जा रहे। यहां रहकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते।

सभी घर फूस और एस्बेस्टस के : विजय सहनी बताते हैं कि गांव में 50 से अधिक परिवार हैं। यहां के लोग बांस का काम और मजदूरी कर जैसे-तैसे घर चलाते हैं। सभी के घर खपड़ैल और फूस के हैं। कुछ लोगों ने एस्बेस्टस भी डाला है। प्रचंड गर्मी में घर भट्ठी बने हैं। पानी की घोर किल्लत है। ऐसे में बीमारी का प्रकोप। अब गांव छोड़ें नहीं तो क्या करें? अरविंद सहनी, देवानंद सहनी, परमानंद सहनी जैसे कई के घरों में सन्नाटा है। ये लोग घर छोड़कर बाहर चले गए हैं। उन्हीं घरों में लोग नजर आते हैं, जिनके यहां बच्चे नहीं।

मौत की कहानी हर ओर : सात साल का बेटा खोने का गम चतुरी सहनी को कचोट रहा है। कहते हैं प्रिंस हर रोज की तरह खेल कर आया था, अचानक चमकी हुई और तबीयत बिगड़ गई। सूई-दवा भी काम न आई, आठ जून को देखते-देखते उसने दम तोड़ दिया। चतुरी की पीड़ा हमें झकझोर ही रही थी। वहीं बैठे विजय सहनी कहते हैं, गांव में कहीं भी चले जाएं, बच्चों की मौत की कहानी हर ओर है। बाद में पता चला कि दो रोज पहले ही उनकी बेटी की बीमारी से मौत हो चुकी है। रामदेव सहनी कहते हैं कि सर, गिनती भूल जाएंगे, इतने बच्चों की मौत हुई है यहां। उनकी भी एक बेटी की हाल में मौत हुई है। नंदू सहनी बताते हैं कि उनके तीन बच्चे बीमार हैं, महावीर सहनी के भी दो बच्चों का इलाज चल रहा।

भीषण गर्मी और लू ने ली 41 और की जान, अब तक 285 की मौत

जागरण टीम, पटना

बिहार में भीषण गर्मी और लू चौथे दिन भी जानलेवा साबित हुई। मंगलवार को बिहार के विभिन्न जिलों में 41 लोगों की मौत हो गई। मगध और शाहाबाद में 14, भागलपुर में 4, जमुई और मुंगेर में 2-2, बांका में 3, वैशाली, भोजपुर, नालंदा, छपरा और कटिहार में 16 की जान गई। शनिवार से अब तक सूबे में 285 की मौत हो चुकी है। शनिवार को 60, रविवार को 118, सोमवार को 66 की जान गई थी। दर्जनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 165 मर्जी अभी भी भर्ती हैं, जिनमें 21 नए मरीज आए हैं। औरंगाबाद में भी करीब सौ मरीज भर्ती हैं। सासाराम और नवादा में भी करीब सौ मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। मगध मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विजय कृष्ण प्रसाद ने बताया कि अभी तक जो भी मरीज हैं, वे लू का ही शिकार हैं।

तेज गर्मी और लू के कारण प्रभावित क्षेत्रों में दिन के 11 बजे से चार बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, कई दुकानें खुली थीं, पर इक्का-दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहे थे। दोपहर के समय आसमान में हल्के बादल भी दिखे।

रावी पर लकड़ी का पुल सेना का ट्रक गुजरते वक्त टूटा, जवान बचे

- पाकिस्तान के साथ लगती सीमा की ओर ट्रक से जा रहे थे आठ सैनिक
- ट्रक का अगला हिस्सा रावी में लटका, तीन घंटे में बाहर निकाला

बॉर्डर के पास गुरदासपुर के मकौड़ा पत्तन स्थित रावी दरिया का पुल टूटने से सेना की गाड़ी नदी में गिर गई। जेसीबी से गाड़ी निकालते लोग। जागरण

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर

गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन में रावी दरिया पर बना लकड़ी का पुल सेना का ट्रक गुजरते वक्त मंगलवार दोपहर को अचानक टूट गया। ट्रक का आधा हिस्सा रावी में लटक गया। तिबड़ी कैंट से चले सेना के इस ट्रक में आठ जवान सवार थे, जो सीमा पर जा रहे थे। हादसे में सभी जवान बाल-बाल बच गए। स्थानीय लोग भी सैनिकों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। तीन घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला गया।

मकोड़ा पत्तन गुरदासपुर से 13 किलोमीटर दूर है। रावी दरिया के पार पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर नजर रखने के लिए सेना और बीएसएफ अक्सर दरिया पार जाती है। रावी के पार रहने वाले आठ गांवों के लोग आजादी के बाद से पक्के पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बरसात में जब रावी दरिया उफान पर होता है तो आठ गांवों के लोगों का संपर्क देश से टूट जाता है। रावी पर लकड़ी का पुल अक्टूबर में बनाया जाता है और जून के अंत में हटा लिया जाता है। जुलाई से सितंबर तक लोग किश्ती से ही दरिया पार करते हैं।

पीडब्ल्यूडी ने की पुल की मरम्मत : पुल टूटने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मंगलवार शाम को मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। पीडब्लूडी के एसडीओ नरेश कुमार का कहना है कि पुल अब उठा लिया जाएगा। जून तक ही इसकी समय सीमा होती है। अब दरिया में किश्ती चलेगी।

सैनिकों को नुकसान नहीं : डीसी

गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल का कहना है कि सेना की गाड़ी दरिया में लुढ़की थी। किसी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ है। पुल की मरम्मत के आदेश दे दिए गए हैं।

झारखंड में दिनदहाड़े अगवा कर विधवा से सामूहिक दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, हजारीबाग : प्रसव पीड़ा के बाद अपनी भाभी को सदर अस्पताल लेकर आई विधवा को मेन रोड से दिनदहाड़े अगवा कर लिया गया। इसके बाद चार लोगों ने बोलेरो वाहन में सामूहिक दुष्कर्म किया।

सोमवार सुबह करीब आठ बजे मेन रोड स्थित पानी टंकी के समीप से विधवा का अपहरण किया गया था। दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद उससे मारपीट की। अधमरा होने पर उसे कटकमदाग थाना क्षेत्र सुल्ताना में फेंककर भाग गए। दुष्कर्म की जानकारी मंगलवार सुबह नौ बजे पुलिस को मिली जब सुल्ताना के ग्रामीणों ने पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बेसुध पीड़िता को शाम करीब चार बजे होश आया और इसके बाद उसका फर्द बयान हुआ। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि लाल रंग की गाड़ी से आए अपराधियों ने पता पूछने के बहाने मेन रोड स्थित पानी टंकी के समीप रोका और गाड़ी में खींच ले गए। वाहन में चारों ओर पर्दा लगा था, सभी आरोपित मुंह बांधे हुए थे। हालांकि, उसने यह कहा है कि वह चालक को देखकर चेहरे से पहचान कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

12 जून को भाभी को लेकर आई थी सदर अस्पताल: चतरा की रहने वाली पीड़िता 12 जून को अपनी भाभी को प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल लेकर आई थी। 17 को उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। छुट्टी से पूर्व वह होटल से मिठाई लेकर आ रही थी, इस दौरान यह कार सवार आए बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

इंडियन ऑयल के नाम पर वायरल हो रही है फर्जी चेतावनी

विश्वास. News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: इंडियन ऑयल के नाम पर एक फर्जी मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैसेज में इंडियन ऑयल की ओर से कथित दावा किया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के कारण अपने वाहन में सीमा से ज्यादा पेट्रोल न भरवाएं। वरना विस्फोट हो सकता है। विश्वास टीम की पड़ताल में यह मैसेज फर्जी साबित हुआ। इंडियन ऑयल ने ऐसी कोई भी चेतावनी जारी नहीं की है।

पड़ताल: विश्वास न्यूज की टीम ने सबसे पहले इंडियन ऑयल की वेबसाइट https://www.iocl.com/ को स्कैन करना शुरू किया। हमें इसके होम पेज पर एक अनाउंसमेंट दिखा। इसमें साफतौर पर इस बात का उल्लेख किया गया था कि सोशल मीडिया में एक अफवाह उड़ रही है, जिसमें इंडियन ऑयल की ओर से चेतावनी की बात कही जा रही है। मैसेज में लिखा गया है कि ऑटोमोबाइल निर्माता अपने वाहनों को परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तैयार करते हैं। फुल लिमिट तक वाहनों में पेट्रोल या डीजल डलवाना पूरी तरह सेफ है।

इसके बाद टीम ने InVID टूल की मदद से इंडियन ऑयल के ट्विटर हैंडल @IndianOilcl को स्कैन किया। यहां हमें 16 जून 2018 को किया गया एक ट्वीट मिला। इसमें भी यही बात कही गई है कि वाहनों में फुल लिमिट तक पेट्रोल भरवाना सेफ है। चेतावनी वाले इस ट्वीट को पिछले साल भी किया गया था।

अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम इंडियन ऑयल के फेसबुक पेज पर पहुंचे।

वहां कई पोस्ट को स्कैन करने के बाद हमें इंडियन ऑयल की चेतावनी से जुड़ी एक पोस्ट मिली। इस पर भी वही कटेंट था, जो इंडियन ऑयल की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल पर मौजूद था। इसे 27 अप्रैल 2019 को पोस्ट किया गया था। इंडियन ऑयल की ओर से लगातार उस अफवाह का खंडन किया जा रहा है, जो उसके नाम पर लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है। इसके बाद हमने इंडियन ऑयल के मुख्यालय में संपर्क किया। वहां से हमें जानकारी मिली कि पिछले कुछ सालों से लगातार एक ही अफवाह हर गर्मी में फैलाई जाती है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अंत में हमने फर्जी चेतावनी वाले मैसेज को वायरल करने वाले फेसबुक पेज RTI Club Uttarakhand को स्कैन किया। देहरादून से संचालित होने वाले इस पेज को 2248 लोग फॉलो करते हैं।

क्या है वायरल मैसेज में

RTI Club Uttarakhand नाम के फेसबुक पेज ने इंडियन ऑयल की कथित चेतावनी वाली पोस्ट को अपलोड किया है। इसके अलावा भी कई यूजर्स फेसबुक, Twitter और WhatsApp पर इस फर्जी मैसेज को फैला रहे हैं। वायरल हो रहे मैसेज में लिखा, 'आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होना तय है, इसलिए अपने वाहन में पेट्रोल अधिकतम सीमा तक ना भरवायें। यह ईधन टैंक में विस्फोट का कारण बन सकता है। कृपया आप अपने वाहन में आधा टैंक ही ईधन भरवायें और एयर के लिए जगह रखें। इस हफ्ते 5 विस्फोट दुर्घटनाओं की वजह अधिकतम पेट्रोल भरना रही है। कृपया पेट्रोल टंकी को दिन में एक बार खोलकर अंदर बन रही गैस को बाहर निकलने दे।'

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 293

रहें सतर्क

उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण चारधाम यात्रा मार्गों पर हृदय रोग से होती हैं सर्वाधिक मौत, केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्रा सबसे चुनौतीपूर्ण, केदारनाथ में ऑक्सीजन का लेवल सबसे कम

यात्री चारधाम यात्रा के दौरान रखें 'दिल' का विशेष ख्याल

जागरण संवाददाता, देहरादून

आप उत्तराखंड हिमालय में चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो दिल का विशेष ख्याल रखें। कमजोर दिल वालों के लिए तो यात्रा से परहेज बरतने में ही भलाई है। कारण यह कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण चारधाम यात्रा मार्गों पर हृदय रोग से सर्वाधिक मौतें होती हैं। इस साल भी यह सिलसिला थमा नहीं है और सात मई से अब तक 51 यात्री चारों धाम में दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि चारधाम यात्रा पर (खासकर केदारनाथ व यमुनोत्री) आने वाले श्रद्धालु अपनी सेहत, खासतौर पर दिल का ख्याल रखें, ताकि यात्रा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके।

चारधाम यात्रा रूट के अधिक ऊंचाई पर होने के कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित यात्रियों की तबीयत बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। कारण यह भी है कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में यात्रा करने से पहले तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने जरूरी हैं। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एसके झा का कहना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर केदारनाथ में ऑक्सीजन की कमी और लगातार चढ़ाई में रक्तचाप अनियमित होने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में हृदय रोगियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉ. झा के अनुसार इस बार केदारनाथ में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे यात्रा के दौरान अब तक 400 से अधिक ऐसे यात्रियों की जान बचाने में स्वास्थ्य विभाग ने सफलता हासिल की, जिनकी समय पर उपचार न मिलने से जान भी जा सकती थी।

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी के सीएमओ डॉ. डीपी जोशी का कहना है कि यात्री को अगर चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो उसे जबरन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि वह यात्रा ही स्थगित कर दे, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क जीवन पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा यात्रियों को दवाओं की इमरजेंसी किट भी साथ में रखनी चाहिए। खासकर शुगर, सीने में दर्द, हृदय रोग व ब्लड प्रेशर की शिकायत वाले यात्री दवाएं साथ ले जाना न भूलें। डॉ. जोशी बताते हैं कि वर्तमान में पूरे उत्तरकाशी जिले में सिर्फ जिला अस्पताल में ही फिजिशियन की तैनाती है, लेकिन वह इन दिनों अवकाश पर हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ जिले में कहीं नहीं है। अलबत्ता, जानकीचट्टी, यमुनोत्री व गंगोत्री में चिकित्सक तैनात हैं और यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

सबसे ज्यादा चुनौती केदारनाथ में : समुद्रतल से 11654 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में मौसम पल-पल बदलता रहता है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहां ऑक्सीजन का लेवल भी 60 प्रतिशत के आसपास है। इससे यहां यात्रियों को सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, दिल की धड़कन बढ़ने व चक्कर आने की आशंका बनी रहती है। गौरीकुंड से भीमबली तक तो पेड़-पौधे होने के कारण वातावरण काफी अनुकूल है। लेकिन, इससे आगे हवा का दबाव बहुत कम रहता है, जिससे यात्रियों को ऐसी दिक्कत पेश आती हैं।

उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बदरीनाथ में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में यात्रियों को दिल संबंधी तकलीफों से रहना होगा सतर्क। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ का नजारा। जागरण

यात्रियों को चिकित्सकों की सलाह

- 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के यात्री विभिन्न पड़ावों पर स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं।
- पैदल की बजाय घोड़ा-खच्चर या पालकी का उपयोग करें।
- यात्रा के बीच में कुछ देर के लिए आराम अवश्य करें।
- पर्याप्त संख्या में गर्म कपड़े अपने पास रखें।
- बर्फ व बारिश में भीगने से बचें।
- हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, श्वास के रोगी बिना डॉक्टर के परामर्श के यात्रा न करें।
- न तो खाली पेट यात्रा करें, न तला हुआ भोजन ही लें। इससे गैस की समस्या हो सकती है।

हेलीकॉप्टर न मिलने से बीमार यात्री की केदारनाथ में मौत

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा पर आए दो यात्रियों की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। इनमें से एक यात्री गोरगांव (मुंबई) निवासी विनोद व्यास (51) की तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे गुप्तकाशी लाने के लिए हेली सेवा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। लेकिन, 45 मिनट तक हेली कंपनी उन्हें टालती रही, जिससे यात्री ने हेलीपैड पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस के एक अधिकारी और हेली कंपनी के स्टाफ के बीच विवाद हो गया। माहौल इस कदर गरमाया कि उक्त अधिकारी ने हेली कंपनी के स्टाफ पर थप्पड़ जड़ दिया। विरोध में हेली कंपनियों ने तीन घंटे तक हेली सेवाएं बंद रखीं। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर ही हेली सेवाएं शुरू हो पाईं।

दूसरी ओर, बांकुरा (पश्चिम बंगाल) के एक यात्री ने भी हृदयगति रुकने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल से 18 यात्रियों का दल पैदल मार्ग से केदारनाथ जा रहा था। इस बीच बांकुरा के गौरचंद्र मुखर्जी की मौत हो गई।

Downloaded from: www.iascgl.com

दैनिक जागरण

मन और विचारों की पवित्रता से ही मनुष्य सद्कर्म करता है

भ्रष्ट अफसरों की छुट्टी

आयकर विभाग के एक दर्जन अधिकारियों की छुट्टी करने के बाद जिस तरह केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के 15 अफसरों को जबरन रिटायर किया गया उससे यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरतने का सिलसिला आगे भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि टैक्स से संबंधित विभागों के अलावा केंद्र सरकार के अन्य विभागों में भी ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं। आखिर यह एक तथ्य है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग करीब 120 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी अधिकारी हैं और बैंकों के अफसर भी। यह ठीक नहीं कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरे अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई धीमी गति से हो। यह काम तो आनन-फानन किया जाना चाहिए। इससे ही भ्रष्ट अधिकारियों के बीच कोई सही संदेश जाएगा और वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से बाज आएंगे। भ्रष्ट अधिकारी एक दिन भी अपने पद पर नहीं रहने चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया उनमें से कई ऐसे हैं जिन पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप थे। इनमें कुछ निलंबित भी चल रहे थे। इसका मतलब है कि उनके खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई धीमी गति से ही आगे बढ़ रही थी। यह ठीक है कि जिन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया उनके खिलाफ दर्ज मामले अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें अपने किए की सजा जल्द मिले।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारियों को जिस नियम के तहत हटाया गया वह यह कहता है कि सरकार एक समय सीमा के बाद ही भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। स्पष्ट है कि उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के उपाय खोजने होंगे जो सेवा में आने के कुछ समय बाद ही रिश्वतखोरी अथवा अन्य अनुचित कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। यह जरूरी है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती की जाए जो अपनी संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देते या फिर आनाकानी करते हैं। इस सबके अलावा सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर टैक्स से संबंधित विभागों के अधिकारी इतनी आसानी से मनमानी कैसे कर ले रहे हैं? बेहतर हो कि उनके विवेकाधिकारों को परिभाषित करने के बारे में सोचा जाए। ऐसी भी कोई व्यवस्था करनी होगी जिससे जहां भ्रष्ट अधिकारी किसी तरह का संरक्षण न हासिल कर सकें वहीं ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन मिले। इसके लिए आवश्यक हो तो नियम-कानूनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि नौकरशाही में समग्र सुधार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी तो राज्यों की सेवाओं में भी हैं और यह एक तथ्य है कि केंद्रीय स्तर पर भले ही लोकपाल व्यवस्था बन गई हो, लेकिन राज्यों के स्तर पर सक्षम लोकायुक्त व्यवस्था का निर्माण अभी भी नहीं हो सका है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि नौकरशाही में व्यापक सुधार के कदम उठाए जाएं।

हड़ताल की समाप्ति

कोलकाता के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट के खिलाफ सात दिनों तक चली उनकी हड़ताल आखिरकार सातवें दिन खत्म हुई तो राज्य एवं केंद्र प्रशासन समेत आम लोगों से लेकर अन्य चिकित्सकों तक ने राहत की सांस ली। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा सिर्फ बंगाल में ही नहीं कई राज्यों में चरमरा गई थी। पिछले सात दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर जमकर सियासत हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चेतावनी के बाद स्थिति और गंभीर हो गई थी, परंतु आखिरकार जब सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री एवं जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई तो सारी समस्या सुलझ गई। डेढ़ घंटे की बैठक में मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी डॉक्टरों की सारी मांगें मानते हुए ड्यूटी के दौरान उनकी पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। सुरक्षा के बाबत उन्होंने प्रत्येक सरकारी अस्पताल में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की भी घोषणा की। ममता ने उनकी अन्य शिकायतें एवं समस्याएं भी ध्यान से सुनीं। बैठक के बाद एनआरएस अस्पताल लौटकर जूनियर डाक्टरों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की और राज्यभर में आंदोलन कर रहे अपने साथियों से जल्द से जल्द काम पर लौटने की अपील की, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य होने लगीं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में भर्ती हमले में जख्मी डॉक्टर परिबाह मुखर्जी से भी जाकर मिलीं और उनका हालचाल पूछा। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मसले के समाधान को मुख्यमंत्री एवं जूनियर डॉक्टरों की ओर से की गई पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि राज्य सरकार बैठक में लिए गए सारे फैसलों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगी और डॉक्टर भी उच्च आदर्शों के साथ मरीजों की देखभाल करेंगे, परंतु एक सवाल यहां यह उठ रहा है कि हड़ताल के बाद ही सुरक्षा का वादा क्यों किया गया? यदि यह सब इंतजाम पहले से ही हो गया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आई होती?

बाधा बनते बार-बार होने वाले चुनाव

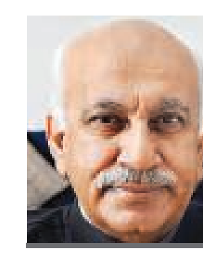

एमजे अकबर

हर पांच साल में चार महीने चुनावों के लिए आवंटित किए जा सकते हैं और शेष 56 माह लोकतंत्र के आधार यानी जनता की सेवा को समर्पित किए जा सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को कितना समय बीता? इस सवाल पर अगर आपका जवाब पांच वर्ष है तब आप संवैधानिक रूप से सही, लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। वास्तविक रूप से देखें तो किसी प्रधानमंत्री के पांच वर्षों के कार्यकाल में तकरीबन डेढ़ साल तो चुनाव प्रचार अभियान में खर्च हो जाते हैं। यदि चुनाव का कैलेंडर पहले से निर्धारित हो और उसे योजनाबद्ध ढंग से मूर्त रूप दिया जाए तो चुनाव अभियान की यह अवधि तीन से चार महीनों में सिमट सकती है। इससे सामान्य राज-काज के लिए वास्तविक रूप से एक साल का वक्त और मिल जाएगा। इसकी पुष्टि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान के घटनाक्रम का विश्लेषण किया जा सकता है। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में लालकिले की प्राचीर से उन्होंने अपना पहला भाषण बमुश्किल खत्म ही किया होगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव का बिगुल बज गया और उन्हें प्रचार अभियान में अग्रिम मोर्चा संभालना पड़ा। उनके कार्यकाल के अंत तक आते-आते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रण शुरू हो गया। इसके कुछ महीनों बाद ही आम चुनाव का आगाज हो गया। इस बीच बिहार, बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों की राजनीतिक जरूरतें भी सामने आती रहीं।

सैद्धांतिक रूप से विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों पर प्रभाव नहीं डालते। हालांकि राज्यसभा में संख्याबल के लिहाज से इसका अपना नफा-नुकसान होता है, मगर व्यावहारिक रूप में शासन की गति और रूपरेखा पर उसका अहम प्रभाव होता है। सुशासन केवल फाइलों तक सिमटी हुई योजनाओं से नहीं सुनिश्चित होता, बल्कि उन योजनाओं के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन से संभव होता है। हमारे संघीय ढांचे के कई दिलचस्प पहलू हैं। उनमें से एक तो यही है कि इस ढांचे के सबसे सशक्त भाग यानी केंद्र सरकार भारत के किसी बड़े भूभाग पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती। केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण उन छिटपुट संघ शासित प्रदेशों तक सीमित है जिन्हें बस भ्रम ही कहा जा सकता है। भारत राज्य सरकारों द्वारा शासित होता है। हालांकि केंद्र अपनी खुद की राष्ट्रव्यापी नीतियों को लेकर पहल कर सकता है, लेकिन उनके व्यापक प्रबंधन का काम राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। यह असमान विकास की एक वजह हो सकती है, लेकिन इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम एक परिसंघ हैं और इसका स्वरूप इसी प्रकार होना चाहिए।

अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी उन समस्याओं से भलीभांति परिचित थे जिनका सामना उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया था। इसके चलते जीएसटी जैसे क्रांतिकारी सुधार में राजस्व को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई उलझन फंसी भी तो उसे कुशलतापूर्वक सुलझा लिया गया। अनुभव यही दर्शाते हैं कि विकास की धारा तभी तेज हुई जब केंद्र और राज्य दोनों में सद्भाव कायम रहा। ऐसा सद्भाव सदैव संभव है। तब भी जब केंद्र और राज्य दोनों में अलग-अलग दलों की सरकार हो, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को वरीयता दे, मगर वर्ष 2014 में जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन-प्रशासन के मामले में दलगत राजनीति कभी आड़े नहीं आ सकती। सहभागिता और गतिशील विकास ही वह पैमाना होना चाहिए जो एक साझा लक्ष्य के लिए सभी चुने हुए नेताओं को जोड़ने वाली कड़ी बने। इसमें जनता और राष्ट्र को प्राथमिकता मिले। हमारे समक्ष चुनौतियों की गंभीरता को देखते हुए कोई भी हार गवारा नहीं कर सकता।

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नए भारत का सपना साकार करना चाहते हैं जिसमें भयावह गरीबी पूरी तरह मिट गई हो और जहां आर्थिक वृद्धि का प्रतिफल सभी तबकों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत के आर्थिक शासन-प्रशासन में भूखे-गरीबों और निःशक्तों में से किसी को या फिर दोनों को ही छोड़ दिया जाता था। मगर मोदी के निर्णायक कदमों ने गरीबों को सहभागी विकास का एक और इंजन बना दिया है। इसमें जन धन और मुद्रा योजना के जरिये पूंजीगत मदद से उनकी क्षमताओं में सुधार हो रहा है।

यह नहीं कहा जा सकता कि पहले सत्ता में रहे नेताओं के इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी भली मंशा के बावजूद अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाए। तंत्र की सुस्त रफ्तार और निष्प्रभावी तौर-तरीके लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। भारत की सबसे गरीब एक चौथाई आबादी अभी भी अपनी अगली खुराक को लेकर अनिश्चितता से जूझती है। वह अपने अस्तित्व के संकट से जूझने में लगी है। इस साल चुनाव में मतदान करने वालों ने वह महसूस किया जिसे स्वयंभू राजनीतिक पंडित नहीं भांप पाए कि एक मजबूत नेता को मजबूत सरकार के लिए संख्याबल भी चाहिए। दूसरे कार्यकाल में त्वरित और नए तौर-तरीकों वाली शुरुआत दर्शाती है कि पीएम मोदी मतदाताओं विशेषकर युवाओं द्वारा उनके कंधों पर सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर कितने गंभीर और सचेत हैं। महज एक निर्णय के माध्यम से वह बीते सत्तर वर्षों में कहीं बड़े प्रशासनिक सुधार का सूत्रपात कर चुके हैं। इस निर्णय के तहत केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के 40 प्रतिशत पदों पर आइएएस सेवा से इतर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। यह एक ऐसे संस्थान में सराहनीय परिवर्तन है जो स्वयं को किसी भी किस्म के बदलाव से बचाता आया है।

विपक्षी दल अक्सर किसी भी नए विचार का इस कारण विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्तारूढ़ दल ने अपने हितों को साधने के लिए इसे लागू किया है। मगर सभी चुनावों को एक साथ कराने का विचार नया नहीं है। यह हमारे संविधान में वर्णित सबसे पुराने विचारों में से एक है। वर्ष 1952 से 1967 के बीच यह सामान्य चलन था। यह विसंगति तब आनी शुरू हुई जब कांग्रेस 1967 में पंजाब से लेकर बंगाल तक राज्य विधानसभाओं के चुनाव हार गई। उनकी जगह लेने वाली संयुक्त मोर्चा सरकारें जनादेश का पालन करने में बुरी तरह नाकाम रहीं। इससे चुनावी कैलेंडर की तस्वीर बदल गई। कालांतर में यह कार्यक्रम और खंडित होता गया जब इंदिरा गांधी ने 1971 में समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया और बाद में तानाशाही के जरिये अपना कार्यकाल 1977 तक बढ़ा लिया। इस दशक में जो प्रावधान भूल सुधार के लिए बना था वही नया चलन बन गया। हम अभी तक उसके साथ अटके हुए हैं।

पीएम मोदी हमारे लोकतंत्र के मूल और व्यावहारिक स्वरूप को बहाल करने की कोशिश में जुटे हैं। हर पांच साल में चार महीने चुनावों के लिए आवंटित किए जा सकते हैं और शेष 56 माह लोकतंत्र के आधार यानी जनता की सेवा को समर्पित किए जा सकते हैं। वक्त आ गया है कि चुनावी विसंगति को संविधान की रूपरेखा और लक्ष्यों के अनुरूप सुसंगत किया जाए।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नकारात्मक राजनीति के नए संकेत

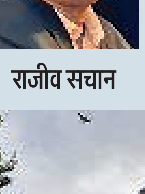

राजीव सचान

क्या विपक्ष यह समझेगा कि उसे तार्किक होने की जरूरत है, न कि संख्याबल के लिहाज से ताकतवर होने की?

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से यह एक स्वर बार-बार सुनाई दे रहा है कि अबकी बार विपक्ष बड़ा कमजोर है। इसी के साथ लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की महत्ता को भी रेखांकित किया जा रहा है। यह निराधार नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं जब सत्ताधारी दल के हिस्से में तीन सौ से अधिक सीटें दिख रही हों। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के समय 1967 को छोड़कर कांग्रेस ने जब भी सत्ता हासिल की उसने साढ़े तीन सौ से अधिक सीटें जीतीं। 1984 में तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटें हासिल की थीं। इस बार भाजपा ने अपने दम पर 303 और सहयोगी दलों के साथ साढ़े तीन सौ से अधिक सीटें हासिल की हैं। स्पष्ट है कि विपक्ष उतना कमजोर नहीं है जितना बताया जा रहा है। सच्चाई यह है कि आज का विपक्ष कमजोर कम, बल्कि बिखरा हुआ और अतार्किक अधिक है। इससे भी खराब बात यह है कि वह विरोध के लिए विरोध की मानसिकता से ग्रस्त है। यह मानसिकता नई नहीं है, लेकिन बीते करीब दो दशकों से यह अधिक देखने को मिल रही है। इसी मानसिकता के चलते 1998 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव का मूल कारण यह था कि वाजपेयी सरकार को समर्थन दे रहीं अन्नाद्रमुक नेता जयललिता नाराज होकर सोनिया गांधी के साथ चाय पीने चली गई थीं। इस चाय पार्टी के आयोजक-संयोजक थे सुब्रमण्यम स्वामी। वाजपेयी सरकार महज एक वोट से गिर गई थी। आज शायद ही किसी को पता हो कि यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? कुछ नेताओं की सनक के चलते मध्यावधि चुनाव हुए और वाजपेयी सरकार और अधिक सशक्त होकर सत्ता में लौटी। 2004 में वह अप्रत्याशित रूप से सत्ता से बाहर हो गई। उसने वादा तो यह किया कि वह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन कई अवसरों पर उसने नकारात्मक रवैये का ही परिचय दिया। इसका एक बड़ा प्रमाण तब मिला जब उसने अमेरिका से हुए परमाणु समझौते का विरोध करना शुरू कर दिया। इस समझौते के विरोध का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी भाजपा यही कहती रही कि यह समझौता देशहित में नहीं। यह पता नहीं कि परमाणु समझौते पर लोकसभा में मतदान के दौरान वोट के बदले नोट का जो सनसनीखेज मामला सामने आया उसके पीछे कौन था, लेकिन जो भी था उसका इरादा सरकार को गिराना था। कायदे से इस मामले की तह तक जाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं हो सका?

2009 में अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन फिर से सत्ता में आया तो इसका एक कारण बतौर विपक्ष भाजपा की नकारात्मक राजनीति थी। 2014 में कांग्रेस अपने खराब कर्मों से सत्ता से बाहर हुई। उसे महज 44 सीटें मिलीं। जब यह माना जा रहा था कि वह अपनी करारी हार पर ईमानदारी से आत्ममंथन करेगी तब वह इस नतीजे पर पहुंची कि जनता ने गलती कर दी है। पूरे पांच साल वह ऐसे व्यवहार करती रही जैसे गलती उसकी नहीं, बल्कि नासमझ जनता की है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पूरे पांच साल संसद के दोनों सदनों में हंगामा करने और टीवी कैमरों के सामने नारे लिखी तख्तियां दिखाने की कोशिश करती रही। उसके सांसद किसी मसले पर बहस के बजाय इसकी तैयारी करते दिखते रहे कि तख्तियों में क्या नारे लिखे जाएं और उन्हें सदन में इस तरह कैसे लहराया जाए कि वे टीवी कैमरों में आ जाएं? 2015 में संसद का वह मानसून सत्र याद करें जो ललित मोदी कांड के नाम पर बर्बाद कर दिया गया था। कांग्रेस इस मामले को किसी बड़े घोटाले की शक्ल देकर संसद के दोनों सदन बाधित किए रही। इसके बाद रह-रह कर सरकार के खिलाफ कथित गंभीर मसले खोजकर संसद के कामकाज को बाधित किए जाने की परंपरा को पुष्ट ही किया गया। यह काम राफेल सौदे को लेकर भी किया गया।

राहुल गांधी कभी भूकंप लाने की बात करते रहे और कभी यह डींग हांकते रहें कि प्रधानमंत्री उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। एक और करारी हार के बाद राहुल गांधी यह मान रहे हैं कि पार्टी के अन्य नेताओं ने चौकीदार चोर है नारे का इस्तेमाल उतने जोर-शोर से नहीं किया जितना उन्होंने किया। वह इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि मोदी नफरत के बल पर चुनाव जीत गए हैं। मोदी के खिलाफ राहुल की अभद्र भाषा की अनदेखी कर सोनिया गांधी यह कह रही हैं कि सत्ता के लिए मर्यादा का उल्लंघन किया गया। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर कम होने पर अपने कार्यकर्ताओं को यह चेतावनी दे डाली कि वह उनकी पहचान करेंगी जिन्होंने ढंग से मेहनत नहीं की। गांधी परिवार के सदस्यों के ऐसे बयानों को देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वैसे भी राहुल गांधी यह कह चुके हैं कि उनके 52 सांसद संसद में भाजपा को बच निकलने का मौका नहीं देंगे। बात केवल लोकसभा में ही विपक्ष के आचरण की नहीं है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि बीते पांच साल लोकसभा से पारित विधेयक किस तरह राज्यसभा में रोके जाते रहे?

राज्यसभा में विपक्ष अपने बहुमत का इस्तेमाल कुछ इसी भावना से करता दिखा जैसे जनता की कथित गलती को ठीक करने की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन मानते हुए यह कहा जाता है कि इस सदन में कहीं अधिक धीर-गंभीर होकर चर्चा की जाती है, लेकिन बीते पांच साल में इसका उलट देखने को मिला। लोकसभा से अधिक हंगामा राज्यसभा में हुआ। संसद में पक्ष-विपक्ष के बीच नोकझोंक और विवाद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध के लिए विरोध का कोई मतलब नहीं। मुश्किल यह है कि आज यदि चार सांसद भी ठान लें तो वे लोकसभा या राज्यसभा को पंगु बना सकते हैं। यदि हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की जाए तो गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर यह कहा जाने लगता है कि विपक्ष का मुंह बंद किया जा रहा है। एक समय विपक्ष जब वाकई बहुत दुर्बल हुआ करता था तब उसके पास राममनोहर लोहिया, पीलू मोदी, इंद्रजीत गुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी आदि ऐसे नेता होते थे जो अकेले ही सत्तापक्ष को कठघरे में खड़ा करने में समर्थ रहते थे। चंद्रशेखर के अवसान के बाद ऐसा कोई नेता नहीं दिखता। शरद पवार बुजुर्ग नेता अवश्य हैं, वह विपक्ष की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये तो नकारात्मक राजनीति के नए संकेत ही हैं। इसी कारण यह कहना कठिन है कि विपक्ष यह समझेगा कि उसे तार्किक होने की जरूरत है, न कि संख्याबल के लिहाज से ताकतवर होने की।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जैसे को तैसा

पुरानी कहावतें आज भी प्रासंगिक हैं। लोग अपनी सुविधा अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, खून के बदले खून आदि। लोगों को जब किसी व्यक्ति से चोट लगती है तो वे भी उसे चोट पहुंचाने की सोचते हैं। इसके लिए रणनीतियां बनाने लगते हैं, पर कभी भी बुराई से बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे को तैसे की भावना व्यक्ति को नीचे की ओर ही लेकर जाती है, क्योंकि किसी को छोटा दिखाने के लिए व्यक्ति को स्वयं को निचले स्तर पर लाना पड़ता है। व्यक्ति जब अपना अभिमान दिखाता है तो उसका स्वाभिमान स्वतः ही कम हो जाता है। स्वाभिमान का स्तर कम होने से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और संघर्ष उत्पन्न होने लगते हैं। किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार का बदला दुर्व्यवहार में देने वाले लोग उसके इर्द-गिर्द ही सोचते रहते हैं। उनका मस्तिष्क एक छोटे से केंद्र बिंदु तक आकर सीमित रह जाता है, जबकि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं उनके मस्तिष्क का विस्तार होता रहता है।

वे जीवन में नई-नई बातें सीखते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वे अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नामोनिशान मिट जाता है। कोई भी कार्य अथवा वस्तु व्यक्ति के जेहन में तब तक जीवित रहता है, जब तक व्यक्ति उसे अपने साथ लेकर चलता है। जैसे ही व्यक्ति उसे अपने मन मस्तिष्क से निकाल देता है, वैसे ही उसके लिए असीमित मार्ग खुल जाते हैं। जब एक व्यक्ति चिल्लाकर बात करता है तो दूसरा भी उससे अधिक चिल्लाकर जवाब देता है। यदि चिल्लाने वाले व्यक्ति की बात का जवाब धीमे स्वर में शांति से दिया जाए तो कई दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। मनोविज्ञान भी इसे सिद्ध कर चुका है कि यदि आप आवाज नीचे रखेंगे तो न ही क्रोध आएगा और न ही आपके अंदर जैसे को तैसा साबित करने वाली मनःस्थिति बनेगी। जैसे को तैसा साबित करने वाली स्थिति व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। जैसे को तैसा कहावत को वास्तव में जैसे को तैसा क्यों भला? होना चाहिए। यदि व्यक्ति को महानता की ओर बढ़ना है तो अपने अंदर से अहम और प्रतिशोध जैसी भावनाओं को निकालना होगा। ये भावनाएं ही जैसे को तैसा की स्थिति उत्पन्न करती हैं।

रेनू सैनी

हिंसा की आग में झुलसते चिकित्सक

आशुतोष कुमार सिंह

एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा आम आदमी नहीं लगा पाता है

हाल के दिनों में डॉक्टरों पर भीड़ के हमले बढ़े हैं। नया मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। वहां के डॉक्टरों को भीड़ ने इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि एक बुजुर्ग को वे मरने से नहीं बचा सके। देश के लोगों में आम धारणा है कि डॉक्टर लूटते हैं। डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करते। कुछ एक मामलों में यह बात सही है, लेकिन जब हम सार्वभौमिकता में बात करते हैं तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा आम आदमी नहीं लगा पाता है। लाखों रुपये की फीस चुकता करने और अपने जीवन के 10-12 साल देने के बाद एक चिकित्सक पैदा होता है। और यह समाज उस चिकित्सक को भगवान का दर्जा देकर यह कहता है कि चिकित्सक बीना फीस लिए मरीजों का इलाज कर दे। एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर प्रैक्टिस करने के लिए जब कोई चिकित्सक समाज में आता है तब उसके सामने अपनी रोजी-रोटी का भी सवाल होता है और साथ ही उस पूंजी की रिकवरी का भी प्रश्न होता है जो या तो उसने अपनी जमीन बेच कर लगाई होती है या कर्ज लेकर। यहां पर एक प्रश्न चिकित्सक बनने की प्रक्रिया का भी है। आखिर चिकित्सक बनाने वाला तंत्र इतना महंगा क्यों है? अगर चिकित्सक बनाने का खर्च कम हो जाए और किसी को चिकित्सक बनने के लिए आर्थिक रूप से विपन्न न होना पड़े तो निश्चित रूप से जो चिकित्सक बनेंगे वे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ज्यादा समझ पाएंगे।

यहां पर एक बात और समझने की है कि समाज के अधिकांश लोग अपने-अपने क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं और डॉक्टर से सदआचरण की अपेक्षा रखते हैं। समाज जब कहता है कि चिकित्सक को इलाज का खर्च कम करना चाहिए, उसी समय समाज का यह भी दायित्व बनता है कि वह सरकार से कहे कि वह चिकित्सक बनने की प्रक्रिया को सस्ता करे। डोनेशन लेकर प्रवेश देने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों से कहें कि वे कम खर्चे में चिकित्सा की पढ़ाई कराएं, लेकिन ऐसा करना हमारे समाज को अच्छा नहीं लगेगा। सच्चाई तो यह है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हमारा समाज एक-दूसरे को भ्रष्टाचारी बता कर खुद को सदविचारी स्थापित करने में जुटा हुआ है। एक डॉक्टर की व्यथा को समझना हो तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर देखिए कि एक डॉक्टर को कितने मरीजों को देखना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 1000 की आबादी पर एक फिजिशियन होना चाहिए, लेकिन अपने देश में 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है। डॉक्टरों पर काम का दबाव दोगुना है।

किसी मरीज का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को मानसिक शांति की जरूरत होती है, लेकिन जब समाज उस डॉक्टर को एक खलनायक के रूप में निरूपित करने लगता है तो डॉक्टर कोई भी जोखिम लेने के पहले 100 बार सोचता है। चिकित्सकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की घटनाएं स्वस्थ समाज के लिए चिंतनीय प्रश्न है। इस विषय पर समाज और सरकार, दोनों को गहन चिंतन-मनन करने की जरूरत है।

(लेखक स्वस्थ भारत न्यास के चेयरमैन हैं)

संवैधानिक मर्यादा सिखाना जरूरी

एनके सिंह के लेख 'केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार की जरूरत' से असहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि जब कोई मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने से ही इन्कार कर दे, सीबीआइ के अधिकारियों को बंदी बना दे तो क्या किया जाए? न्यायपालिका बार-बार कह रही है कि बंगाल में विधि-अनुसार शासन नहीं चल रहा है, किंतु केंद्र पसोपेश में है कि वह अनुच्छेद 356 का उपयोग कर राज्य सरकार को बर्खास्त करे कि नहीं करे, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत के अभाव में कहीं उसका यह प्रस्ताव गिर न जाए। वास्तव में केंद्र सरकार की इस परेशानी का फायदा ममता बनर्जी उठा रही हैं। यह उचित नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में संवैधानिक अनुशासनहीनता के और नए उदाहरण देखने को मिल सकते हैं।

अजय मित्तल, मेरठ

लौट पाएगी बेकसूरों की जान?

डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई, पर इस बीच जिन बेकसूर मरीजों की जानें गई हैं क्या वे फिर से लौट पाएंगी। यह विचारणीय प्रश्न है। कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' ने देशव्यापी हड़ताल का एलान करके लाखों पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़क दिया। इसे मानवीय सेवा के खिलाफ कदम कहा जा सकता है। ममता ने अगर शुरुआती दौर में ही समझदारी से काम लिया होता तो शायद इसका हल तभी निकाला जा सकता था। डॉक्टरों की हड़ताल से दो प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं। एक अस्पतालों में संसाधनों की कमी और दूसरा सुरक्षाकर्मियों की कमी। डॉक्टरों पर हो रहे हमले रोकने के लिए महाराष्ट्र में 2010 में कानून में संशोधन किया गया था, पर क्या हुआ। मुंबई के पास एक अस्पताल में शिवसेना के एक नेता की मृत्यु होने पर पूरा अस्पताल जला देने की घटना याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समस्या कोई भी हो उसे लटकाकर रखने की राजनीति हानिकारक है। नेताओं को तो किसी भी मुद्दे पर वोट की रोटी सेकने की आदत है। अस्पतालों की आधारभूत संरचना की आपूर्ति के लिए सभी राज्य सरकारें तत्परता से निर्णय नहीं लेतीं। बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य बजट पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में हड़ताल की नौबत क्यों आती है? सोचने वाली बात है।

nutankumarpatni@gmail.com

मेलबाक्स

ऐसे तो अराजक हो जाएंगे

मुखर्जी नगर में एक ग्रामीण बस सेवा चालक का पुलिस वालों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। देखते ही देखते कहा सुनी झगड़े में तब्दील हो गई। आवेग में आकर चालक ने तलवार से पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिससे एक पुलिस वाले के सिर पर गंभीर चोट आ गई। इतना ही नहीं चालक के नाबालिग बेटे ने बस चढ़ा कर पुलिसवालों को मारने की कोशिश की। इसके बाद पुलिसवालों ने जब चालक और उसके नाबालिग बेटे की पिटाई की तो तूफान खड़ा हो गया। क्या जनता द्वारा पुलिस वाले के साथ बर्बरता करना उचित था? क्या वाकई पुलिसवालों को सस्पेंड करना चाहिए? मेरा मानना है जनता के साथ-साथ पुलिसवालों का भी पक्ष जानना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो देश में अराजकता का माहौल बन जाए और ताकतवर लोग सड़कों पर ही फैसला करने लग जाएं।

प्रकाश चंद, उत्तम नगर, नई दिल्ली

मासूमों की मौत

विज्ञान और प्रशासन अपनी सफलता के बड़े-बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन बिहार में चमकी बुखार और लू से सैकड़ों लोग की मौत का उनके पास कोई जवाब नहीं है। यह जितना दुखद है उतना शर्मसार करने वाला भी है। मासूम बच्चे बेमौत मर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इन सभी मौतों का जिम्मेदार कौन है। गोरखपुर की इंसेफेलाइटिस भी जटिल समस्या हो गई, जिसकी चपेट में आकर अब तक न जाने कितने बच्चे काल का ग्रास बन चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कारगर उपाय नहीं खोजा जा सका है। यह कमजोरी हमारे विश्व गुरु बनने के रास्ते में बहुत बड़ा अवरोधक है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

20 लाख के करीब यात्री चारों धाम-गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ में दर्शन कर चुके हैं बीते सवा महीने से भी कम अवधि में। यानी हर रोज लगभग 50 हजार यात्री चारों धाम पहुंच रहे हैं।

आजकल

स्पेस वॉर की चुनौती से निपटने की तैयारी

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफएसआइ ग्लोबल से संबद्ध

मोदी सरकार ने अंतरिक्ष में जंग की स्थिति में सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के लिए डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी (डीएसआरओ) बनाने की मंजूरी दी है। इससे यह साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में भारत अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयार और मुस्तैद रहेगा। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका पहले ही रूस और चीन से अंतरिक्ष में जंग की आशंका के मद्देनजर 2020 तक स्पेस फोर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है

27 मार्च, 2019 को जब भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक स्वदेशी एंटी-सैटेलाइट मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की निचली कक्षा में तैनात अपना एक जिंदा उपग्रह माइक्रोसैट-आर को मार गिराया और इस तरह देश दुनिया का चौथा देश बन गया जिनके पास स्पेस वॉर का मुकाबला करने की क्षमता है तो किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा देश इतनी जल्दी स्पेस वॉर को लेकर तैयारियों में तेजी दिखाएगा, लेकिन 11 जून, 2019 को जब मोदी सरकार ने अंतरिक्ष में जंग की स्थिति में सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के लिए एक नई एजेंसी-डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी (डीएसआरओ) बनाने की मंजूरी दी तो देश के ये इरादे साफ हो गए कि आने वाले वक्त में भारत स्पेस से आने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयार और मुस्तैद रहेगा। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका पहले ही रूस और चीन से स्पेस में जंग की आशंका के मद्देनजर 2020 तक स्पेस फोर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, अब उस दिशा में भारत ने भी पहलकदमी की है। हालांकि अभी सवाल ये हैं कि क्या भारत को स्पेस की तरफ से कोई खतरा है? क्या वास्तव में स्पेस में जंग छिड़ने की कोई नौबत आ सकती है? और यदि अंतरिक्ष युद्ध की स्थितियां पैदा हुईं तो क्या हमारा देश इस मामले में चीन आदि पड़ोसियों का मुकाबला करने की स्थिति में होगा?

अंतरिक्ष में जंग की आशंका

उल्लेखनीय है कि सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) ने जिस नई एजेंसी डीएसआरओ को गठित करने को मंजूरी दी है, उस पर अंतरिक्ष में मुकाबले के लिए हथियार और तकनीकी तैयार करने का जिम्मा होगा। यह एजेंसी रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (डिफेंस स्पेस एजेंसी-डीएसए) को शोध और अनुसंधान में सहयोग करेगी। यह भी ध्यान रहे कि जिस डीएसए में तीनों सेनाओं के सदस्य शामिल हैं, उसे मुख्यतः अंतरिक्ष में जंग लड़ने में सहयोग करने के लिए भी बनाया गया है। इन खूबियों और तैयारियों का कोई उद्देश्य तभी समझ में आता है जब यह साबित हो कि अंतरिक्ष से कोई खतरा वास्तव में पैदा हो सकता है। ऊपरी तौर पर लगता है कि तनातनी की किसी स्थिति में दो देशों में जंग छिड़ने या विश्वयुद्ध जैसी स्थितियों के बीच पारंपरिक तौर-तरीकों वाले ही युद्ध हो सकते हैं। इनमें से ज्यादा खतरा एटमी हथियारों का दिखाया जाता है, पर इधर कुछ अरसे से जिस तरह से कुछ देश भविष्य के युद्धों का खाका खींच रहे हैं, उसे देखते हुए यह आशंका जल्दी ही सच साबित होती लग रही है कि आने वाले दिनों में कोई जंग धरती पर नहीं, बल्कि स्पेस में लड़ी जाएगी। युद्ध यदि सीधे-सीधे अंतरिक्ष में नहीं हुआ तो भी ऐसा हो सकता है कि धरती पर होने वाले युद्ध अंतरिक्ष के जरिये संचालित हों। इस प्रसंग में अमेरिका की स्पेस फोर्स की तो चर्चा है ही, क्योंकि कुछ माह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस फोर्स में लोगों के चुनाव को लेकर राय भी मांगी थी, लेकिन इस मामले में कोई पहल सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका के अलावा चार अन्य देशों के पास अंतरिक्षीय फौज जैसे प्रबंध हैं। इन्हें मिलिट्री स्पेस कमांड कहा जाता है। ये देश हैं चीन (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स), फ्रांस (फ्रेंच ज्वाइंट स्पेस कमांड), रूस (रशियन एयरोस्पेस फोर्सेज एवं रशियन स्पेस फोर्सेज) और इंग्लैंड (रॉयल एयर फोर्स एवं आरएएफ एयर कमांड।

अमेरिका की तैयारी

जहां तक अमेरिका का मामला है तो अमेरिकी सेना की फिलहाल पांच शाखाएं-वायुसेना, थल सेना, कोस्ट गार्ड, मरीन कॉर्प्स और नौसेना हैं, लेकिन घोषणा के मुताबिक 2020 तक यह स्पेस आर्मी बनी तो यह अमेरिकी सेना की छठी शाखा होगी। स्पेस आर्मी के गठन के बारे में दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन की ओर से पैदा हो रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य हुआ है। असल में अमेरिका नेतृत्व को लगता है कि रूस और चीन जिस तरह से स्पेस में बड़ी संख्या में उपग्रह छोड़ रहे हैं, उनसे अंतरिक्ष में तैनात अमेरिका के संचार, नेवीगेशन और खुफिया सूचनाएं जुटा रहे उपग्रहों को खतरा हो सकता है। यह नहीं, कुछ वर्ष पूर्व जिस प्रकार से चीन ने बेकार हो चुके अपने एक सैटेलाइट को मिसाइल दागकर अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया था, उससे अमेरिका को महसूस हो रहा है कि किसी दिन तनातनी बढ़ने पर चीन उसके यानी अमेरिका के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में तबाह कर सकता है। इसलिए वह अंतरिक्ष में होने वाली इस किस्म की जंग के लिए पहले से पूरी तैयारी रखना चाहता है।

स्पेस आर्मी का स्वरूप

किसी भी देश की स्पेस डिफेंस एजेंसी या स्पेस आर्मी कैसे काम कर सकती है, इसका एक संकेत अमेरिका की स्पेस आर्मी के गठन की रूपरेखा से मिल सकती है। हालांकि अभी ट्रंप प्रशासन ने साफ नहीं किया है कि उसकी स्पेस आर्मी कैसे काम करेगी और उसके हथियार कौन-कौन से होंगे? पर अमेरिका में इससे पहले स्पेस वॉर का जो मोटा-मोटा खाका खींचा गया है, उसमें मुख्य रूप से तीन तरह की प्रणालियों की बात गई है। पहली तो यह है कि अगर कोई शत्रु देश अमेरिका पर आक्रमण करता है तो अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थित सैन्य उपग्रह-कॉमन एयरो व्हीकल से तीन हजार नॉटिकल मील की गति से भारी तबाही मचाने वाला एक हजार पाउंड तक के वजन वाला बम बिल्कुल सटीक निशाने पर दागा जा सकेगा। इसी तरह अंतरिक्ष में तैनात उपकरणों की सहायता से लेजर किरणों से हमला बोलना अमेरिका को लुभाता रहा है। इस तरह की प्रणाली को इवोल्यूशनरी एयर एंड स्पेस ग्लोबल लेजर इंगेजमेंट (ईगल) कहा गया है। इससे हवा से हवा में, सतह से सतह पर या अंतरिक्ष स्थित लेजर प्रक्षेपक सिस्टम से धरती पर संहारक क्षमता वाली लेजर किरणें फेंकी जा सकती हैं और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। तीसरा सबसे विचित्र हथियार वह है, जिसे रोड्स फ्रॉम गॉड जैसा अनूठा नाम दिया गया है। धातु की बनीं अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में 7200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काटने वाली करीब सौ किलोग्राम वजन वाली इन सड़कों या प्लेटफॉर्मों से पृथ्वी पर सचमुच मौत की वर्षा की जा सकती है। यही नहीं, पार्टिकल बीम (यानी आवेशित और खतरनाक किरणें), कायनेटिक किल वेपंस (जिसमें रॉकेट अथवा गोलियों की तीव्र बौछार फेंकने वाले हथियार शामिल हैं) एवं मिसाइलों के अलावा और भी अनेक हथियार हैं, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी अथवा अंतरिक्ष में ही कहर बरपा सकते हैं। इनमें अपारंपरिक श्रेणी के स्पेस बग्स, स्पेस हैकर्स, ई-बम, प्रोपल्शन सिस्टम, स्पेस फाइटर, एलियन टेक्नोलॉजी और प्लाज्मा वेपंस तक शामिल हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्पेस बग्स एक तरह के कीटाणु होंगे, जो अंतरिक्ष से धरती पर उतर कर कोई खतरनाक बीमारी पैदा कर सकते हैं। स्पेस हैकर्स के जरिये अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों से लेकर पृथ्वी पर स्थित संचार तथा विद्युत प्रणालियों को ठप्प किया जा सकता है। अमेरिका के रक्षा विभाग की एयरफोर्स इकाई अतीत में स्टार वॉर नाम की योजना में एक ऐसी मिसाइल प्रतिरक्षण प्रणाली की चर्चा कर चुकी है, जिसमें हमले की सूचना पाते ही शत्रु देश की तरफ अंतरिक्ष में तैनात मिसाइल दागी जा सकती है। अपनी ओर आने वाले युद्धक विमान या मिसाइल को भी अंतरिक्ष में तैनात प्रणालियों से ही नष्ट किया जा सकता है।

विश्व की चिंता

अंतरिक्ष में जंग की योजनाओं पर कई सवाल भी उठ चुके हैं। खासतौर से उपग्रहों को अंतरिक्ष में नष्ट करने की चीन, अमेरिका समेत भारत की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। इस बारे में दुनिया के कई मुल्कों का मत है कि उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करना महज एक बहाना है, असल में इस तरह ये देश स्पेस वार की अपनी छिपी परियोजनाओं के मकसद से अपने अंतरिक्षीय हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। इन योजनाओं का विरोध भी हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह अंतरिक्ष में कबाड़ बढ़ने से संबंधित है। खगोलविज्ञानियों ने कहा है कि स्पेस में सैटेलाइटों को मार गिराने से अंतरिक्ष में वह कबाड़ और बढ़ेगा, जो पहले से ही एक गंभीर समस्या बना हुआ है। जाहिर है ये दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, पर जब सवाल देश की सुरक्षा को पूरी तरह चाक-चौबंद बनाने का हो तो इस तरह के समझौते करना मजबूरी हो जाता है।

रीगन ने देखा था स्पेस वॉर का सपना

यूं अंतरिक्ष से जंग का यह विचार आज का नहीं है। सबसे पहले 1983 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस तरह की जंग का स्वप्न देखा था। हालांकि अमेरिका ने अंतरिक्ष से जंग की अपनी योजना पर तुरंत अमल नहीं किया, लेकिन उसके बाद लगभग 13 साल तक पूरी दुनिया में इस विचार को लेकर आशंका और भय का माहौल बना रहा। रीगन चाहते थे कि पृथ्वी पर जो युद्ध होते हैं, उन पर अंतरिक्ष में तैनात सैनिक उपग्रहों और उपकरणों से इस तरह नियंत्रण पाया जाए कि अमेरिका और उसके मित्र देश हमेशा बढ़त पा सकें। इस बीच 1996 में जब बिल क्लिंटन ने स्टार वॉर की योजना को कुछ समय के ठंडे बस्ते में डाल दिया था तो दुनिया ने चैन की सांस ली थी, पर अब ट्रंप प्रशासन इस योजना पर फिर से विचार कर रहा है। छह मार्च, 2018 को अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस के निदेशक ले. जनरल रॉबर्ट पी. एश्ले जूनियर ने अमेरिकी सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने कहा था कि रूस और चीन ऐसे हथियार विकसित कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल वे अंतरिक्षीय जंग में कर सकते हैं। हालांकि खुद उन्होंने अमेरिका के स्पेस वॉर में शामिल होने की बात नहीं कही, लेकिन यह माना जाता है कि रूस, चीन के साथ अमेरिका भी ऐसी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें धरती से मिसाइल दाग कर अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट को ध्वस्त किया गया था।

रूस की पहल : वर्ष 2014 की बात है। उन दिनों दुनियाभर की स्पेस एजेंसियां रूस के एक रहस्यमयी सैटेलाइट पर नजर रखी हुई थीं। कृत्रिम उपग्रहों पर नजर रखने वाले कई विशेषज्ञ ऑब्जेक्ट 2014-28 ई नामक रूसी सैटेलाइट की भ्रम पैदा करने वाली हरकतों से चकराए हुए थे। इनमें से कुछ को लग रहा था कि यह अंतरिक्ष में बेकार हो चुके उपग्रहों से बना था, जबकि कुछ का मानना था कि इसे असल में रूस ने अपने किसी अन्य सैटेलाइट को ईंधन देने या उसकी मरम्मत करने के लिए भेजा था, लेकिन ज्यादातर का मानना था कि यह असल में दुश्मनों को खत्म करने का सामान था। बाद में अमेरिका ने इसे सैटेलाइट की श्रेणी में डाल दिया। दावा किया जाता है कि अमेरिका और रूस में वर्ष 1950 में ही एंटी-सैटेलाइट हथियार बनने शुरू हो गए थे। रूस ने 1960 में एक फाइटर सैटेलाइट विकसित किया था, जिसे दूसरे उपग्रहों के करीब उड़ने और हथियार इस्तेमाल करके उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था। रूस ने आधिकारिक तौर पर तो वह कार्यक्रम बंद कर दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि वह भी चोरी-छिपे लंबे समय तक एंटी-सैटेलाइट वेपंस को तैयार करता रहा है।

खरी-खरी

सांप दूरबीन लिए बैठे हैं

जगदीश ज्वलंत

हमारे संवाददाता उस संवेदनशील क्षेत्र में जा पहुंचे हैं, जहां चूहों के बिलों में अनधिकृत रूप से सांपों ने डेरा जमा रखा है। चूहे या तो बिल छोड़ भाग गए या निवाला बन गए। बीनचंदजी, बताइए ताजा हालात क्या हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, जी, आपकी तो सुन पा रहा हूं, किंतु यहां जिनकी सुनने आया हूं, उनके दर्शन दुर्लभ हैं। कुछ को तो सांप सूंघ गया है और कुछ उनके सूंघने से स्वयं को बचा रहे हैं। यहां अभी-अभी एक बिल से सांप ने फन निकाला है। मैं कैमरामेन से कहूंगा जरा इधर दिखाएं। हां जी, आप कैमरे के सामने हैं। मैं आपको नागनाथ कहूं या सांपनाथ?

कुछ भी कह लो, काम तो हमारा एक ही है। अब हमसे यह मत पूछना कि डसना कहां से सीखा, विष कहां से पाया। यह हमारी आनुवांशिक परंपरा है। विष रगों में दौड़ता है। दिमाग में भी कह लें। और कुछ? जी आप इतनी दूरी तय करके बिना बाधा के यहां तक आए कैसे? देखिए, यह प्रश्न स्वाभाविक है। जंगलराज हमारा साथ देता है।

चूहों की कमजोरियां हमें आमंत्रित करती हैं। पता है, हमने आज तक कोई बिल नहीं बनाया। भई क्यों बनाएं? लगे हैं चूहे इस काम में। बिल और चूहे हमारे लिए ही तो हैं। हमारा लक्ष्य चूहों के संख्या बल को नियंत्रित करना है और स्वभाव, प्रकृति, परिस्थिति इसमें हमारी अप्रत्यक्ष मदद कर रही है। चूहों की रोकथाम ही हमारे संवर्धन का मार्ग है। बिलों की गणना से चूहों का भ्रम होता है, किंतु कोई अंदर नहीं झांकता। न कैमरे, ना कैमरामेन। किंतु गहराई में हम ही हैं, सिर्फ हम।

सामने नागिन-डांस चल रहा है। मैं कैमरामेन से कहूंगा जरा कैमरा उधर घुमाएं। देखिए नागिनें नृत्य कर रही हैं। तृप्त, संतुष्ट और निर्भय। ताजा फूटे अंडे भी हैं। इन्हें सपोले नाम से जाना जाता है। ये डरते नहीं हैं। सीमावर्ती कोतवालों को ये सैंया मानते हैं। लचीली नीतियों के अभयारण्य में तुष्टीकरण की हवाओं में ये पनपते हैं। तेजी से फैलते और फिजाओं में बिखर जाते हैं।

आपकी किसी चूहे से बात हुई? नहीं, वे दूर-दूर तक दिखलाई नहीं दे रहे हैं। उनका कुछ सामान यहां पड़ा है। गेहूं के दाने हैं और कपड़ों की कतरनें। इनके नियंत्रण के लिए कुछ हो रहा है? नहीं! नियंत्रणकर्ता सपेरे बीन लिए बैठे हैं तो उधर सांप भी दूरबीन लिए बैठे हैं।

ट्वीट-ट्वीट

मंत्री या संसद सदस्य की शपथ का एक महत्वपूर्ण अंश होता है, 'भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।' बहुत कम लोग इसे शुद्ध बोल पाए। 'अक्षुण्ण' की अनेक छटाएं सुनाई पड़ीं। अशुद्ध वाचन की यह बात किसी ने उठाई भी नहीं। क्या कोई नियम-विनियम ऐसी शपथ को अवैध नहीं मानता? सुरेश पंत@drsureshpant

हर बात में पार्टीपरक राजनीति अच्छी नहीं। पुलिसकर्मी पर तलवार से हमले को जायज ठहराने की कोशिश न करें। तलवार से हमला होने पर पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं आप? इसे धार्मिक भावनाओं का सवाल न बनाएं। इस तरह की राजनीति के नतीजे अपना समाज पहले से ही बहुत झेल रहा है। पुरुषोत्तम अग्रवाल@puru_ag

कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में अपना नेता बनाया है। उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही में विपक्षी गतिरोध बढ़ने के आसार अधिक दिखते हैं। रशीद किदवई@rasheedkidwai

उत्तराखंड डायरी

उत्तराखंड को चाहिए ग्रीन बोनस

कुशल कोठियाल
राज्य संपादक, उत्तराखंड

हाल में दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की पर्यावरणीय सेवाओं के बदले केंद्र से ग्रीन बोनस देने की मांग की। गौरतलब है कि उत्तराखंड अपनी दो-तिहाई भूमि पर वनों का संरक्षण कर देश को महत्वपूर्ण सेवा दे रहा है। वनों-नदियों-वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित रखने की कीमत भी प्रदेश एवं प्रदेशवासी चुका रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास केवल दो जिलों तक सिमट कर रह गया है। सरकार की तमाम रियायतों के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश गति नहीं पकड़ पा रहा है। ढांचागत विकास एवं निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों के चलते तमाम मुश्किलात आती हैं। मानव एवं वन्यजीव संघर्ष समय के साथ-साथ गंभीर रूप लेता जा रहा है। पहाड़ों के कई गांवों में सूर्यास्त होते ही घरों में दुबकना जीवन रक्षा के लिए जरूरी हो गया है। लिहाजा वनों के लिए प्रदेशवासियों के इस त्याग की सही कीमत न सही, लेकिन कुछ प्रोत्साहन राशि तो मिलनी ही चाहिए। सरकार इस रकम का उपयोग जरूरी ढांचागत विकास एवं इको-फ्रेंडली उद्योगों की स्थापना के लिए कर सकती है। इससे प्रदेशवासियों को भी यह लगेगा कि पर्यावरण की जो सेवा वे दे रहे हैं, उसे देश भी मान्यता देता है। ग्रीन बोनस की मांग हालांकि कोई नहीं मांग नहीं है, लेकिन केंद्र एवं प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकारें होने के कारण इस बार कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं। ग्रीन बोनस तो पक्ष-विपक्ष का चुनावी मुद्दा भी रहा है।

बड़ा दायित्व, बढ़ी उम्मीदें : केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण महकमा संभालने के दो सप्ताह बाद हरिद्वार के सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक क्षेत्र में आए। हर समय हर एक के लिए उपलब्ध निशंक इस बार कुछ बदले-बदले नजर आए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दायित्व मिलने की खुशी को जगजाहिर करने के बजाय उन्होंने अपनी दायित्वशीलता से लोगों को गंभीरता से अवगत कराया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से पहले ही समझदारी भरी क्षमा मांग ली कि वे पहले वाली उपलब्धता की अपेक्षा अब न करें। उन्हें प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें यह परीक्षा पास करनी है। इसलिए वह ज्यादा समय एवं ध्यान इस पर देना चाहते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने विभागों के आवंटन के साथ ही बड़ा लक्ष्य भी सौंपा होगा, वरना निशंक ऐसे तो न थे।

चारधाम यात्रा : चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और सवा महीने से भी कम अवधि में 20 लाख के आसपास यात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। यानी हर रोज लगभग 50 हजार यात्री चारों धाम पहुंच रहे हैं। इसमें भी सर्वाधिक यात्रियों की आमद केदारनाथ धाम में हो रही है। चारधाम यात्रा के इतिहास में यह पहला मौका है, जब केदारनाथ दर्शनों को बदरीनाथ से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं, जबकि चारधाम में केदारनाथ की राह सबसे चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद यात्री सुविधाओं के विकास ने केदारनाथ के प्रति यात्रियों का आकर्षण बढ़ा दिया है। यही वजह है कि बदरीनाथ में अब तक केदारनाथ से सिर्फ दस हजार यात्री अधिक पहुंचे हैं। मार्ग की चुनौतियों के बावजूद गंगोत्री-यमुनोत्री में भी इस बार यात्रियों की अच्छी-खासी आमद हो रही है।

पंत के निधन से आई रिक्तता : विभिन्न विषयों पर अर्जित ज्ञान और मधुर व्यवहार के चलते सबको प्रभावित करने वाले प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत का निधन राज्य की राजनीति में एक ऐसी रिक्तता पैदा कर गया जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। प्रकाश पंत उन चंद नेताओं में से थे, जिन्हें जो भी दायित्व दिया गया वह उन्होंने बाखूबी निभाया। बतौर विधानसभा अध्यक्ष संसदीय प्रक्रियाओं में महारत हासिल की तो वित्त मंत्री के तौर पर वित्तीय ज्ञान पर मजबूत पकड़ बनाई। राज्य की राजनीति में शायद ही ऐसे नेता होंगे जो किताबों एवं बौद्धिक बहसों में गहराई तक जाने की क्षमता रखते हों। मौजूदा सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय सौंपा गया और इसी दौरान देश में जीएसटी भी लागू किया गया। इस दौरान हमने उन्हें विभागीय उच्च अधिकारियों को जीएसटी की पेचीदगियों को समझाते हुए भी देखा और व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की समस्याओं के निवारण खोजते हुए भी देखा। जाति, क्षेत्र एवं अन्य जुगाड़ के दम पर राजनीति करने वालों के बीच कोई विशुद्ध रूप से ज्ञान और व्यवहार के बूते भी अपनी जगह बना सकता है और राजनीति की अग्रिम पांत में शामिल हो सकता है, इसका विरला उदाहरण थे प्रकाश पंत।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एक राष्ट्र-एक चुनाव पर सभी दलों की सहमति बनने की संभावना है?

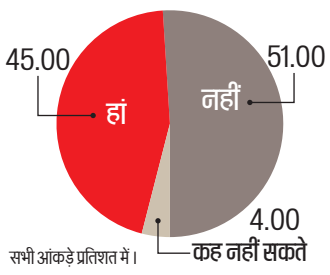

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप बढ़ने में प्रशासन का लचर रवैया जिम्मेदार है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बीमारी के सामने बेबस है सरकार,
त्राहि-त्राहि के शोर में डूबा दिखे बिहार।
डूबा दिखे बिहार न दिखता कोई चारा,
बैठे हैं नीतीश लिये चेहरा बेचारा।
नेता नगरी मस्त न उसकी मिटे खुमारी,
भले जान पर जान जाय लेती बीमारी।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

सुंदरता का एक नया संदर्भ

मनीषा सिंह
स्वतंत्र टिप्पणीकार

जिस तरह घरेलू कामकाजी स्त्री हमारी सामाजिक संरचना का मजबूत स्तंभ है, उसी तरह अपनी बुद्धि-सौंदर्य के बल पर कामयाब होने वाली स्त्री भी नए भारत की छवि गढ़ रही है

अक्सर यह सवाल बौद्धिक विमर्शों में पूछा जाता रहा है कि स्त्री के सौंदर्य का आखिर उद्देश्य क्या है? यह सवाल तब और मानीखेज हो जाता है जब किसी सौंदर्य प्रतियोगिता का नतीजा आता है और हमारे आसपास की कोई लड़की अपनी सुंदरता के बल पर उसमें विजेता घोषित की जाती है। इधर एक ऐसा ही वाकया फेमिना मिस इंडिया, 2019 के परिणाम के साथ सामने आया है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता की इस बार इसलिए ज्यादा चर्चा है, क्योंकि इस बार इसमें देश के विकसित राज्यों के बजाय प्रायः उपेक्षित और पिछड़े राज्यों से संबंध रखने वाली लड़कियों ने कामयाबी का परचम लहराया है।

राजस्थान के राजसमंद जैसे बेहद पिछड़े इलाके से आने वाली और सीए की पढ़ाई कर रही सुमन राव इसकी विजेता हैं। दूसरे-तीसरे स्थान पर और रनर अप रहीं अन्य लड़कियां भी पिछड़े राज्यों की हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव, बिहार की श्रेया शंकर और तेलंगाना की संजना विज इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हुए इस प्रतियोगिता में शामिल हुईं और एक मुकाम हासिल कर दिखा दिया कि सफलता के लिए विकसित इलाकों, राज्यों या महानगरों से ताल्लुक जरूरी नहीं होता। यह हमारे देश की सुंदरता ही नहीं, बल्कि कामयाबी का एक नया संदर्भ है जहां बेहद उपेक्षित इलाकों से आई लड़कियां भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं और सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। हालांकि इस बीच खासतौर से सुंदरता के बल पर अर्जित कामयाबी इसलिए सवालों के घेरे में रहती है कि क्या देहयष्टि और नैन-नक्श के बल पर हासिल सफलता को प्रेरक माना जाना चाहिए? अहम सवाल यह है कि क्या दैहिक पैमानों पर खुद को सुंदर, संतुलित और स्मार्ट साबित करने वाली लड़कियां वास्तव में हमारी उन लाखों युवतियों की प्रेरणा मानीं जानी चाहिए जो शहरों, गांवों और कस्बों में आज पढ़ाई और खेलकूद जैसे मोर्चों पर अपनी योग्यता साबित करने के लिए छटपटा रही हैं? कहीं इससे उनमें यह संदेश तो नहीं जाएगा कि लड़कियों के लिए प्राथमिक जरूरत सुंदर होना है, बुद्धि और कौशल के मामले में श्रेष्ठ होना नहीं?

इस संबंध में हमारे देश और समाज की यह एक कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर लोग भारतीय स्त्री में आज भी उसी छवि को देखना पसंद करते हैं, जिसमें वह घूंघट निकाले घरेलू कामकाज करते हुए और बच्चे पालते, बड़े-बुजुर्गों की सेवाटहल में जिंदगी बिताती है। भारतीय स्त्री की यह छवि महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और सामाजिक रचना का आधार भी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लड़कियां और महिलाएं इसी छवि से बंधकर रह जाएं। जिस तरह घरेलू कामकाजी और घूंघट वाली ग्रामीण-कस्बाई स्त्री हमारी सामाजिक संरचना का मजबूत स्तंभ है, उसी तरह घर से बाहर निकलकर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली और अपनी बुद्धि-सौंदर्य के बल पर कामयाब होने वाली स्त्री भी नए भारत की छवि गढ़ रही है। यहां अहम सवाल यह है कि आखिर इन दोनों खूबियों के साथ स्त्री जीवन को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है?

निःसंदेह हमारे देश के कई राज्यों के ग्रामीण और कस्बाई सामाजिक जीवन की एक सच्चाई यह है कि वहां घरेलू स्त्री ही पूरे समाज की धुरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौका पड़ने पर इन्हीं गांव-देहात और कस्बों आदि से निकलने वाली लड़की मॉडलिंग नहीं कर सकती, ट्रेनों में अकेले सफर नहीं कर सकती और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में आत्मविश्वास के साथ हिस्सा नहीं ले सकती है। फिलहाल सुमन राव, शिवानी जाधव, श्रेया शंकर और इससे पहले मानुषी छिल्लर एवं इसके आगे-पीछे तमाम कस्बाई लड़कियों ने अपने कारनामों से इस धारणा के पुर्जे-पुर्जे कर दिए हैं। असल में ग्रामीण, कस्बाई, पिछड़े राज्यों से आई तमाम मॉडर्न सोच वाली लड़कियों ने आधुनिक वेशभूषा अपनाकर आत्मविश्वास से भरकर कई मंचों पर साबित किया है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे एक प्रेरक बदलाव की वाहक बन सकती हैं। जिस तरह अपनी इच्छा से घूंघट निकालने वाली गोबर थापने वाली स्त्री समाज और देश की धुरी है, उसी तरह ये आधुनिक लड़कियां भी छोटे शहरों-कस्बों और पिछड़े राज्यों की लड़कियों में सपने भर रही हैं कि आज अगर वे भी मेहनत करेंगी तो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, पहलवान, क्रिकेटर या मिस इंडिया-मिस वर्ल्ड बनकर कोई ऊंचा मुकाम बना सकती हैं।

हमारे देश में भी परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर समाज की सोच अब भी पुरातनपंथी खांचे में जकड़ी हुई है। यह एक विडंबना है कि हमारा समाज एक गोबर थापने वाली महिला को अनपढ़-गंवार कहने के संदर्भ के साथ अनुपयोगी साबित करना चाहता है तो दूसरी तरफ मिस इंडिया बनने वाली युवती की भी इसलिए आलोचना करता है कि उसने कम कपड़े पहने होंगे। असलियत में हमारा समाज न तो एक स्त्री को उसकी संपूर्णता में समझ पा रहा है और न ही उसके सौंदर्य के जरूरी दूसरे पहलू को पकड़ पा रहा है। स्त्री की यह सुंदरता उसका सांस्कृतिक सौंदर्य है जो घूंघट में भी प्रतिफलित होता है और बिकिनी में भी। यह सांस्कृतिक सुंदरता स्त्री की सोच और उसकी तरक्की की देन है। जिस तरह देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से प्राकृतिक सुंदरता के पैमानों और आकलन में अंतर आया है, उसी तरह हमारे देश की स्त्री के सांस्कृतिक शरीर के सौंदर्य में भी फर्क पड़ा है। यह समझना होगा कि जिस तरह किसी की सफलता को आंकने के कई अन्य नजरिए होते हैं, जैसे कि उसकी हिम्मत, बुद्धिमानी, ताकत, जिम्मेदारी का अहसास। उसी तरह सुंदरता भी एक परिपक्व धारणा है। कोई व्यक्ति, खास तौर से स्त्री अगर सुंदर होने के साथ-साथ आत्मविश्वास से भरी है और कामकाज के जिस क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करती है, उसमें भी वह सफल है तो वह स्त्री सम्मान की हकदार है। हमारा समाज असल में सुंदर स्त्रियों की कामयाबी के ये अर्थ और संदर्भ अभी उचित ढंग से समझ नहीं पा रहा है। जरूरी था कि वक्त के साथ-साथ समाज में सुंदरता के मापदंड भी बदल जाते और स्त्री सुंदरता के उस पहलू पर भी जोर दिया जाता, जिसमें वह देश एवं समाज के विकास में पुरुषों के बराबर ही हिस्सेदार है।

एचडीएफसी बैंक पर लगा एक करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मंगलवार को निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग नहीं करने और अन्य निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। आरबीआइ ने कहा कि इस जुर्माने का संबंध कुछ आयातकों द्वारा विदेशी मुद्रा के रेमीटेंस के लिए एचडीएफसी बैंक में फर्जी बिल ऑफ इंट्रीज (बीओई) जमा किए जाने से है।

चीन के बाजार में निकट भविष्य में हमारे प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है। वहां अपनी सेवा लांच करने के लिए हमें सही परिस्थितियों की जरूरत होगी।
— सुंदर पिचाई, सीईओ, गूगल

सेंसेक्स	39,046.34	85.55	निफ्टी	11,691.50	19.35	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 33,720	₹100	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 38,220	₹130
डॉलर	₹ 69.70	₹0.21	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 62.68							

मुसीबत ▸ कंपनी के शेयर 40 फीसद टूटे, बचे दो निदेशकों ने भी दिया बोर्ड से इस्तीफा

जेट एयरवेज मामले को एनसीएलटी में ले गए कर्जदाता बैंक

बुधवार से एनसीएलटी में होगी कंपनी के मामले की सुनवाई

मुंबई, प्रेट्र : कर्ज के बोझ तले दबी और निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के बड़े कर्जदाता आखिरकार मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में ले आए। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई में 26 कर्जदाताओं के कंसोर्टियम ने मंगलवार को जेट एयरवेज की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी में याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल बुधवार से मामले की सुनवाई करेगा।

इससे पहले कंपनी के दो परिचालन कर्जदाता शमन व्हील्स और गग्गर इंटरप्राइजेज 10 जून को ही जेट एयरवेज को एनसीएलटी में घसीट चुके हैं। उनके मामलों पर एनसीएलटी में गुरुवार को सुनवाई होगी। कंपनी पर शमन व्हील्स का 8.74 करोड़ रुपये, जबकि गग्गर इंटरप्राइजेज का 53 लाख रुपये बकाया है।

निदेशकों ने दिया इस्तीफा : इस बीच, संकटग्रस्त जेट एयरवेज के दो और निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई नियामकीय सूचना में कहा, 'अशोक चावला और शरद शर्मा ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो 17 जून से प्रभावी हो गया है। बोर्ड कंपनी कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, जिसके मद्देनजर कोई अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति नहीं हो रही है।'

कंपनी पर 36,500 करोड़ रुपये बकाया : विमानन कंपनी पर बैंकों का 8,500 करोड़ रुपये का बकाया है। जेट एयरवेज को अपने वेंडर्स को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करना है। कंपनी पर अपने करीब 23,000 कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया मद में 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी 13,000 करोड़ रुपये का घाटा उठा चुकी है। इस तरह इस वक्त कंपनी पर कुल 36,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। लेकिन सर्विस कंपनी होने के नाते उसके पास संपत्ति नहीं के बराबर है। विमान संपत्ति के मामले में उसके पास सिर्फ 16 अपने विमान हैं, जिनका कुल मूल्य करीब 5,000 करोड़ रुपये ही है।

कर्जदाताओं को बहुत ज्यादा वसूली की कोई उम्मीद नहीं। फाइल

कंपनी के शेयर हुए लहूलुहान

जेट एयरवेज का मामला एनसीएलटी में जाने के चलते मंगलवार को कंपनी के शेयरों में जबर्दस्त गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में इंट्रा-डे आधार पर कंपनी के शेयर 52.78 फीसद तक गिरकर 32.25 रुपये के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गए। मामूली सुधार के बाद भी कारोबार के आखिर में बीएसई में कंपनी के शेयर 40.78 फीसद गिरकर 40.45 रुपये के भाव पर बंद हुए। एनएसई में कंपनी के शेयरों में 40.78 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। इस स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयरों का बंद भाव 40.50 रुपये रहा।

कड़े डाटा स्टोरेज नियमों की होगी समीक्षा

▸ उद्योग द्वारा चिंता जताए जाने के बाद रिजर्व बैंक ने दिया मामले की समीक्षा का आश्वासन

▸ आरबीआइ ने पिछले साल पेमेंट कंपनियों को अपने डाटा भारत में ही स्टोर करने का दिया था निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) डिजिटल डाटा भारत में ही स्टोर करने के कड़े नियमों की समीक्षा करेगा। सरकार की तरफ से मंगलवार को ऐसा कहा गया। मास्टरकार्ड और वीजा जैसी कुछ विदेशी कंपनियों ने इन नियमों के प्रति आपत्ति जताई है। यह ऐसा मसला है, जिससे न केवल मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां परेशान हैं, बल्कि अमेरिकी सरकार भी नाराज है। इन नियमों की समीक्षा का फैसला ऐसे समय किया गया है, जब भारत और अमेरिका के बीच आपसी व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है।

वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ देश में डाटा से संबंधित नियमों पर चर्चा की थी। बैठक में शामिल कंपनियों ने आरबीआइ के सख्त निर्देश पर चिंता जताई थी। इसके बाद आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने उद्योग के प्रतिनिधियों को अश्वस्त किया कि आरबीआइ इस मामल पर गौर करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल अप्रैल में विदेशी पेमेंट कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे पर्यवेक्षण के नजरिए से अपने-अपने पेमेंट्स डाटा भारत में स्थित कंप्यूटर में ही स्टोर करें। विदेशी कंपनियों को भारत में डाटा स्टोर करने के लिए अतिरिक्त निवेश करना होगा। लेकिन सरकार का मानना है कि देश में डाटा स्टोर करने से उनकी सही तरीके से निगरानी की जा सकेगी। बयान के मुताबिक मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा ने भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में हिस्सा लिया था।

बैठक में ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर भी चिंता जताई गई। प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति में भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और सर्च इंजन जैसे स्रोतों के उपयोग से बने डाटा का स्टोरेज भारत में ही करने का नियम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय कंपनियों ने जहां डाटा के स्थानीय स्टोरेज का समर्थन किया है, वहीं फेसबुक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई है। गोयल ने उद्योग के प्रतिनिधियों का आश्वस्त किया कि उनकी सभी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने उद्योग के प्रतिनिधियों को अपनी चिंता लिखित रूप में 10 दिनों के अंदर भेजने के लिए कहा।

अमेरिकी कंपनियां भारत के इस कदम से हैं खासा परेशान। प्रतीकात्मक

प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई-कॉमर्स बाजार पर अध्ययन शुरू किया

नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने ई-कॉमर्स बाजार पर एक अध्ययन शुरू किया है। इसका मकसद इस क्षेत्र में कारोबारी तौर तरीकों और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले मुद्दों को समझना है। अध्ययन में उन उत्पादों को खास तौर से शामिल किया जाएगा, जिनमें ऑनलाइन कॉमर्स का अत्यधिक विकास हुआ है।

पीएम ने 100 दिनों के एजेंडा पर की सचिवों की समीक्षा बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष के आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों के एजेंडा को लेकर कई मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में वित्त मंत्रालय के सभी पांच विभागों और प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के अलावा नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि अगले पांच वर्षों में भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों के बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, हर घर तक पाइप के जरिये पानी पहुंचाने, सबके लिए बिजली मुहैया कराने और कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार समेत कई अन्य मुद्दे चर्चा का विषय रहे। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर को गति देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्तों की चुनौतियां दूर करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के दूसरे प्रमुख उपायों पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट पांच जुलाई को पेश होना है।

इस बीच, प्रधानमंत्री शनिवार को शीर्ष अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे। इसका मकसद आर्थिक नीतियों की दिशा और विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करना है। नीति आयोग द्वारा आयोजित इस बैठक में कई मंत्री, आयोग के अधिकारी, शीर्ष अर्थशास्त्री, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और उद्योगपति शामिल होंगे।

हवाई यातायात विकास की राह पर लौटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अप्रैल में गिरावट का सामना करने के बाद घरेलू हवाई क्षेत्र की स्थिति मई में फिर से वृद्धि के रास्ते पर रही। विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 2.96 फीसद का इजाफा रहा।

इससे पहले अप्रैल में पिछले वर्ष इसी महीने के मुकाबले 4.5 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1.22 करोड़ रही जो मई 2018 में 1.18 करोड़ थी। यह सीधे 2.96 फीसद की वृद्धि को दर्शाता है।

ऑटो कंपनियों के सामने बीएस-6 की चुनौती

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

▸ अगले वर्ष अप्रैल से सिर्फ बीएस-6 वाहनों की होनी है बक्री

▸ बिक्री घटने से कंपनियों के पास पड़ा है बीएस-4 वाहनों का बड़ा स्टॉक

▸ कंपनियों पर इस वर्ष दिसंबर से ही बीएस-6 वाहनों का उत्पादन शुरू करने का दबाव

एक तो बाजार की मंदी और अब बीएस-6 मानकों के मुताबिक मॉडलों में बदलाव करना - देश की कार कंपनियों के सामने दोहरी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। पैसेंजर कारों की बिक्री पिछले एक दशक के निचले स्तर पर पहुंचने की वजह से जहां मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के पास 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के स्टॉक पड़े हुए हैं। वहीं उन्हें बीएस-6 मानकों के मुताबिक इंजन बनाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को मोटे तौर पर 40,000 करोड़ रुपये का नया निवेश भी करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑटोमोबाइल उद्योग को सरकार से उम्मीद है कि वह शुल्कों में कटौती कर उन्हें और ज्यादा संकट में फंसने से बचाने की कोशिश करेगी।

बीएस-6 मानक लागू करने पर सरकार की तरफ से गठित अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में पूरे हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया गया कि अगले वर्ष अप्रैल से कम से कम दो महीने पहले बीएस-6 पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसमें आटो कंपनियों के प्रतिनिधियों की तरफ से बताया गया कि उनकी इनवेंट्री (नहीं बिके वाहन) बढ़ती जा रही है। इस वर्ष दिसंबर के बाद से उन्हें बीएस-6 मानक वाले वाहन ही तैयार करने होंगे, तभी अगले वर्ष मार्च-अप्रैल तक वे पूरे देश में उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसे में अगर अगले पांच-छह महीने के दौरान उनके वाहनों की बिक्री नहीं बढ़ती है तो उन्हें भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें कुछ ऐसी रियायतें मिलनी चाहिए जिससे बीएस-4 मानक वाले सभी वाहनों (स्टॉक) की बिक्री हो जाए। अब देखना है कि उक्त समिति इस बारे में वित्त मंत्रालय को तैयार कर पाता है या नहीं।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) की तरफ से पिछले हफ्ते जारी रिपोर्ट बताती है कि इस वर्ष मई में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 20.6 फीसद की गिरावट हुई है, जो पिछले एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसी महीने भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 19.7 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। देश की शीर्ष 10 वाहन निर्माता कंपनियों में से सात ने पिछले तीन महीनों में कई बार उत्पादन को बंद किया है ताकि पुराने स्टॉक की बिक्री पहले हो। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां उत्पादन घटाने में जुटी हैं। एक अनुमान है कि कार कंपनियों के पास 30 हजार करोड़ रुपये के वाहन ग्राहक के इंतजार में हैं।

गौरतलब है कि अगले वर्ष अप्रैल से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले कारों की बिक्री होनी है। इस बदलाव के लिए कार कंपनियों को मौजूदा इंजन में बदलाव करना पड़ रहा है, क्योंकि बीएस-6 मानक वाले ईंधन भी दूसरी किस्म के होते हैं। इनसे कम प्रदूषण फैलता है। पेट्रोलियम मंत्रालय का आकलन है कि देशभर में बीएस-6 अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तेल कंपनियों के स्तर पर करीब 90,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ इकरा रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों को बीएस-6 इंजन बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ रहा है।

पहले से ही मंदी से परेशान हैं ऑटो कंपनियां। फाइल

पवन ऊर्जा क्षमता 4,000 मेगावाट तक बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में चालू वित्त वर्ष के दौरान 3,500 से 4,000 मेगावाट तक वृद्धि की संभावना है। हालांकि भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां महत्वपूर्ण बनी रहेंगी। रेटिंग एजेंसी इकरा ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2019--20 में पवन ऊर्जा क्षमता में 3,500 से 4,000 मेगावाट वृद्धि की उम्मीद है। प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों तथा नोडल एजेंसियों द्वारा बड़ी परियोजनाओं के आवंटन से क्षमता वृद्धि में मदद मिलेगी। केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य की वितरण कंपनियों ने फरवरी, 2017 से 12,000 मेगावाट से अधिक क्षमता आवंटित की हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर प्रगति धीमी रही है और वित्त वर्ष 2018-19 में केवल 1,600 मेगावाट का इजाफा हुआ। जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई। इकरा के वाइस प्रेसिडेंट और क्षेत्र के प्रमुख (कॉरपोरेट रेटिंग)] गिरीश कुमार कदम ने कहा, 'सरकार ने मसलों के समाधान को लेकर कुछ उपाय किए हैं। इसमें सुविधा शुल्क के रूप में प्रोत्साहन की पेशकश तथा जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों से मदद शामिल हैं। उन्होंने कहा, हालांकि, क्रियान्वयन और वित्तीय चुनौतियों के कारण कुछ परियोजनाओं के समक्ष समस्याओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। कंपनियों द्वारा समय पर वित्त की व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी हुई है।

शुल्क दरें प्रतिस्पर्धी

हाल में पवन ऊर्जा नीलामी में शुल्क दरें तीन रपए प्रति यूनिट से नीचे बनी हुई हैं। वर्ष 2017 में यह 3.01 रुपये प्रति यूनिट थी जो 2018 में 2.64 रुपये प्रति यूनिट पर आ गई। हालांकि वर्ष 2019 के पांच महीनों में औसत बोली शुल्क 2.85 रुपये प्रति यूनिट रहा। इसका कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े जोखिम, कम प्रतिस्पर्धा और वित्त संबंधी चुनौतियां थी। इसके बावजूद परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले शुल्क दरें प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं।

एनडीटीवी मामले में रॉय दंपती को सैट से राहत

▸ सेबी के फैसले पर दिया स्थगन आदेश, 16 सितंबर को होगी सुनवाई

▸ आदेश की प्रति मुहैया नहीं कराने के लिए भी सेबी की खिंचाई

मुंबई, प्रेट्र : सिक्युरिटीज अपीलीय प्राधिकरण (सैट) ने एनडीटीवी मामले में प्रणय रॉय दंपती को राहत दी है। सैट ने मंगलवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी के उस फैसले पर अंतरिम स्थगन आदेश दिया है, जिसके तहत रॉय दंपती और एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी पर दो वर्षों के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। सैट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रतिबंध आदेश की प्रति नहीं मुहैया कराने को लेकर भी सेबी के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की। प्राधिकरण ने सेबी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसके आदेशों की प्रति सबसे पहले संबंधित पक्षों को मुहैया कराई जाए। सैट ने इस मामले में अपना जवाब देने के लिए सेबी को छह सप्ताह और उसके बाद आवेदनकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

सेबी के पिछले सप्ताह के आदेश के खिलाफ रॉय दंपती और एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी आरआरपीआर ने सैट में याचिका दायर की थी। सैट ने कहा कि एनडीटीवी के निदेशक पद से दूर रखना पहली नजर में कंपनी के शेयरधारकों या निवेशकों के सर्वश्रेष्ठ हित में नहीं है। सैट ने रॉय दंपती को कंपनी में अपनी मौजूदा शेयरधारिता में अगले आदेश तक कोई बदलाव नहीं करने का भी निर्देश दिया।

यह था मामला : सेबी ने पिछले सप्ताह एनडीटीवी लिमिटेड के तीन मुख्य प्रमोटर्स प्रणय रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग कंपनी को पूंजी बाजार से दो साल की रोक लगा दी। नियामक ने रॉय दंपती को इस दौरान कंपनी में बोर्ड या शीर्ष प्रबंधन में कोई पद लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया। सेबी के मुताबिक तीनों प्रमोटर्स ने तीन लोन के बारे में अल्पमत शेयरधारकों को अंधेरे में रखकर कई नियमों का उल्लंघन किया था। नियामक ने आदेश में कहा कि दंपती एक साल के लिए सूचीबद्ध किसी कंपनी में कोई पद नहीं ले सकते हैं।

फेसबुक जल्द ला रही अपनी क्रिप्टोकरेंसी

सैनफ्रांसिस्को, एपी : सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने मंगलवार को बिटक्वाइन जैसी एक नई डिजिटल करेंसी पेश करने की अपनी योजना की घोषणा की। फेसबुक और करीब दो दर्जन साझेदार कंपनियों ने नई करेंसी 'लिब्रा' का प्रोटोटाइप पेश किया। जेनेवा में स्थित लिब्रा नाम का एक गैरलाभकारी संगठन ब्लॉकचेन आधारित नई करेंसी की निगरानी करेगा। यही संगठन नई करेंसी के मूल्य के आधार पर दुनिया में चलने वाली वास्तविक मुद्राओं का भंडार रखेगा, ताकि लिब्रा के मूल्य में एक निश्चितता बनी रहे।

लिब्रा एसोसिएशन के पॉलिसी एवं कम्युनिकेशंस प्रमुख डेंट डिस्पार्टे ने कहा कि नई डिजिटल करेंसी लिब्रा दुनियाभर में बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों तक ई-कॉमर्स और वित्तीय सेवा की पहुंच उपलब्ध कराएगी।

लिब्रा एसोसिएशन ने 28 सदस्यों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इन सदस्यों में मास्टरकार्ड, वीसा, स्ट्रिप, किवा, पेपाल, लिफ्ट, उबर और वुमंस वर्ल्ड बैंकिंग भी शामिल हैं। फेसबुक भी संगठन का एक सदस्य है, लेकिन वह अलग से एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा भी बना रही है।

सवा करोड़ टन पुराना गेहूं महंगे में बेचने चली सरकार

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

▸ बाजार के मुकाबले महंगे में बेचने का एलान, खरीदारों का टोटा

▸ एफसीआइ के लिए सरकारी खरीद वाले नए गेहूं के भंडारण की चुनौती

खुले बाजार में गेहूं की भरपूर उपलब्धता से कीमतें घटी हुई हैं, ऐसे में सरकार सवा करोड़ टन पुराना गेहूं बेचने निकली है। वह भी बाजार के मुकाबले अधिक मूल्य में। ऐसे में सरकार को खरीदार मिलने की कोई संभावना नहीं है। यही वजह है कि खाद्य मंत्रालय के इस एलान का जिंस बाजार पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। सरकारी गोदामों में पड़े गेहूं का कोई लेनदार नहीं मिल रहा है।

चालू रबी खरीद सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है, जिसके भंडारण को लेकर सरकारी एजेंसियां सांसत में हैं। दूसरी ओर इनके गोदामों में 1.20 करोड़ टन गेहूं का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। उसे बाहर निकलने की जल्दी है। वैश्विक बाजार में गेहूं की मांग नहीं होने से निर्यात संभव नहीं है। सरकारी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) खाद्यान्न के पुराने स्टॉक को हर हाल में खाली कराना चाहती है। खुले बाजार में बेचने की नीति के तहत एक करोड़ टन गेहूं और 50 लाख टन चावल बेचने की अनुमति सरकार की तरफ से मिल गई है। लेकिन इन जिंसों के लिए तय की गई कीमतें खुले बाजार के मुकाबले बहुत अधिक हैं। इनमें गेहूं का मूल्य 2,080 से 2,245 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि चावल के लिए 2,785 रुपये प्रति क्विंटल भाव निश्चित किया गया है। इसके मुकाबले उत्पादक बाजारों में गेहूं का मूल्य किसी भी हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं है। यानी सरकार के पुराने गेहूं का मूल्य खुले बाजार के मुकाबले लगभग डेढ़ गुना है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पुराने स्टॉक वाले गेहूं का मूल्य उसके भंडारण के खर्च को जोड़कर तय किया गया है।

सरकारी स्टॉक में अभी 1.20 करोड़ टन पुराने गेहूं के साथ चालू सीजन में कुल 4.65 करोड़ टन गेहूं है। पिछले खरीफ सीजन के चावल का स्टॉक गोदामों में 2.75 करोड़ टन है। इनमें गेहूं का बड़ा स्टॉक खुले में ढंककर रखना होगा। वैसे तो कागजों में गोदामों की कुल क्षमता 8.80 करोड़ टन खाद्यान्न के भंडारण की है। लेकिन जहां जरूरत है वहां इतने गोदाम नहीं हैं।

प्रतीकात्मक

खाद्यान्न बदइंतजामी

▸ बाजार के मुकाबले महंगे में बेचने का एलान, खरीदारों का टोटा

▸ एफसीआइ के लिए सरकारी खरीद वाले नए गेहूं के भंडारण की चुनौती

हलचल

सेंसेक्स 85 .55 अंकों की तेजी के साथ 39,046 .34 पर बंद, निफ्टी 19 .35 अंकों के उछाल के साथ 11,691 .50 पर पहुंचा

धातु, ऊर्जा में खरीदारी से शेयर बाजार सुधरे

मुंबई, प्रेट्र : धातु, ऊर्जा व आइटी शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार में चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला रुक गया और गुरुवार को प्रमुख सूचकांकों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले हालांकि निवेशकों ने बाजार में बढ़चढ़कर पूंजी नहीं लगाई। बीएसई का सेंसेक्स 85.55 अंकों की तेजी के साथ 39,046.34 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 19.35 अंकों की तेजी के साथ 11,691.50 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में वेदांता सर्वाधिक 2.47 फीसद उछला। इसके बाद कोल इंडिया में 2.02 फीसद, पावर ग्रिड में 1.88 फीसद, आइसीआइसीआइ बैंक में 1.88 फीसद, इन्फोसिस में 1.38 फीसद और एचसीएल टेक में 1.28 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर यस बैंक में सर्वाधिक 5.94 फीसद गिरावट रही। बीएसई पर जेट एयरवेज में 40.78 फीसद गिरावट रही।

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के ऑयल एंड गैस सेक्टर में सर्वाधिक 1.13 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा में सर्वाधिक 0.55 फीसद गिरावट रही। बीएसई में मिडकैप इंडेक्स में 0.08 फीसद तेजी रही, जबकि स्मॉलकैप में 0.42 फीसद गिरावट रही। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि फेडरल रिजर्व का फैसला आने तक निवेशक बाजार में फूंक-फूंक कर कदम रखेंगे। विश्लेषकों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व अपनी मुख्य नीतिगत दरों को जस की तस रखेगा। फेड का फैसला बुधवार को बाजार बंद होने के बाद आएगा।

पिछले कुछ समय से बाजारों को नहीं मिल रही ठोस सकारात्मक दिशा। फाइल

एचडीएफसी एएमसी करीब सात फीसद लुढ़का

नई दिल्ली : एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी (एचडीएफसी एएमसी) के शेयर बीएसई पर 6.32 फीसद गिरकर 1,807.75 रुपये पर बंद हुए। कंपनी ने सोमवार को बीएसई को दी गई सूचना में कहा था कि उसने एचडीएफसी एमएफ के कुछ फिक्स्ड मैच्युरिटी प्लान (एफएमपी) को नकदी सुविधा देने का फैसला किया है। इन योजनाओं का कुछ एक्सपोजर एडिसंस इन्फ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स और स्प्रिट इन्फ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (एनसीडी) में है, जिसके कारण उन्हें नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एनसीडी जारी करने वाली ये कंपनियां एस्सेल समूह की सहायक इकाई हैं।

सोना 100 रुपये संभला, चांदी 130 रुपये उछली

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के चलते घरेलू बाजार में निवेशकों ने सोना और चांदी की खरीद में दिलचस्पी दिखाई। इसके चलते मंगलवार को सोना 100 रुपये चढ़कर 33,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी ने भी 130 रुपये की छलांग ली और कारोबार के आखिर में 38,220 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में सोने के भाव में 100 रुपये की गिरावट देखी गई थी।

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को विदेशी बाजारों में पीली धातु के प्रति निवेशकों में उत्साह अच्छा उत्साह दिखा। इसलिए घरेलू बाजार में भी निवेशकों ने सोने की खरीद में दिलचस्पी दिखाई। दूसरी तरफ, चांदी को औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं का पूरा साथ मिला।

न्यूयॉर्क में सोने का हाजिर भाव बढ़त के साथ 1,344.90 डॉलर और चांदी का भाव 14.96 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 100 रुपये चढ़कर 33,720 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना 33,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने की आठ ग्राम की गिन्नी 26,800 रुपये प्रत्येक के भाव पर बनी रही।

चांदी हाजिर 130 रुपये चढ़कर 38,220 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 140 रुपये उछलकर 37,256 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 80,000 रुपये खरीद और 81,000 रुपये बिक्री के स्तर पर कायम रही।

प्रतीकात्मक

2027 तक चीन को पीछे छोड़ देगा भारत आबादी के मामले में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक विश्व की आबादी दो अरब बढ़कर 7.7 अरब से 9.7 अरब हो जाएगी।

अमेरिका में आबादी वृद्धि में भारतवंशी दूसरे स्थान पर

दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल शीर्ष पर

भारतीय अमेरिकियों की संख्या

44,02,363	38.3%	31,83,063
2017	इजाफा	2010

साल 2010 से 2017 के सात वर्षों के दरम्यान भारतीय मूल के लोगों की संख्या अमेरिका में तेजी से बढ़ी है। वृद्धि के लिहाज से एशियाई देशों में यह दूसरे स्थान पर है। 206.6 फीसद के साथ नेपाल पहले तो 38.3 फीसद के साथ भारत दूसरे पायदान पर है। साउथ एशियन एडवोकेसी ग्रुप साउथ एशियन अमेरिकंस लीडिंग टूगेदर (साल्ट) की ताजा जनसांख्यिकीय रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं।

बिना वैध दस्तावेज के

रिपोर्ट बताती है कि 6.3 लाख भारतीय अमेरिका में ऐसे हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। 2010 की इनकी संख्या में 72 फीसद इजाफा दिखा है। इनमें ज्यादातर ऐसे अप्रवासियों की संख्या है जिनकी वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है फिर भी वे अमेरिका में रहे हैं। 2016 में ऐसे लोगों की संख्या 2.5 लाख थी।

अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोग

सभी दक्षिण एशियाई देशों से अमेरिका बसने वाले लोगों की संख्या 2010 में 35 लाख थी। 2017 में यह बढ़कर 54 लाख हो गई। 44 लाख के साथ भारत की इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी है।

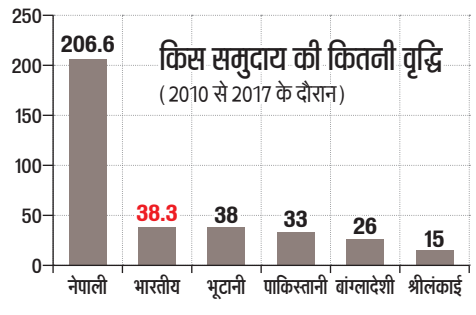

आश्रय मांगने वालों की संख्या

पिछले दस साल में अमेरिका की चमक-दमक देखते हुए वहां शरण लेने वालों की संख्या में तेज इजाफा हुआ है। अमेरिकी इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने 2017 से अब तक दक्षिण एशियाई मूल के 3013 लोगों को पकड़ा है। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर पैट्रोल ने अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2018 के बीच 17119 दक्षिण एशियाई लोगों को गिरफ्तार किया है।

एच-4 वीजा धारक

रिपोर्ट के अनुसार 1997 से 17 लाख एच-1बी वीजा धारकों के आश्रितों (पत्नियों) को एच-4 वीजा दिया जा चुका है।

घरेलू आय

बांग्लादेशी और नेपाली समुदायों की घरेलू आय सभी एशियाई अमेरिकी समूहों में सबसे कम है। बांग्लादेशियों की औसत आय 49,800 डॉलर है तो नेपालियों के लिए यह आंकड़ा 43,500 डॉलर का है।

आय की असमानता

रिपोर्ट के अनुसार 54 लाख कुल दक्षिण एशियाई लोगों में से करीब दस फीसद लोग गरीबी से ग्रस्त हैं। इनकी संख्या करीब 4.72 लाख है।

किस समुदाय में कितनी गरीबी

(फीसद में)

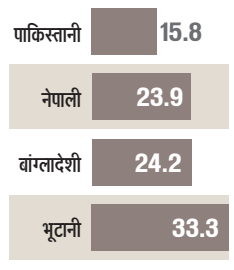

बड़ा वोट बैंक

रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को 2020 के चुनाव के लिए एक बड़े वोट बैंक के रूप में दिखाया गया है। इनकी कुल आबादी में से करीब आधे लोग (49.9 फीसद) वोट देने की उम्र में हैं। 2016 में इन लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। एशियाई अमेरिकी मतदाताओं की संख्या पिछले एक दशक में दोगुना हो चुकी है। 2001 में इनकी संख्या 20 लाख से बढ़कर 2016 में 50 लाख हो चुकी है। इनमें भारतीयों की हिस्सेदारी 15 लाख से अधिक है। पाकिस्तानियों की संख्या 2.22 लाख और बांग्लादेशियों की संख्या 69,825 है।

सख्त तेवर ▶ अगले सप्ताह से अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट एजेंसी करेगी कार्रवाई

अवैध प्रवासी किए जाएंगे बाहर : ट्रंप

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं 1.20 करोड़ लोग

वाशिंगटन, रायटर : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारी अगले हफ्ते से उन प्रवासियों को देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे जो यहां अवैध रूप से रह रहे हैं। अनुमान है कि अमेरिका में करीब एक करोड़ 20 लाख लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध मेक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों से है।

अमेरिका में प्रवासी मामलों को देखने वाली एजेंसी इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (आइसीई) का जिक्र करते हुए ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट किया, 'आइसीई अगले हफ्ते से उन लाखों अवैध लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगी जो अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं।' हाल में शरणार्थी मसले पर अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक समझौते का एलान किया गया था। इस समझौते के तहत मेक्सिको मध्य अमेरिकी देशों के उन नागरिकों को वापस लेगा जो अमेरिका में शरण मांग रहे हैं। मेक्सिको ऐसे शरणार्थियों को रोकने के लिए अमेरिका से लगती सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने को भी राजी हुआ है।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि मेक्सिको ने अगर समझौता नहीं किया तो उसके यहां से अमेरिका में आने वाले सामान पर पांच फीसद शुल्क लगा दिया जाएगा। यह शुल्क हर माह तब तक बढ़ता जाएगा, जब तक वह समझौते को राजी नहीं होता।

मध्य अमेरिका में शरण लेने के लिए रियो ब्रावो नदी को पार करते शरणार्थी। रायटर

मध्य पूर्व में नए विवाद न खड़े करे अमेरिका : चीन

बीजिंग, एएफपी : चीन ने अमेरिका को मध्य पूर्व में नए विवाद खड़े करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में 1000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने की घोषणा की है। ईरान के साथ तनातनी जारी रहने के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उनका देश ईरान पर दबाव बनाए रखेगा।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को तेहरान से आसानी से परमाणु करार से पीछे नहीं हटने का आग्रह किया। ईरान ने कहा है कि यदि विश्व शक्तियां समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रहती हैं तो वह अपने यूरेनियम भंडार में वृद्धि शुरू कर देगा। अमेरिका ने सोमवार को ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने की घोषणा की। तस्वीर पेश कर उसने कहा है कि पता चलता है कि पिछले सप्ताह ओमान की खाड़ी में टैंकर पोतों पर हुए हमले में तेहरान का हाथ था।

एच-4 वीजाधारकों की अभी बनी रहेगी नौकरी

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में अभी एच-4 वीजाधारकों से रोजगार का अधिकार वापस लेने संबंधी नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसलिए ऐसे लोग पहले की ही तरह नौकरी करते रह सकेंगे। अमेरिका में एच-1बी वीजाधारकों के पति/पत्नी को एच-4 वीजा दिया जाता है। एच-1बी वीजाधारकों में बड़े पैमाने पर भारतीय आइटी पेशेवर हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में कुछ एच-4 वीजाधारकों को रोजगार की अनुमति देने का फैसला किया गया था। सत्ता संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इस तरह के प्रावधान को खत्म करने की योजना बना रहे हैं।

▶ **ओबामा के कार्यकाल में मिली थी अनुमति, प्रावधान के खिलाफ हैं ट्रंप**

हालांकि अब तक इस संबंध में नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ट्रंप प्रशासन पिछले दो साल में इस संबंध में अधिसूचना को कई बार टाल चुका है। एक अधिकारी के मुताबिक, आव्रजन अधिकारी पहले की ही तरह रोजगार आधारित वीजा की श्रेणी में एच-4 वीजा की समीक्षा कर रहे हैं। एच-4 वीजाधारकों की नौकरी पर रोक के नियम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। हाल ही में अमेरिका के गृह मंत्रालय ने अपने वार्षिक एजेंडा में फिर एच-4 वीजाधारकों को रोजगार की अनुमति देने का प्रावधान खत्म करने पर जोर दिया था।

अमेरिका कभी भी गुल कर सकता है रूस की बत्ती

न्यूयॉर्क टाइम्स से

▶ **रूस ने चेताया, अमेरिका के साथ गहरा सकता है साइबर वार**

मॉस्को : अमेरिका और रूस के तनाव भरे संबंधों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जो साइबर वार का कारण बन सकती है। खबर है कि रूस के इलेक्ट्रिक पॉवर ग्रिड को अमेरिका हैक कर रहा है। इससे रूस की बत्ती कभी भी गुल की जा सकती है। इस खबर पर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने सोमवार को आगाह किया कि अमेरिका के साथ साइबर वार गहरा सकता है। इसके साथ ही यह विश्वास भी जताया कि हमारा सिस्टम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमलों को रोकने में सक्षम है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दमित्री एस पेस्कोव ने यह चिंता भी जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रयास के बारे में जानकारी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, रूस के एनर्जी सिस्टम और दूसरे लक्ष्यों में अमेरिका ने साइबर टूल्स लगा दिए हैं।

अमेरिका के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों में बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ने की सूरत में इस प्रोग्राम के जरिये रूस के पॉवर ग्रिड पर हमला किया जा सकता है। अखबार का कहना है कि यह कदम उन चेतावनियों के बाद उठाया गया जिसमें इसी तरह के आक्रामक रवैये के लिए रूस को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों सालों से चेतावनी दे रही थीं। यह हालांकि स्पष्ट नहीं है कि रूसी पॉवर ग्रिड में कितनी गहराई तक यह तथाकथित साफ्टवेयर लगाया गया है। पेस्कोव ने कहा, 'इस जानकारी का मतलब यह है कि रूस के खिलाफ साइबर हमले की काल्पनिक संभावना है।'

रूसी पॉवर ग्रिड की पुख्ता है सुरक्षा

रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'हमारे सिस्टम के खिलाफ किसी हमले की कोई सूचना नहीं मिली है। रूसी एनर्जी पॉवर ग्रिड की सुरक्षा बेहद उच्च है। इस तरह के खतरों से निपटने के लिए रूसी तकनीक और उपकरणों को उन्नत करने पर काम किया जा रहा है।'

साइबर क्राइम का सबसे बड़ा स्रोत है रूस

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि रूस साइबर क्राइम का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके निर्देश पर ही अमेरिकी सिस्टम को निशाना बनाया जाता है। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने यह जानकारी दी थी कि रूसी खुफिया एजेंटों ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका की मतदान प्रणाली तक पहुंच बनाने का प्रयास किया था।

यूएस में पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद भारतवंशी ने दी थी जान

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के आयोवा प्रांत की पुलिस ने भारतवंशी आइटी पेशेवर चंद्रशेखर सुनकारा (44) और उनके परिवार के तीन सदस्यों की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने कहा है कि चंद्रशेखर ने पत्नी और दो बेटों की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकशी कर ली थी।

आंध्र प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लावण्या और बेटे प्रभाष (14) व सुहास (11) वेस्ट डेस मोइनेस स्थित अपने घर में शनिवार सुबह रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। सभी के शरीर पर गोली लगने के निशान थे। फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि चंद्रशेखर ने आत्महत्या की थी। जबकि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने सोमवार को एक कहा, 'लावण्या और दो बच्चों की जिस तरह मौत हुई, वह हत्या है। जबकि चंद्रशेखर की मौत का तरीका आत्महत्या का है। जांचकर्ता अभी मामले की जांच कर रहे हैं।'

▶ **इसी साल अप्रैल में चंद्रशेखर मिला था हथियार रखने का परमिट**

आयोवा सार्वजनिक सुरक्षा विभाग (डीपीएस) ने बताया है कि चंद्रशेखर टेक्नोलाजी सर्विस ब्यूरो में बतौर आइटी पेशेवर काम कर रहे थे। पिछले साल उनकी आय एक लाख पांच हजार डॉलर (करीब 73 लाख रुपये) थी। डलास काउंटी के शेरिफ चाड लियोनार्ड के अनुसार, चंद्रशेखर को इसी साल अप्रैल में हथियार रखने का परमिट मिला था। इसके बाद उन्होंने एक हथियार खरीदा था।

न्यूज गैलरी

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा को दो मामलों में जमानत

ढाका : बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को मानहानि के दो मामलों में जमानत मिल गई है। भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की सजा काट रहीं जिया जमानत के बाद भी रिहा नहीं हो पाएंगी। जिया पर 2014 और 2016 में मुसलमानों की भावनाएं को ठेस पहुंचाने और बांग्लादेश के जनक शेख मुजीब पर आपत्तिजनक बयान देने पर मानहानि के मुकदमे किए गए थे। (प्रेट्र)

आतंकी हमले का वीडियो शेयर पर न्यूजीलैंड में 21 माह की जेल

वेलिंगटन : गत 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में गोलीबारी की आतंकी वारदात को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर फिलिप नेविले को 21 महीने की सजा सुनाई गई है। न्यूजीलैंड में आपत्तिजनक वीडियो बनाना, रखना और शेयर करना अपराध है, जिसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। गोलीबारी में 51 लोगों की जान गई थी। (एएनआइ)

इंडोनेशिया में डूबी नौका, 17 मरे

जकार्ता : इंडोनेशिया के जावा द्वीप में खराब मौसम के कारण यात्रियों से भरी एक मोटरबोट के समुद्र में डूबने से 17 लोगों की मौत हो गई। इनमें चार बच्चे भी हैं। हादसा सोमवार को हुआ। मोटरबोट पर क्षमता से ज्यादा कुल 57 लोग सवार थे। (रायटर)

जमात-उद-दावा के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजेगी पाक सरकार

लाहौर, प्रेट्र : मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा (जेयूडी) व फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन (एफआइएफ) द्वारा संचालित कथित मदरसों के छात्रों को पाकिस्तान सरकार शासकीय स्कूलों में दाखिला दिलाएगी। इन संगठनों को दी गई 180 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पर टेरर फंडिंग की अंतरराष्ट्रीय निगरानीकर्ता संस्था द्वारा जताई गई आपत्ति के बाद सरकार ऐसी योजना बना रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाक सरकार द्वारा जेयूडी और एफआइएफ के मदरसों को दी गई वित्तीय सहायता पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, 'सरकार एफएटीएफ को यह विश्वास दिलाने में नाकाम रही कि मार्च में नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद अच्छी संख्या में जेयूडी व एफआइएफ के मदरसों तथा स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में इमरान खान सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि वहां पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाए।' अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा दोनों संगठनों को इतनी बड़ी राशि देने पर एफएटीएफ सशंकित है।

गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तानी सरकार को जैश ए मुहम्मद, जेयूडी और एफआइएफ द्वारा संचालित मदरसों को या तो सील करना पड़ा था या उनका संचालन अपने हाथ में लेना पड़ा था।

विश्व बैंक पाकिस्तान को देगा 6400 करोड़ रुपये का कर्ज

इस्लामाबाद, प्रेट्र: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने विश्व बैंक के साथ लगभग 6400 करोड़ रुपये के कर्ज वाले तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉन न्यूज ने प्रधानमंत्री इमरान खान के आर्थिक सलाहकार के हवाले से बताया कि इस पैसे का उपयोग तीन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान राजस्व कार्यक्रम और उच्च शिक्षा विकास में से प्रत्येक पर जहां लगभग 2800 करोड़ रुपये खर्च होंगे, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में राजस्व जुटाने और संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

▶ **तीन समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर, उच्च शिक्षा विकास में लगाएंगे 2800 करोड़**

▶ **पिछले महीने ही आइएमएफ से लिया है 42 हजार करोड़ का बेलआउट पैकेज**

इमरान खान। फाइल

समझौतों पर विश्व बैंक के कंट्री हेड पेटचमुथु इलंगोवन ने जहां दस्तखत किए, वहीं पाकिस्तान की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव नूर अहमद, उच्च शिक्षा आयोग के प्रतिनिधियों और खैबर पख्तूनख्वाह सरकार ने हस्ताक्षर किए।

बताया गया है कि राजस्व कार्यक्रम के तहत कर आधार बढ़ाने और उसके अनुपालन को सुविधाजनक बनाने पर 2800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के कर लक्ष्य को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 17 प्रतिशत तक बढ़ाना है। साथ ही सक्रिय करदाताओं की संख्या 35 लाख तक बढ़ाना है। 800 करोड़ रुपये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में राजस्व जुटाने और संसाधन प्रबंधन के लिए किया जाएगा। इमरान के आर्थिक सलाहकार ने देश के सतत आर्थिक विकास के लिए पाकिस्तान की सरकार को अपना निरंतर समर्थन देने के लिए विश्व बैंक का आभार जताया है। बता दें कि पाकिस्तान भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए आइएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष), विश्व बैंक और एडीबी (एशियाई विकास बैंक) जैसे कई वित्तीय संस्थानों से मदद मांग रहा है। पिछले महीने ही उसने तीन साल के लिए आइएमएफ के साथ लगभग 42 हजार करोड़ रुपये के बेलआउट पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

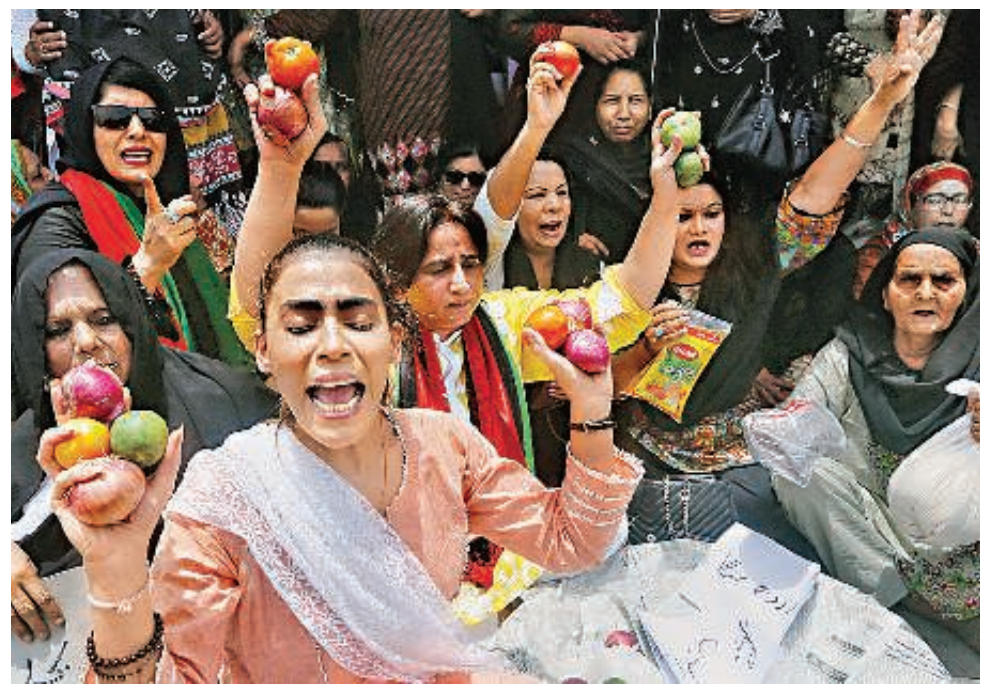

पाकिस्तान में महंगाई पर उबाल...

आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके पाकिस्तान में महंगाई उछाल पर है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है। विपक्षी राजनीतिक दल भी महंगाई के मुद्दे पर मुखर हो गए हैं। मंगलवार को लाहौर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्याज, टमाटर आदि लेकर ऊंची खाद्य कीमतों पर आक्रोश जताया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की जनता को महंगाई ने बेहाल कर रखा है। मई माह में खाद्य पदार्थों और ईंधन के दामों में जोरदार बढ़ोतरी से मई में महंगाई की वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति एक माह पहले की 8.82 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 9.11 प्रतिशत पर पहुंच गई। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा बीते दिनों जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई में मुद्रास्फीति की औसत दर 7.19 प्रतिशत रही। मई-19 में थोक मूल्य सूचकांक की महंगाई 1.43 प्रतिशत और संवेदनशील मूल्य सूचकांक 0.78 प्रतिशत उछल गया। ब्यूरो के अनुसार मुद्रास्फीति को बढ़ाने में मुख्य रूप से ईंधन और खाद्य पदार्थों का योगदान रहा। एपी

यूट्यूब ने हटाए नफरत फैलाने वाले 90 लाख वीडियो : सुंदर पिचाई

वाशिंगटन, प्रेट्र : गूगल के भारतवंशी अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने कहा है कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग साइट यूट्यूब ने अपनी नीतियों के तहत नफरत फैलाने वाले तथा नुकसानदेह वीडियो को हटाने का काम शुरू कर दिया है। पिछली तिमाही में उसने करीब 90 लाख ऐसे वीडियो हटाए भी हैं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्लेटफार्म काफी बड़ा हो चुका है और ऐसी सामग्री को पूरी तरह हटाना आसान नहीं है।

पिचाई ने सीएनएन को बताया, 'हम इसे दुरुस्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बावजूद कुछ ही वर्षों में यह महसूस करते हैं कि इसे और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्लेटफार्म के इस्तेमाल का तरीका बदल चुका होता है।' उन्होंने कहा, 'पिछली तिमाही में ही हमने 90 लाख वीडियो हटाए। यह प्रक्रिया अब भी जारी है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि अभी और करने की जरूरत है।' यूट्यूब की विवादास्पद सामग्री की पिछले वर्षों में काफी आलोचना हुई है।

पाक के दोहरे वीजा के फैसले का सिखों को होगा फायदा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के एक सिख नेता ने गुरुनानक देव की 550 वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे की यात्रा के लिए समुदाय के 10,000 श्रद्धालुओं को दोहरे प्रवेश वीजा सुविधा की अनुमति देने के सरकार के फैसले की सराहना की है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान सरकार ने बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर के विकास के लिए 2019-20 के संघीय बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

'दुनिया न्यूज' के मुताबिक, पंजाब के प्रांतीय संसदीय सचिव सरदार महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि गुरुनानक देव की जयंती छह नवंबर को मनायी जाएगी। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर को भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे के साथ जोड़ेगा और इससे भारत के सिख श्रद्धालुओं को बिना वीजा के वहां जाने में मदद मिलेगी। उन्हें करतारपुर साहिब जाने के लिए केवल अनुमति लेनी होगी। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना में 1522 में गुरुनानक देव ने की थी।

▶ **गुरुनानक देव की 550 वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे की यात्रा के लिए समुदाय के 10,000 श्रद्धालुओं जाएंगे पाक**

खासकर वीजा सुविधा, ऑनलाइन वीजा और आगमन पर वीजा के लिए सरकार की हालिया पहल का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि इन कदमों से हजारों सिखों को फायदा होगा और धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ेगा। उन्होंने गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती के अवसर पर 10,000 सिख श्रद्धालुओं को वीजा सुविधा देने के सरकार के फैसले की सराहना की। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने बीते दिनों गुरुद्वारा के दर्शन के लिए आने वाले सिख श्रद्धालुओं से 20 यूएस डॉलर (लगभग 3127 रुपए) वूलने का एक प्रस्ताव भी रखा था। उम्मीद है कि हर दिन लगभग 10 हजार श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे।

अमेरिका के सुझाव पर अफगान सेना बंद कर रही सैन्य चौकियां

काबुल, एएफपी : अफगानिस्तान की सेना ने लगातार तालिबान का निशाना बन रही सैन्य चौकियों को बंद करना शुरू कर दिया है। इनकी जगह बड़े सैन्य अड्डे बनाए जाएंगे। अफगान सेना को यह सुझाव अमेरिका ने दिया था। दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा को लेकर बनाई गई छोटी चौकियों पर आए दिन आतंकी हमले करते रहते हैं। इन हमलों में अभी तक हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है।

अफगान सेना के शीर्ष अफसर जनरल दादान लवांग ने कहा, सैन्य चौकियां अब काम की नहीं रहीं। आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले 50 फीसद सुरक्षाकर्मी इन चौकियों में ही शहीद हुए। नई योजना का मकसद सेना की कार्रवाई को उस स्तर तक पहुंचाना है जहां अफगान सैनिक आगे बढ़कर आतंकियों को निशाना बना सकें, ना कि उनसे बचने के उपाय करें। अफगान मिशन पर तैनात नाटो सेना के प्रमुख जनरल स्कॉट मिलर ने भी कहा है कि सैन्य चौकियों को बंद करना एक निर्णायक कदम है।

दुनिया से 600 परमाणु हथियार कम हुए, बाकी की क्षमता बढ़ी

स्टॉकहोम, एएफपी : दुनिया में पिछले एक साल के दौरान परमाणु हथियारों की संख्या तो कम हुई लेकिन उनकी क्षमता बढ़ाने का कार्य जोर-शोर से हुआ। इस समय दुनिया में कुल 13,865 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया की सारी आबादी को कई बार खत्म कर सकते हैं। यह जानकारी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान की रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 रह गई। यह संख्या 2018 के कुल परमाणु हथियारों से 600 कम है। मतलब साफ है कि चालू वर्ष में मानव इतिहास के सबसे संहारक हथियार कम हुए। लेकिन इस दौरान परमाणु हथियार संपन्न सभी देशों ने अपने हथियारों के जखीरे का आधुनिकीकरण किया है। हालांकि चीन, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ाया भी है। जिन देशों ने अपने हथियारों की संख्या में कटौती की है वे अमेरिका और रूस हैं। इन्हीं दोनों देशों के पास कुल संख्या के 90 फीसद परमाणु हथियार हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार बनाने का मुकाबला 2010 में हुई स्टार्ट संधि से रुका था। इसी के बाद शीत युद्ध काल का खात्मा हुआ था। दोनों देशों ने बड़ी संख्या में अपने-अपने परमाणु हथियार नष्ट किए थे। शीत युद्ध काल में एक समय तो दुनिया के परमाणु हथियारों की संख्या 70 हजार के करीब पहुंच गई थी।

▶ **भारत, पाकिस्तान और चीन संख्या बढ़ा रहे हैं और क्षमता भी**

▶ **शीत युद्ध काल में 70 हजार हो गए थे संहारक अस्त्र**

संस्थान के निदेशक शेनन काइले के अनुसार इस साल दुनिया ने थोड़े से ही लेकिन नई तरह के परमाणु हथियार देखे हैं। परमाणु हथियारों की मौजूदा संख्या भी बहुत है लेकिन उनकी क्षमता बढ़ाने की कवायद को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरे दौर में जीते बोरिस जॉनसन

लंदन, रायटर/प्रेट्र : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे की जगह लेने की दौड़ में आगे चल रहे लंदन के पूर्व मेयर और विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन को मंगलवार को दूसरे दौर के मतदान में सबसे ज्यादा 126 मत मिले। विदेश सचिव जेरेमी हंट को 46 और पर्यावरण मंत्री माइकल गोव को 41 वोट मिले। 37 वोट के साथ अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री रोरी स्टीवर्ट चौथे स्थान पर रहे। गृह मंत्री साजिद जाविद पांचवें स्थान पर आए। उन्हें 33 मत मिले हैं। अब शेष प्रत्याशी मतदान के अगले चरण का सामना करेंगे जिसके बाद मैदान में दो रह जाएंगे। उसके बाद कंजरवेटिव के सदस्य तय करेंगे कि नेता और ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अंतिम फैसले के लिए पार्टी के 1,60,000 जमीनी कार्यकर्ताओं से पोस्टल बैलेट मंगाए जाएंगे। विजेता का फैसला 22 जुलाई तक होने की उम्मीद है। पहले दौर के मतदान में 114 सांसदों के समर्थन के साथ बोरिस जॉनसन सबसे आगे रहे थे। हंट को 43, गोव को 37, डोमिनिक राब को 27, जाविद को 23 वोट मिले थे।

ये भी जानिए
इयोन मोर्गन वनडे में 200 छक्के लगाने वाले विश्व के आठवें बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी शीर्ष पर हैं जिन्होंने 351 छक्के जड़े हैं।

मैनचेस्टर में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को कुलदीप यादव ने इस गेंद पर बोल्ड किया ● फाइल फोटो, एएफपी

कुलदीप की ड्रीम बॉल

साउथैंप्टन : कुलदीप यादव ने मैनचेस्टर में पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के खिलाफ महज 78 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाई और फिर बहुत तेजी से अंदर आकर बाबर के विकेट ले उड़ी। इस गेंद ने 5.80 डिग्री का टर्न लिया था और रफ्तार बेहद कम होने के बावजूद बाबर गच्चा खा गए। गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकल गई। कुलदीप के आदर्श ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शेन वार्न की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' ने 14 डिग्री का टर्न लिया था, जिस पर माइक गेटिंग आउट हुए थे। इसी ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 26 साल पहले शेन वार्न ने 1993 के एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड के माइक गेटिंग को बोल्ड किया था।

कुलदीप यादव

- **पहला घरेलू टी-20 मैच :** 31 मार्च 2014, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उप्र के लिए रेलवे के खिलाफ चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट
- **पहला प्रथम श्रेणी :** 22-25 अक्टूबर 2014, दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र के लिए उत्तर क्षेत्र के खिलाफ 77 रन और तीन विकेट
- **पहला लिस्ट-ए मुकाबला :** 07 नवंबर 2014, विजय हजारे ट्रॉफी में उप्र के लिए रेलवे के खिलाफ दो विकेट
- **पहला टेस्ट :** 25-28 मार्च, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में चार विकेट
- **पहला वनडे मैच :** 23 जून 2017, वेस्टइंडीज के खिलाफ बारिश के कारण गेंदबाजी ही नहीं आई, दूसरे मैच में तीन विकेट चटकाए
- **पहला अंतरराष्ट्रीय टी-20 :** 09 जुलाई 2017, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच का एकमात्र विकेट लिया

गेंदबाज है या जादूगर

- पहेली बनी बाबर का विकेट लेने वाली कुलदीप की गेंद
- कोच कपिल ने कहा, यादव हजारों बार फेंक चुका है यह गेंद

विश्व कप में दैनिक जागरण
अभिषेक त्रिपाठी ● साउथैंप्टन

जब कोई गेंदबाज, जादूगर बन जाए तो सामने वाले का सब कुछ लुटना तय है... कुछ ऐसा ही कानपुर के छोरे चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने रविवार को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ किया। उन्होंने जिस 'ड्रीम बॉल' पर बाबर आजम को बोल्ड किया उसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है। हालांकि, उनके कोच कपिल देव पांडे ने कहा कि उनका शिष्य हजारों बार यह गेंद कर चुका है और ऐसी ही गेंद पर उसने धर्मशाला में अपने पहले टेस्ट मैच में पीटर हैंड्सकोंब को आउट किया था।

पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम मुकाबले में भारत ने डकवर्थ-लुइस नियम के तहत 89 रनों से जीत दर्ज की थी। उस मैच में रोहित शर्मा ने शतक लगाया था और भारत ने पाकिस्तान को 337 का लक्ष्य दिया। एक समय फखर जमां और बाबर आजम की साझेदारी भारत के लिए खतरा बन रही थी, जिसे कुलदीप ने तोड़ा। कुलदीप के कोच कपिल देव पांडे ने दैनिक जागरण से कहा कि वह ड्रिफ्ट गेंद थी, चाइनामैन गेंद नहीं थी। कुलदीप ने उसे थोड़ा फ्लाइट किया था, जो ड्रिफ्ट होकर विकेट पर गई। इसके लिए आपको बॉर्डी कोआर्डिनेशन की जरूरत होती है। उसे वहां हवा का भी अच्छा सहयोग मिला। इस पूरे संयोजन ने उस गेंद को शानदार बना दिया। हवा से गेंद अंदर की तरफ आई। जब उनसे पूछा गया कि आपने उन्हें कितनी बार यह गेंद करते हुए देखा है तो उन्होंने कहा कि कुलदीप ने हजारों बार यह गेंद फेंकी हैं। हम नेट पर उस गेंद के लिए घंटो अभ्यास करते थे। इस गेंद को फेंकने के लिए कुलदीप राउंड द विकेट अभ्यास करते हैं। आपको याद होगा कि धर्मशाला में पहले टेस्ट में कुलदीप ने इसी गेंद पर हैंड्सकांब को आउट किया था।

कुलदीप ने इस गेंद के बारे में कहा कि बारिश से मिले ब्रेक के बाद मैं पवेलियन गया और मैंने वह गेंद देखी। गेंद ड्रिफ्ट हुई थी और फिर टर्न ले गई थी। हर स्पिनर इस गेंद को पसंद करेगा। यह एक शानदार ड्रीम डिलिवरी और टेस्ट मैच की गेंद थी। मैंनें बल्लेबाज को हवा में छकाया और उसे गलती करने को मजबूर किया। कुलदीप ने एशिया कप में भी बाबर आजम को आउट किया था। कप्तान विराट कोहली ने भी कुलदीप की तारीफ करते हुए कहा था कि बाबर को जिस गेंद पर कुलदीप ने बोल्ड किया वह बेहतरीन गेंद थी। उसमें ड्रिफ्ट था, टर्न था। इंग्लैंड में आकर वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।

दायें हाथ के बल्लेबाज को होती है मुश्किल : इस गेंद के सामने दायें हाथ के बल्लेबाज को होने वाली मुश्किल के बारे में पूछने पर कपिल ने कहा कि दायें हाथ से खेलने वाले बाबर इस गेंद को समझ ही नहीं पाए। वह सोच रहे थे कि यह गेंद गुगली होगी या बाहर की ओर निकलेगी या ज्यादा स्पिन नहीं होगी। वह खड़े ही रह गए। वह गेंद को पढ़ नहीं सके। कुलदीप जब गेंद को हवा में फ्लाइट करते हैं तो बल्लेबाज के लिए असमंजसस की स्थिति रहती है कि वह खेले कि रोके, इसीलिए हर स्पिनर के लिए गेंद को फ्लाइट करना बहुत जरूरी है।

आसान नहीं है यह गेंद फेंकना : जब कपिल से पूछा गया कि यह गेंद फेंकना कितना मुश्किल है तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। इसके लिए आपको अपना वजन ट्रांसफर करना होता है। इसमें लेंथ और फ्लाइट के साथ बदलाव करना होता है। लूप के साथ गेंद फेंकने से फायदा मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दो स्पिनर शेन वार्न और मुरलीधरन ने हमेशा हवा में ज्यादा देर तक गेंद फेंकी। वे फ्लाइट करते थे और गेंद को अपनी तरफ खींचते थे। आप अगर ध्यान से देखें तो वार्न अपने शुरुआती दौर में रन खाते थे, लेकिन बाद में वह महान गेंदबाज बने। कुलदीप से वार्न की तुलना पर उन्होंने कहा कि दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए।

मेरा सपना पूरा किया : मेरा सपना था कि कुलदीप इस तरह से अंतरराष्ट्रीय मैच में किसी बल्लेबाज को बोल्ड करे। उसने नेट पर और जूनियर मुकाबलों में कई बार ऐसा किया था और कई खिलाड़ियों को बोल्ड मारा था। उसने 2017 में धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हैंड्सकोंब को बोल्ड किया तो हमारे यहां अभ्यास करने वाले एक बच्चे रिषभ ने उससे कहा कि तुमने सर का सपना पूरा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विश्व कप के दो मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने पर दबाव में होने के सवाल पर कुलदीप ने कहा कि यह दबाव वाला मैच था। मैंने उससे कहा था कि छोटे मैच में विकेट लोगे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में करोगे तो सब पूछेंगे। उसने वैसे ही किया। उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शांतचित्त होकर चढ़कर गेंदबाजी की। मैंने उससे कहा है कि थोड़ी सी गुगली और बढ़ाओ। वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चार-पांच और गुगली फेंक सकता था। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुलदीप के रिदम खोने के सवाल पर कपिल ने कहा कि उसने विश्व कप में कभी भी रिदम नहीं खोया था। मैंने उससे कहा कि जिस बल्लेबाजी विकेट पर एडम जांपा ने छह ओवर में 50 रन दिए वहां आपने नौ ओवर फेंके और 55 रन दिए। भारतीय प्रशंसकों की अपेक्षाएं होती हैं कि गेंदबाज को दो-तीन विकेट मिले। कुलदीप पर अपेक्षाओं का बोझ होता है। विश्व कप में कुलदीप को खेलते हुए देखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब वह कहेगा तो मैं आऊंगा।

मौके पर जादू दिखाने में माहिर कुलदीप

मैनचेस्टर : कुलदीप एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें सिर्फ मौके का इंतजार रहता है और जैसे ही मौका मिलता है वह दुनिया पर छा जाते हैं। वह चाहे सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का मुकाबला हो या विजय हजारे ट्रॉफी का मैच। चाहे पहला टेस्ट मैच हो, पहला वनडे या पहला विश्व कप। जब भी, जहां भी मौका मिला उसने खुद को साबित किया। 2004-05 में कानपुर के ऊबड़-खाबड़ मैदान से क्रिकेट का ककहरा शुरू करने वाला छोटा बच्चा अब 24 वर्ष की उम्र में भारतीय वनडे, टी-20 व टेस्ट टीम का स्थायी सदस्य बन गया है। उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम, भारतीय अंडर-19 टीम, उत्तर प्रदेश रणजी टीम, मध्य क्षेत्र, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइटराइडर्स में शामिल होने के बाद 2017 में कुलदीप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टेस्ट कैप मिली थी जिसमें उसने पहली पारी में ही चार विकेट हासिल करके खुद को साबित कर दिया था। धर्मशाला टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया 144/1 स्कोर पर पहुंच गया था तब कोहली की अनुपस्थिति में कप्तानी करने उतरे अजिंक्य रहाणे ने कुलदीप को गेंद थमाई और उन्होंने चार विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया। उन्हें इस मौके की कई वर्षों से तलाश थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा के अलावा अक्षर पटेल, जयंत यादव और अमित मिश्रा तक को मौका मिल रहा था। भारत को इस सीरीज को जीतने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था और इसीलिए कुलदीप को सरप्राइज पैकेज के तौर पर शामिल किया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को उन्हें खेलने का अनुभव नहीं था। उनकी बदौलत भारत ने सीरीज जीत ली। इसके बाद उन्हें वनडे और टी-20 में मौका नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका चुनाव नहीं हुआ। विंडीज दौरे पर उन्हें मौका दिया गया, लेकिन पहले वनडे में बारिश के कारण वह गेंदबाजी नहीं कर सके। दूसरे वनडे में उन्होंने नौ ओवर में 50 रन देकर तीन विकेट लिए। उस समय ही तय हो गया था कि कुलदीप भारत की विश्व कप योजना का हिस्सा होंगे और ऐसा हुआ भी। कुलदीप को 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल किया गया था, लेकिन तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं दिया। ऐसा भी समय आया जब वह कुछ निराश रहने लगे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की। कुलदीप जब 17 साल के थे तब उनका अंडर-19 विश्व कप में खेलना तय माना जा रहा था, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। दो साल बाद उन्हें इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला और उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली।

कुलदीप की गेंद पर गच्चा खाकर बोल्ड हो गए आजम ● फाइल फोटो, एपी

द. अफ्रीका के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती

बर्मिंघम, प्रेट्र : लुंगी नगिदी की वापसी से मजबूत हुई दक्षिण अफ्रीका की टीम बुधवार को यहां न्यूजीलैंड का सामना करने उतरेगी। दोनों टीमें जब मैदान पर उतरेंगी तो दक्षिण अफ्रीकी टीम का इरादा 2015 के विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने का होगा, जबकि न्यूजीलैंड की टीम फिर से अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान वापस पाना चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका को विश्व कप के पिछले संस्करण में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, इस बार उसका विश्व कप अभियान बेहद निराशाजनक अंदाज में शुरू हुआ। उसे अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर काबिज अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ एकमात्र जीत मिली है, लेकिन उससे पहले उसे शुरुआती तीन मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि उसके बाद अगला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था।

तेज गेंदबाज डेल स्टेन और एनरिच नार्त्जे के चोटिल होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी की गेंदबाजी कमजोर हुई है। नगिदी के पूरी तरह से फिट होकर लौटने और टीम के आखिरकार जीत का स्वाद चख लेने के बाद कप्तान फाफ डुप्लेसिस राहत की सांस लेंगे। एजबेस्टन की टर्न लेती पिच पर अनुभवी स्पिनर इमरान ताहिर पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बल्लेबाजी में हाशिम अमला और क्विंटन डिकॉक ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था।

उधर, स्पिनरों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टीम के बल्लेबाजों के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए पिछली बार की उप विजेता न्यूजीलैंड की टीम लेग स्पिनर ईश सोढ़ी को मिशेल सेंटनर के साथ उतार सकती है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का दारोमदार कप्तान केन विलियमसन, रॉस टेलर, कोलिन मुनरो और मार्टिन गुप्टिल उठाएंगे।

शतक पूरा करने के बाद इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ● एपी

मैनचेस्टर में जमकर बरसे मोर्गन

इयोन ने खेली 148 रनों की तूफानी पारी, इंग्लैंड ने अफगानिस्तान की टीम को 150 रनों से दी शिकस्त

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : इंग्लिश कप्तान इयोन मोर्गन मंगलवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर विश्व कप के मैच में अफगानिस्तानी गेंदबाजों पर जमकर बरसे। विश्व कप में बारिश के कारण कई मैच रद हुए, लेकिन जब मोर्गन ने बरसना शुरू किया तो अफगानी गेंदबाज उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। बायें हाथ के बल्लेबाज मोर्गन का बल्ला इस विश्व कप में शांत था और उन्होंने अपनी यह कसक अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर पूरी की। वह एक छोर से छक्कों की बारिश करते रहे। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के मुख्य स्पिनर राशिद खान की जमकर धुलाई की। मोर्गन ने 71 गेंदों में 148 रनों की पारी में चार चौके लगाए, जबकि 17 लंबे-लंबे छक्के जड़ दिए। यह उनके वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी है। उनके अलावा जॉनी बेयरस्टो (90) और जो रूट (88) की पारियों से इंग्लैंड ने 50 ओवर में छह विकेट पर 397 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में आठ विकेट पर 247 रन बनाकर मैच 150 रनों से हार गई।

हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान को सस्ते में समेट देगी और अफगानी टीम को 50 ओवर खेलने नहीं देगी। लेकिन अफगानिस्तान की टीम इस विश्व कप में पहली बार 50 ओवर खेलने में सफल रही। अफगानिस्तान की ओर से हसमतुल्लाह शाहिदी ने टीम के लिए सर्वाधिक 76 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 100 गेंदों का सामना किया जिसमें पांच चौके और दो छक्के जड़े। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स को तीन-तीन विकेट मिले। अफगानिस्तान को अभी भी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का इंतजार है जबकि इंग्लैंड इस जीत से शीर्ष पर पहुंच गया।

मोर्गन ने तोड़े रिकॉर्ड : कमर में दर्द से परेशान चले रहे मोर्गन का इस मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा था और उनको अंतिम एकादश में लाने का फैसला टीम प्रबंधन ने टॉस से पहले किया। मोर्गन ने अपनी पारी में कई रिकॉर्ड भी बनाए। वह वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस तरह वह वनडे इतिहास के पहले बल्लेबाज बने जिसने सिर्फ छक्कों के जरिये ही 100 रन बना डाले। उन्होंने इस विश्व कप का सबसे तेज शतक भी लगाया। मॉर्गन ने 57 गेंद पर छक्का जड़कर शतक पूरा किया। यह विश्व कप इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक है। विश्व कप में इससे तेज शतक आयरलैंड के केविन ओ ब्रायन (50 गेंद) के नाम है। साथ ही इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज का विश्व कप में यह सबसे तेज शतक है। इंग्लैंड की पारी में 25 छक्के लगे, जो विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले इंग्लैंड ने ही वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में 24 छक्के जड़े थे। मोर्गन ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती 25 गेंदों में 28 रन ही बना पाए थे, लेकिन इसके बाद मोर्गन ने रनों की गति ऐसी बढ़ाई कि अगली 46 गेंदों में 120 रन कूट डाले। मोर्गन ने 28 रन पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। इंग्लैंड की टीम ने अंतिम 15 ओवर में 198 रन बनाए।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम को बेयरस्टो और चोटिल जेसन रॉय की जगह खेल रहे जेम्स विंस (26) ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़कर सतर्क शुरुआत दिलाई। दौलत जादरान (3/85) ने विंस को आउट करके टीम को पहला झटका दिया। बेयरस्टो और रूट ने इसके बाद अगले 20 ओवर से अधिक समय तक अफगानिस्तान के गेंदबाजों को सफलता से महरूम रखा। बेयरस्टो ने स्पिनर रहमत शाह पर पारी का पहला छक्का जड़ा। रूट ने नायब की गेंद पर एक रन के साथ 20वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया। इस ओवर में बेयरस्टो ने चौके के साथ 61 गेंद में अर्धशतक जड़ा, जो वनडे में उनका सबसे धीमा अर्धशतक है। इसके बाद बेयरस्टो धीरे-धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जब 90 रन पहुंचे थे गुलबदीन नायब (3/68) ने पवेलियन भेज दिया। बेयरस्टो ने 99 गेंद की पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए जो रूट के साथ 120 रन की साझेदारी की। बेयरस्टो के आउट होने के बाद मोर्गन क्रीज पर उतरे और उन्होंने रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 189 रन की साझेदारी की। रूट छक्का जड़ने की कोशिश में नायब की गेंद पर आउट हुए।

स्कोर बोर्ड

टॉस : इंग्लैंड (बल्लेबाजी)

इंग्लैंड 397/6 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
जेम्स विंस का. मुजीब बो. दौलत	26	31	03	00
जॉनी बेयरस्टो का. एवं बो. नायब	90	99	08	03
जो रूट का. रहमत बो. नायब	88	82	05	01
इयोन मोर्गन का. रहमत बो. नायब	148	71	04	17
जोस बटलर का. नबी बो. दौलत	02	02	00	00
बेन स्टोक्स बो. दौलत	02	06	00	00
मोइन अली नाबाद	31	09	01	04
क्रिस वोक्स नाबाद	01	01	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-1, नोबॉ-1, वा-7) 9
कुल : 50 ओवर में छह विकेट पर 397 रन

विकेट पतन : 1-44 (विंस, 9.3), 2-164 (बेयरस्टो, 29.5), 3-353 (रूट, 46.4), 4-359 (मोर्गन, 46.6), 5-362 (बटलर, 47.4), 6-378 (स्टोक्स, 49.1)

गेंदबाजी :
मुजीब उर रहमान 10-0-44-0
दौलत जादरान 10-0-85-3
मुहम्मद नबी 9-0-70-0
गुलबदीन नायब 10-0-68-3
रहमत शाह 2-0-19-0
राशिद खान 9-0-110-0

वनडे में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी	देश	छक्के	बनाम	जगह	वर्ष
इयोन मोर्गन	इंग्लैंड	17	अफगानिस्तान	मैनचेस्टर	2019
रोहित शर्मा	भारत	16	ऑस्ट्रेलिया	बेंगलुरु	2013
एबी डिविलियर्स	द. अफ्रीका	16	वेस्टइंडीज	जोहानिसबर्ग	2015
क्रिस गेल	वेस्टइंडीज	16	जिंबाब्वे	कैनबरा	2015
शेन वॉटसन	ऑस्ट्रेलिया	15	बांग्लादेश	ढाका	2011

11 छक्के अफगानिस्तान के राशिद खान ने इंग्लैंड के खिलाफ खाए। यह वनडे में किसी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड है

वनडे में एक टीम द्वारा सर्वाधिक छक्के

छक्के	टीम	बनाम	जगह	वर्ष
25	इंग्लैंड	अफगानिस्तान	मैनचेस्टर	2019
24	इंग्लैंड	वेस्टइंडीज	सेंट जॉर्ज	2019
23	वेस्टइंडीज	इंग्लैंड	ब्रिजटाउन	2019
22	न्यूजीलैंड	वेस्टइंडीज	क्विंसटाउन	2014
22	वेस्टइंडीज	इंग्लैंड	सेंट जॉर्ज	2019

विश्व कप में सबसे तेज शतक

गेंद	बल्लेबाज	बनाम	वर्ष
50	केविन ओ ब्रायन	इंग्लैंड	2011
51	मैक्सवेल	श्रीलंका	2015
52	डिविलियर्स	वेस्टइंडीज	2015
57	मोर्गन	अफगानिस्तान	2019
66	मैथ्यू हेडन	द. अफ्रीका	2007

इंग्लैंड का विश्व कप में सर्वाधिक स्कोर

रन	बनाम	जगह	वर्ष
397/6	अफगानिस्तान	मैनचेस्टर	2019
386/6	बांग्लादेश	कार्डिफ	2019
338/8	भारत	बेंगलुरु	2011
334/4	भारत	लॉर्ड्स	1975
334/9	पाकिस्तान	नॉटिंघम	2019

राहुल के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती को तैयार रोहित

विशेष संवाददाता, साउथैंप्टन : रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी की सफलता का राज उनका आपसी तालमेल रहा है और भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित अब विश्व कप के बाकी मैचों में कुछ वैसा ही तालमेल केएल राहुल के साथ बिठाना चाहते हैं।

धवन की चोट के कारण राहुल ने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित के साथ पारी का आगाज किया। रोहित ने राहुल को पहले स्ट्राइक लेने दी, जबकि धवन के होने पर वह खुद ऐसा करते हैं। रोहित ने कहा कि केएल को स्ट्राइक लेना पसंद है और मैंने उन्हें दी क्योंकि मैं चाहता था कि वह सहज होकर अपने हिसाब से खेलें। वह सलामी बल्लेबाज के रूप में यहां पहला मैच खेल रहे थे और मैं उन्हें पूरी तरह से सहज करना चाहता था। उधर, राहुल इसे एक बड़े मौके के तौर पर ले रहे हैं और जब तक धवन नहीं आते हैं तब तक वह उनकी कमी को पूरी करने के लिए तैयार हैं। राहुल ने कहा कि शिखर और रोहित पिछले तीन चार साल से शानदार शुरुआत दे रहे हैं। मुझे अपने समय का इंतजार करना पड़ा और मुझे खुशी है कि मैंने पारी का आगाज किया। हालांकि दोनों के बीच हुई 136 रन की साझेदारी के दौरान कुछेक ऐसे मौके आए जब तालमेल की कमी की वजह से रोहित रन आउट होते-होते बचे। रोहित ने कहा कि यह एक नई तरह की चुनौती है लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर दिन एक नई चुनौती सामने होती है। वह दो रन लेना चाहते थे और मैं एक। यह छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन हम दोनों ही रन आउट नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान काफी बातें कीं। अब मुझे पता है कि आगे कुछ मैचों में वही पारी का आगाज करेंगे तो यह तालमेल और बेहतर होगा। बातचीत बहुत जरूरी है क्योंकि इससे दोनों को मदद मिलेगी। राहुल के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुहम्मद आमिर का पहला स्पैल खेलना था। उन्होंने कहा कि नई गेंद फेंकने वाले किसी भी गेंदबाज को संभलकर भांपना होता है। हमने पहले स्पैल में वही किया।

साझेदारी
- केएल ने किया था पाक के खिलाफ पहली गेंद का सामना
- कुछ मौकों पर रन आउट होने से बचे थे रोहित

फुर्सत पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ घूमने निकले विराट, धौनी स्कॉटलैंड में, केदार जाधव लंदन में, रोहित-शिखर ने परिवार के साथ बिताया समय

पाकिस्तान में हाहाकार, मजे में टीम इंडिया के खिलाड़ी

अभिषेक त्रिपाठी ● साउथैंप्टन

जहां भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम में हाहाकर मचा है तो वहीं विराट की टीम इंग्लैंड के मजे ले रही है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने दो दिन की छुट्टी मनाई। टीम ने सोमवार और मंगलवार को कोई अभ्यास नहीं किया। टीम के सभी सदस्यों ने मंगलवार की रात को प्रबंधन को रिपोर्ट किया और अब बुधवार की सुबह टीम अभ्यास करेगी।

भारतीय टीम को अगला मैच शनिवार को साउथैंप्टन में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। रविवार को मैनचेस्टर में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली सोमवार की सुबह ही पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए लंदन निकल गए। अनुष्का पहले से ही लंदन में थीं। सूत्रों के अनुसार इसके बाद दोनों स्कॉटलैंड गए। हालांकि टीम प्रबंधन ने इसकी पुष्टि नहीं की। महेंद्र सिंह धौनी और अन्य खिलाड़ी भी स्कॉटलैंड गए। वहीं मध्यक्रम के बल्लेबाज केदार जाधव दो दिन लंदन में रहे। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की दो दिन छुट्टी थी। इस समय वे क्या करते हैं, कहां जाते हैं उससे हमें कोई लेना-देना नहीं। भारतीय टीम के एक सूत्र ने बताया कि मैनचेस्टर में पाकिस्तान को हराने के बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन अपने परिवार के साथ ट्रेन के जरिये सोमवार को साउथैंप्टन पहुंचे। मुहम्मद शमी भी ट्रेन से ही यहां आए, जबकि रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, विजय शंकर, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह सहित अन्य खिलाड़ी टीम बस से साउथैंप्टन पहुंचे।

हम साथ-साथ हैं : भारतीय टीम इन 'बांडिंग' सत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही है। इसमें कोई मजेदार खेल या साथ में भोजन करना शामिल है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम ने पेंटबॉल खेला था और बुधवार से शुक्रवार तक टीम के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित होंगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय टीम में पिछले कुछ साल से इस तरह के सत्र हो रहे हैं। इसमें रोचक खेल और कुछ गतिविधि शामिल हैं। खिलाड़ी मंगलवार तक ब्रेक पर थे। इसके बाद यह गतिविधियां शुरू होंगी। इसमें लीडरशिप ग्रुप में कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धौनी हैं। 15 में से 12 खिलाड़ियों को ग्रुप में बांट दिया जाता है और तीनों सीनियर खिलाड़ी एक-एक ग्रुप में होते हैं। इस पर जोर दिया जाता है कि अलग-अलग क्षेत्रों के खिलाड़ी साथ में घूमे और खाना खाएं। मसलन विजय शंकर टीम के सबसे नए सदस्य हैं और तमिलनाडु का होने के कारण वह दिनेश कार्तिक के साथ सहज महसूस करेंगे, लेकिन कई बार कार्तिक को किसी दूसरे जूनियर खिलाड़ी के साथ भी खाना पड़ सकता है।

यह जबरिया नहीं है, लेकिन सहज होना चाहिये। पिछली सदी के आठवें दशक में इंग्लिश काउंटी में भी ऐसा होता था जिसमें काउंटी टीम के खिलाड़ी खास परिधान पहनकर खास सीन की नकल किया करते थे।

> पिछले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान की टीम में बड़ा अंतर आया है और रविवार को यह एक बार फिर ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर दिखा। पाकिस्तान की टीम अब भी सिर्फ प्रतिभा पर भरोसा कर रही है, जबकि भारत के खेल में टीम वर्क दिखता है। पिछली सदी के आखिरी दशक में हमारी टीम मजबूत होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान भारत से खौफ खाता है। पाकिस्तान की टीम जब भी ऐसे मैचों में जाती है तब वह दबाव में रहती है और ऐसा लगता है कि वह एक कमजोर टीम है।
> **वकार यूनुस**, पूर्व पाक तेज गेंदबाज

विश्व कप के दौरान मस्ती के मूड में कप्तान कोहली सहित भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी ● ट्विटर

> कृपया खिलाड़ियों के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करें। इंशाअल्लाह हम वापसी करेंगे और इसके लिए आपका साथ चाहिए।
> **मुहम्मद आमिर**, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज

> सभी खिलाड़ियों की ओर से मैं मीडिया और लोगों से हमारे परिवार के लिए सम्मान बरकरार रखने की अपील करता हूं। उन्हें बिना वजह इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है।
> **शोएब मलिक**, पाक ऑलराउंडर

पाक कप्तान सरफराज ने साथी खिलाड़ियों को चेताया

साउथैंप्टन : विश्व कप में भारत से 89 रनों से हारने के बाद आलोचना झेल रहे पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने साथी खिलाड़ियों को चेताया है कि अगर बाकी मैचों में वे अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं लाते हैं तो देश में और जलालत झेलने को तैयार रहें। सरफराज ने कहा कि अगर टीम का यही प्रदर्शन जारी रहा तो पाकिस्तान में उन्हें और अपमान झेलना होगा। उन्होंने कहा, 'यदि कोई सोचता है कि मैं घर लौट जाऊंगा तो वह मूर्ख है। खुदा ना करे, अगर कुछ हो गया तो सिर्फ मैं अकेला ही घर नहीं जाऊंगा। खराब प्रदर्शन को भुलाकर बाकी चार मैचों में अच्छा खेलना होगा।' भारत से हार के बाद पाकिस्तानी टीम की जमकर आलोचना हो रही है। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो कप्तान को बददिमाग तक करार दिया है। कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने पूरी टीम को अनफिट करार दिया है। भारत के खिलाफ पहली गेंद पर आउट होने वाले शोएब मलिक को टीम से बाहर करने की मांग की जा रही है। उनका उनकी पत्नी भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के साथ रात में बाहर घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है।

हमारी टीम के अहम स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू को इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड से अलग हो जाना चाहिए।
– रोबर्टो मार्टिनेज, फुटबॉल कोच, बेल्जियम

शाकिब अल हसन ने कहा, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई

टांटन, प्रेट्र : दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने कहा है कि वह पिछले कुछ महीनों से मेहनत कर रहे थे और वो रंग लाई। शाकिब ने सोमवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 124 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। शाकिब ने कहा कि यह बेहतरीन अहसास है। आखिरी तक विकेट पर टिके रहना सबसे संतोषजनक अहसास है। अब खुश हूं कि यह मेहनत रंग लाई।

फुटबॉल ▸ कोपा अमेरिका में जापान को 4-0 से दी शिकस्त, इडूवेर्डो वर्गास ने दागे दो गोल

गत चैंपियन चिली ने जापान को हराया

साओ पाउलो, एएफपी : गत चैंपियन चिली ने कोपा अमेरिका में जापान को 4-0 से हराकर अपने खिताबी रक्षा अभियान की जोरदार शुरुआत की, जहां उसके लिए इडूवेर्डो वर्गास ने दो गोल दागे।

वर्गास (54वें और 83वें मिनट) ने दूसरे हाफ में अपने दोनों गोल दागे जिसकी बदौलत 2015 और 2016 की चैंपियन चिली ने जापान को आसानी से शिकस्त दी। जापान इस टूर्नामेंट में दो आमंत्रित एशियन टीमों में से एक है। पहले हाफ में एरिक पुल्गार (41वें मिनट) ने गोल करके चिली को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि दूसरे हाफ में वर्गास के दो गोल करने के अलावा मैनचेस्टर युनाइटेड के लिए खेलने वाले एलेक्सी सांचेज (82वें मिनट) ने भी स्कोर किया। इसके साथ ही सांचेज ने चिली के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 42 पहुंचा दी। हाल के समय में सांचेज का करियर बेहद खराब दौर से गुजरा है। उन्होंने कहा कि पिछले छह सप्ताह मेरे करियर के सबसे खराब समय रहे हैं। मैंने पहले हाफ में थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन दूसरे हाफ में मैं ज्यादा आजादी और उत्साह के साथ खेला। इस जीत के साथ चिली की टीम ग्रुप-सी में उरुग्वे के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई। दोनों टीमों के एक-एक मुकाबलों के बाद अंक (03) और गोल अंतर (+04) एक समान हैं। इस मुकाबले में जापान की टीम ने भी हार के बावजूद गोल करने के कुछ अच्छे मौके तैयार किए, लेकिन वह स्कोर करने के मामले में थोड़ी दुर्भाग्यशाली रही।

वेसिनो कोपा अमेरिका से बाहर

वेलो होरिजोंते (ब्राजील), एएफपी : उरुग्वे के मिडफील्डर माटियास वेसिनो चोट की वजह से कोपा अमेरिका के बाकी मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। वेसिनो को ग्रुप-सी में रविवार को इक्वाडोर के खिलाफ मुकाबले में चोट लगी थी, जहां उनकी टीम 4-0 से जीतने में सफल रही। 27 वर्षीय वेसिनो का सोमवार को मेडिकल टेस्ट हुआ, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में भाग लिया।

साओ पाउलो में जापान की टीम को शिकस्त देने के बाद जश्न मनाते चिली के खिलाड़ी। एएफपी

यूएफा के अध्यक्ष रहे मिशेल प्लाटिनी हुए गिरफ्तार

पेरिस, एएफपी : यूरोपियन फुटबॉल की शीर्ष संस्था यूएफा के पूर्व प्रमुख मिशेल प्लाटिनी को 2022 विश्व कप की मेजबानी कतर को सौंपने की जांच के संदर्भ में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर रहे प्लाटिनी को 2007 में यूरोपीय फुटबॉल की संचालन संस्था का प्रमुख चुना गया था। कतर को 2022 विश्व कप की मेजबानी सौंपने के मामले की जांच कर रही फ्रांस की भ्रष्टाचार रोधी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। कतर को विश्व कप की मेजबानी सौंपने के फैसले से विवाद हो गया था क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए गए थे। प्लाटिनी नैतिक आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में चार साल के लिए फुटबॉल से प्रतिबंधित किए जाने से पहले 2015 तक यूएफा के प्रमुख रहे। उन पर फीफा के पूर्व दागी प्रमुख सैप ब्लाटर से 20 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) लेने का आरोप भी था। कतर पर विश्व कप की मेजबानी हासिल करने के लिए वोट खरीदने का आरोप लगा था और इसके बाद अमेरिका के स्वतंत्र जांचकर्ता माइकल गार्सिया की रिपोर्ट में कई संदिग्ध वित्तीय लेने-देन के खुलासे हुए। इनमें से कई सेंड्रो रोसेल से जुड़े थे जो स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के पूर्व अध्यक्ष थे।

दक्षिण अफ्रीका की टीम को सिर्फ जीतना होगा

जैक कैलिस
ऑलराउंडर

दक्षिण अफ्रीका के बड़े खिलाड़ियों के पास यह अपने आप को साबित करने का मौका है। मैंने पांच विश्व कप खेले हैं, इसलिए मैंने जूनियर खिलाड़ी से लेकर सीनियर खिलाड़ी तक की जिम्मेदारी उठाई है और मैं जानता हूं कि यह कप्तान और उनके ज्यादा अनुभवी खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे आगे आकर अगुआई करें। दक्षिण अफ्रीकी टीम को न्यूजीलैंड को हराने की जरूरत है और उसके बाद अपने अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने से पहले उसे पाकिस्तान व श्रीलंका को हराना होगा। उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने का अपना मौका बनाने के लिए सिर्फ जीतना होगा और उसके बाद नेट रन रेट निर्भर करेगा।

कम से कम वे जानते हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है और अभी भी उन्हें विश्वास करना होगा कि उनकी किस्मत उनके हाथों में है। यह वह स्थिति है जहां फाफ डुप्लेसिस, क्विंटन डिकॉक, हाशिम अमला, कैगिसो रबादा और इमरान ताहिर को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। यह सामान्य से ज्यादा कोशिश करने या फोकस करने का सवाल नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ करना होता है। इन सभी खिलाड़ियों ने पहले भी ऐसा किया है और मैं उन्हें फिर से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं।

हाशिम के लिए हाल में मैदान में और मैदान के बाहर मुश्किल समय रहा है। हालांकि, वह अब अपने करियर के अंत की ओर हैं, लेकिन उनका दृढ़संकल्प अभी भी उज्ज्वल है। पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने आखिरकार क्रीज पर कुछ अच्छा समय बिताया।

दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने पिछले दो विश्व कप में क्वार्टर फाइनल (2011) और सेमीफाइनल (2016) में बाहर किया था। वे हमेशा से काफी मजबूत टीम रही है और बड़े मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने में माहिर हैं। कीवी खिलाड़ी जानते हैं कि उनके पास दोहरा मौका है, मैच जीतना और वे अंतिम चार में अपना स्थान सुनिश्चित करने से एक जीत दूर हैं, लेकिन उनके पास दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नॉकआउट हैट्रिक करने का मौका है।

THE ULTIMATE INVERTER BATTERY
EXIDE INVATUBULAR

अमला को संघर्ष करते देखना काफी दुखद

सुनील गावस्कर
कलम से

न्यूजीलैंड की टीम पराजित सी दिख रही दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ मैदान में उतरने को बेताब होगी। हालांकि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, खासतौर से सीमित ओवरों के क्रिकेट में। दक्षिण अफ्रीका भी पिछले विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार का बदला चुकाना चाहेगा।

दक्षिण अफ्रीका का अभियान ना सिर्फ शुरुआती हार से बल्कि, डिविलियर्स के विश्व कप में खेलने की इच्छा जताने पर उठे विवाद से भी प्रभावित हुआ है। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत ने डिविलियर्स के प्रस्ताव को खबरों की सुर्खियां बना दिया। इससे टीम का अभियान और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। उनकी बल्लेबाजी बिलकुल भी नहीं चली है और इंग्लिश परिस्थितियों व पिच से मदद नहीं मिलने पर गेंदबाज भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद हाशिम अमला के हेलमेट से टकराई थी और अब लगता है कि वह अब भी उस झटके से उबरे नहीं हैं। अमला जैसे शीर्ष बल्लेबाज को इस तरह से संघर्ष करते देखना सच में काफी दुखद है। बाउंसर की वापसी से बहुत सारे फ्रंट फुट बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बढ़ी है। कुछ अंपायरों ने भी बाउंसर पर नियमों में थोड़ी ढील ही बरती है और इसलिए तेज गेंदबाज एक ओवर में तीन या चार बाउंसर तक फेंक रहे हैं। न्यूजीलैंड ने अभी तक बाउंसर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं किया है। बोल्ट और हेनरी अच्छी गति के साथ गेंद को स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। खासतौर से बोल्ट दायें हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद को अंदर ला सकते हैं, जो शुरुआती ओवरों में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जिमी निशाम के रूप में न्यूजीलैंड के पास ऐसा ऑलराउंडर है, जो कुछ अच्छे ओवर फेंकने के साथ बड़े शॉट भी लगा सकता है। कप्तान विलियमसन और रॉस टेलर की मौजूदगी से उनकी बल्लेबाजी काफी मजबूत है।

महिला वनडे विश्व कप 30 जनवरी से न्यूजीलैंड में

क्राइस्टचर्च, प्रेट्र : आइसीसी ने अगले साल होने वाले महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप की तारीखों की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत न्यूजीलैंड में 30 जनवरी से होगी और इसमें कुल 31 मैच खेले जाएंगे। दो पुरुष विश्व कप (1992 व 2015) और एक महिला विश्व कप (2000) की मेजबानी कर चुका न्यूजीलैंड चौथी बार विश्व कप की संयुक्त या अकेले दम पर मेजबानी कर रहा है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के अनुसार, 50 ओवर का यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 20 फरवरी तक चलेगा। यह आइसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण होगा और न्यूजीलैंड ने मेजबान होने के कारण टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है। आइसीसी महिला चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष चार में शामिल टीमों को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश मिलेगा।

'हैड्स मैंने जीता और टेल्स तुम हारे'

विश्व कप डायरी

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप के मैच में हसन अली की एक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर छक्का मारा था। लोगों ने इस शॉट की तुलना 2003 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ ही सचिन तेंदुलकर द्वारा शोएब अख्तर की ऑफ स्टंप के बाहर मारे गए छक्के से की। इस पर आइसीसी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'सचिन 2003 में और रोहित 2009 में, किसने बेहतर शॉट खेला।' इस पर सचिन ने अपना जबाव दिया और लिखा, 'हम दोनों भारत से हैं और एक ही शहर आमची मुंबई से हैं। इसलिए हैड्स मैं जीता और टेल्स तुम हारे।'

रणवीर बोले, विराट ने भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी : बॉलीवुड स्टार अभिनेता रणवीर सिंह ने यह कहते हुए कप्तान विराट कोहली की तारीफ की है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तस्वीर बदल दी है। रणवीर ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पाकिस्तान के साथ हुए मैच के दौरान कमेंट्री में पदार्पण किया था। उनके साथ सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग कमेंट्री बॉक्स में थे। भारत ने पाकिस्तान को उस मैच में 89 रनों से हराया था। रणवीर ने मैच का लुत्फ भी लिया था और बीच-बीच में खिलाड़ियों से भी मिले थे। रणवीर ने इंस्टाग्राम पर कपिल देव के साथ फोटो साझा की और विराट की कप्तानी की तारीफ की। रणबीर ने लिखा, 'विराट असली अल्फा वॉरियर की तरह हमारे देश की टीम की कमान संभाल रहे हैं।' रणवीर इन दिनों फिल्म '83' में काम कर रहे हैं, जो 1983 विश्व कप पर आधारित है।

होप ने कहा, लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की रणनीति थी : बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मैच में वेस्टइंडीज की धीमी गति से रन बनाने के लिए आलोचना हो रही हो, लेकिन 121 गेंद में 96 रन बनाने वाले शाई होप ने कहा कि बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरते देख उनका लक्ष्य एक छोर संभाले रखना था। होप ने कहा, 'मैं जब भी क्रीज पर आता हूं तो लंबे समय बल्लेबाजी के लिए उतरता हूं। मैं आखिरी ओवरों के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता। जिम्मेदारी लेना जरूरी है।' उन्होंने कहा, 'मैं स्ट्राइक रेट बेहतर करूंगा जो भी जरूरत होगी, वह करूंगा। दूसरे छोर से विकेट गिरते जा रहे थे जिससे निचला क्रम दबाव में आ रहा था, इसके लिए मेरा टिककर खेलना जरूरी था। वहीं, कप्तान जेसन होल्डर ने कहा कि टीम की आगे की राह अब मुश्किल हो गई है।

विविध

झारखंड के नक्सल प्रभावित गांवों की आवाज बन रहीं खबरनवीस दीदियां

उत्कर्ष पांडेय, लातेहार

झारखंड के लातेहार जैसे जिले कुछ साल पहले तक नक्सली गतिविधियों के चलते ज्यादा चर्चा में रहते थे। आज यहां महिलाएं जागरूकता की अलख जगाकर विकास की नई इबारत लिख रही हैं। डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम ने आधी आबादी को न सिर्फ जागरूक किया है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया। एक तरफ महिलाएं मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपनी आजीविका का जरिया बना रही हैं, साथ ही इन्हीं के जरिए वे अपने समूह और गांव की सफलता की कहानियां भी दूसरों तक पहुंचा रही हैं। इस बदलाव का वाहक कुछ पत्रकार दीदियां बनी हैं। उन्होंने कंप्यूटर, मोबाइल और टेबलेट को अपना हथियार बना लिया। यही वजह है कि इस नक्सल प्रभावित जिले के ग्रामीण इलाकों के लोग इन दिनों अखबार, मैगजीन से लेकर मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट तक पर देश-दुनिया की खबरें देख और पढ़ रहे हैं। इन खबरों में खेत-खलिहान से लेकर उनके लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं से लेकर अंतरिक्ष तक की गतिविधियां शामिल हैं। इनमें रूढ़िवादी मान्यताओं और सामाजिक विसंगतियों से बाहर निकलने के लिए जागरूक और प्रेरित करने वाली खबरें भी हैं।

नारी सशक्तीकरण

झारखंड के गांव में समाचार संकलन के दौरान वीडियो बनातीं पत्रकार दीदी। जागरण

ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के अलावा पत्रकार दीदियों के रूप में किया जा रहा अनोखा प्रयास सराहनीय है।
– राजीव कुमार, उपायुक्त, लातेहार

लोगों तक पहुंच रहीं सफलता की कहानियां : सखी मंडल से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं कम्युनिटी जर्नलिस्ट यानी सामुदायिक पत्रकार बनकर अपने गांव की आवाज बन गई हैं। ये अपने समूह और गांव की वह कहानियां लोगों तक पहुंचाती हैं जो अब तक सुर्खियां नहीं बनी थीं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (जेएसएलपीएस) की ओर से दिए गए प्रशिक्षण और आर्थिक मदद का लाभ उठा कर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं नित नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं।

कंप्यूटर की-बोर्ड पर जिंदगी का ताना-बाना : डिजिटलीकरण ने जिले की ग्रामीण आबादी के पैरों की बेड़ियां तोड़ इनके हाथों को ताकत दी है। अब इनकी उंगलियां कंप्यूटर के की-बोर्ड पर जिंदगी का ताना-बाना बुनती हैं। इनकी कौतूहल भरी हंसी मोबाइल में कैद होती है। इनकी चमकती आंखें सपने देखती हैं, तकनीक अब इनकी हमसफर जो बन गई हैं।

ले चुकी हैं पत्रकारिता का प्रशिक्षण : जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर गारू प्रखंड में रहने वाली सविता देवी जेएसएलपीएस की मदद से सामुदायिक पत्रकारिता का प्रशिक्षण ले चुकी हैं। वह बताती हैं, हम अपने गांव और समूह की कई खबरें लिख चुके हैं।

महिलाओं ने बदली किस्मत

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं को एक समय घर से बाहर कदम निकालने से पहले कई बार सोचना पड़ता था, लेकिन सखी मंडल से जुड़ने के बाद इन महिलाओं में न केवल निर्भीकता आई है, बल्कि समूह को ये अपनी ताकत भी समझती हैं। जंगलों से अपनी जीविका को चलाने वाली ये महिलाएं अब अलग-अलग तरह के काम कर रही हैं। अब ये बैंक जाती हैं, समूह के साथ-साथ प्रखंड कार्यालय की बैठक में हिस्सा लेती हैं। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान का संचालन करती हैं। कभी महिलाएं सरकारी योजनाओं से कोसों दूर रहती थीं, लेकिन आज ये सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर सशक्त हो रही हैं।

सोशल नेटवर्किंग साइट से जरिए बता रहीं संघर्ष गाथा : सविता देवी की तरह जिले में आठ से ज्यादा महिलाएं अब गांव की पगडंडियों से निकलकर वेबसाइट और यू-ट्यूब जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों को महिलाओं के संघर्ष की गाथा सुनाती हैं। महिलाएं अपने आसपास के वह मुद्दे और समस्याएं उठाती हैं, जहां आमतौर पर पत्रकार नहीं पहुंच पाते।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

पति ने जेल में झेली यातनाएं, पत्नी ने सब्जी बेचकर बच्चों को किया बड़ा

शुजाउद्दीन, नई दिल्ली

आपातकाल का नाम आते ही 25 जून 1975 की रात का काला मंजर लोगों की आंखों के सामने आ जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत करने वालों को जेल की कोठरियों में बंद कर दिया गया था। शारीरिक और मानसिक यातनाएं इस तरह दी गई कि उसे याद कर लोग आज भी सिहर जाते हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा में रहने वाले लाल बिहारी तिवारी (78) को पुलिस ने रातों रात घर से उठाकर जेल में बंद कर दिया। इस बीच घर की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गई कि उनकी पत्नी को परिवार चलाने के लिए सब्जियां तक बेचनी पड़ी।

आपातकाल के बाद तिवारी आगे चलकर विधायक और सांसद भी बने। उन्होंने बताया कि वह जनसंघ के कार्यकर्ता थे। जून 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जय प्रकाश नारायण की एक सभा हुई। इसमें जनसंघ, ओल्ड कांग्रेस सहित विभिन्न दल शामिल हुए। सभी ने एक आवाज में इंदिरा गांधी को कुर्सी से हटाने का आह्वान किया। अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। 25 जून की रात 12 बजे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। जनसंघ समेत अन्य गैर कांग्रेसी पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं को घर, ऑफिस समेत अन्य जगहों से पुलिस गिरफ्तार कर जेल में बंद करने लगी। चूंकि तिवारी खुद जनसंघ के कार्यकर्ता थे, ऐसे में आपातकाल लगते ही वह अलग-अलग इलाकों में रहकर इंदिरा के खिलाफ अभियान चलाते रहे। जुलाई 1975 में उन्हें किसी ने सूचना दी कि उनके बेटे रवि तिवारी की तबीयत बहुत खराब है। वह रात के समय छिपते हुए घर पर बेटे को देखने पहुंचे। उसी दिन पुलिस ने छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी कमाई से घर खर्च चलता था। उनके परिवार में पत्नी विंदेश्वरी देवी के अलावा छह बच्चे थे। परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। तब उनकी पत्नी ने सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा में रहने वाले लाल बिहारी तिवारी। जागरण

दोस्त और रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था साथ : लाल बिहारी तिवारी ने बताया कि पुलिस उन्हें डीआइआर के तहत गिरफ्तार कर शाहदरा थाने लेकर गई। यहां दो दिनों तक उन्हें लॉकअप में रखकर बहुत मारा गया। पुलिस जनसंघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं के बारे में पूछती थी, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। वह जेल में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह समेत बड़े नेताओं के साथ भी रहे। जेल में बहुत यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने इंदिरा का विरोध करना नहीं छोड़ा। 19 महीने में जेल से रिहा हुए। वह जब जेल गए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने परिवार का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया।

आपातकाल के बाद चमका किस्मत का सितारा : आपातकाल के बाद तिवारी की किस्मत खूब चमकी। पहली बार वह जून 1993 में घोंडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से विधायक का चुनाव लड़े और जीत गए। कुछ ही महीनों के बाद उन्हें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। वह तीन बार सांसद भी रहे। उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ ही एचकेएल भगत को हराया। मौजूदा समय में वह दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

जेल जाते ही चली गई थी नौकरी : तिवारी ने बताया कि वह दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार में लीगल मैनेजर थे। जैसे ही विभाग को उनकी गिरफ्तारी की खबर लगी उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। जेल में कोई काम नहीं कराया जाता था। आपातकाल खत्म होने के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। नई सरकार के आने के बाद वह फिर से बहाल हो गए। तिवारी ने बताया कि तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 13 में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवी बंद किए गए थे। कई सप्ताह तक पुलिस ने तरह-तरह की यातनाएं दीं, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटा। करीब तीन महीने के बाद उन्होंने इसी वार्ड में संघ की शाखा लगानी शुरू कर दी।

थानागुड़ी : सुशासन की नायाब व्यवस्था, जिसे फिर बहाल करने की फरियाद

हेमंत कश्यप, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सदियों से चली आ रही थानागुड़ी की परंपरा धीरे-धीरे खत्म हो गई है। पहुंच मार्ग के अभाव में लंबी पदयात्रा कर गांव पहुंचने वाले राजस्व और पुलिस महकमे के अधिकारी यहां ठहर कर गांव वालों की समस्या दूर किया करते थे, लेकिन नौवें दशक के बाद यह व्यवस्था बंद हो गई है। इसलिए अब गांव वालों को अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए लंबी यात्रा कर जिला मुख्यालय आना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि थानागुड़ी की व्यवस्था फिर से प्रारंभ की जानी चाहिए ताकि अधिकारी गांव में आएं और उनकी समस्याओं का निराकरण करें।

बस्तर के गांव में जब सरकारी आवासीय व्यवस्था नहीं थी, तब गांव वाले अधिकारियों के लिए बस्ती में एक आवास का निर्माण करते थे, जिसके सामने एक बरामदा होता था। इसे थानागुड़ी कहा जाता था। लंबी पदयात्रा कर गांव पहुंचे अधिकारी यहां रहते थे। इनके लिए ग्रामीणों द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति मुस्तैद रहता था। वह पानी भरने से लेकर भोजन पकाने तक की व्यवस्था करता था। इसे अठपहरिया कहते थे। ग्रामीण आगंतुक अधिकारी के लिए तीन दिनों का राशन दिया करते थे, जिसे भाता कहा जाता था। गुड़ी में पटवारी से लेकर बड़े अधिकारी तक ठहरा करते थे। थानागुड़ी में अधिकारियों की सेवा करने वाले अठपहरिया को ग्रामीण साल में एक बार पारिश्रमिक के रूप में धान दिया करते थे।

▸ गांव की समस्याएं गांव में ही हल कर देते थे राजस्व व पुलिस के अधिकारी

अधिकारी निपटाते थे समस्याएं : बस्तर में यातायात के साधनों और पहुंचमार्ग का अभाव था, इसलिए अधिकारी लंबी दूरी तय कर दूरस्थ गांव पहुंचते थे और थानागुड़ी में दो-तीन दिन ठहरकर समस्याएं निपटाने के अलावा विभिन्न शासकीय योजनाओं का सर्वे किया करते थे। आजादी के पहले से चली आ रही यह व्यवस्था वर्ष 1980 के आसपास बस्तर के गांवों में रही। ग्रामीणों ने बताया कि मनमानी करने वाले कुछ अधिकारियों के कारण ही यह व्यवस्था खत्म हो गई। बताया गया कि थानागुड़ी में ठहरे कुछ अधिकारी ग्रामीणों से मांस-मदिरा के अलावा अय्याशी के लिए दीगर वस्तुओं की मांग करने लगे थे। कभी कभी इन्हें खाट में बैठाकर दूसरे गांव पहुंचाना पड़ता था, जिसके चलते ग्रामीणों को कई परेशानी उठानी पड़ती थी, इसलिए ग्रामीणों ने ही यह व्यवस्था खत्म कर दी। अब भी कुछ गांवों में थानागुड़ी बचे हैं।

अब शहर आ रहे ग्रामीण : संभागीय मुख्यालय से करीब 125 किमी दूर हर्राकोडेर के आयतू, तिरथा और मांगीराम बताते हैं कि जब गांव में थानागुड़ी थी, तब जगदलपुर से बारसूर होकर या बिंता घाटी उतरकर राजस्व और पुलिस अधिकारी लंबी यात्रा कर उनके गांव पहुंचा करते थे। थानागुड़ी में ठहर उनकी समस्याओं का निराकरण किया करते थे। लेकिन, जब से व्यवस्था बंद हुई है, प्रकरणों को निपटाने के लिए लंबी दूरी तय कर तहसील या जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। उधर, राजस्व और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले बस्तर में पहुंच मार्गों और आवागमन के साधनों का अभाव था, इसलिए पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर से लेकर थानेदार और पुलिस कप्तान को लंबी पदयात्रा कर दूरस्थ गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करना पड़ता था।

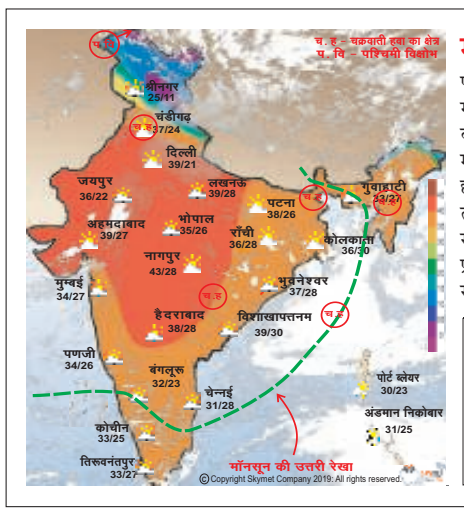

मौसम विशेष

पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर गरज व तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होगी। पश्चिमी राजस्थान में मौसम गर्म रहेगा। दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में मौसम में सुधार होगा। तापमान में वृद्धि के साथ मौसम गर्म रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/26/व	अहमदाबाद	40/28/व
कोलकाता	35/28/व	बड़ौदा	39/27/आंबा
चेन्नई	37/27/आंबा	नागपुर	41/30/व
हैदराबाद	36/26/व	इन्दौर	39/27/व
बंगलूरू	31/22/व	रांची	38/28/व
त्रिवेन्द्रम	34/27/व	पटना	41/31/व
गुवाहाटी	32/28/व	जमशेदपुर	38/28/आंबा
गंगटोक	18/10/व	पुणे	25/23/व

भारत का पहला भू-स्थिर उपग्रह एप्पल भेजा गया

1981 में आज ही प्रयोगात्मक संचार उपग्रह एप्पल लांच हुआ। इसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रॉकेट पर फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसका इस्तेमाल टेलीविजन और रेडियो प्रसारण में किया गया। 19 सितंबर, 1983 को इस कार्यक्रम को निष्क्रिय कर दिया गया।

गारफील्ड कॉमिक्स की हुई शुरुआत

दुनिया की सर्वाधिक प्रकाशित कॉमिक स्ट्रिप के लिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाली गारफील्ड कॉमिक्स की शुरुआत 1978 में आज ही हुई थी। गारफील्ड नामक बिल्ले पर आधारित इस कॉमिक को जिम डेविस ने बनाया है। इसे दुनिया भर में रोजाना 26 करोड़ लोग पढ़ते हैं।

हिंदी के प्रथम कहानीकार रहे हैं पंडित माधवराव सप्रे

सुप्रसिद्ध अनुवादक और आरंभिक संपादकों में प्रमुख स्थान रखने वाले पंडित माधव राव सप्रे का जन्म 1871 में आज ही मध्य प्रदेश के पथरिया में हुआ। वह हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी 'एक टोकरी भर मिट्टी' को हिंदी भाषा की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। मराठी भाषी होने के बावजूद उन्होंने हिंदी के विकास के लिए सतत कार्य किया। मौलिक रचनाएं करने के साथ उन्होंने संत समर्थ रामदास और लोकमान्य तिलक जैसे विद्वानों की रचनाओं का अनुवाद भी किया। कई पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। 23 अप्रैल, 1926 को रायपुर में उनका देहांत हो गया।

इधर-उधर की

केले की बंदूक बनाकर लूट लिया बैंक

लंदन, एजेंसी: तमाम तरीके के हथियारों के बल पर बैंक लूटे जाने की घटनाएं तो आपने सुनी होगी, लेकिन केले से बैंक लूटने की कोशिश का यह विरला मामला है। ब्रिटेन के डोर्सेट में 50 वर्षीय लारेंस वॉनडेरेल ने कुछ ऐसा ही कारनामा करने की सोची। केले के ऊपर एक विशेष चीज लपेट कर उसे बंदूक का रूप-रंग देते हुए वे बार्कलेज बैंक पहुंचे। वहां मौजूद स्टाफ को धमकाया कि जितना कैश है मेरे हवाले कर दो, अन्यथा गोली मार दूंगा। डरकर स्टाफ ने नकदी उनके हवाले कर दिया। इसके बाद वॉनडेरेल पास के थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने केले के दम पर बैंक लूट लिया है। इस पर पुलिस भी चौंक गई। मौके पर पड़ताल के लिए पहुंची तो सारी बातें सच साबित हुई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले ही बैंक प्रबंधन उसे नौकरी से हटा दिया था। प्रबंधन को सबक सिखाने के लिए उसने यह कदम उठाया है। इस मामले में कोर्ट ने वॉनडेरेल को 14 माह की सुनाई।

टेक्नोलॉजी भी करती है इंसानों में भेदभाव

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- एआइ आधारित सिस्टम में सामने आए हैं भेदभाव के कई मामले
- सिस्टम डेवलप करने में विविधता की कमी बन रही प्रदर्शन में बाधा

वाशिंगटन : आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) यानी मशीनों को सोचने-समझने की ताकत देना। इन दिनों टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआइ सबसे ज्यादा चर्चा में है। एआइ की मदद से मशीनें आपकी आवाज सुनकर काम को अंजाम दे सकती हैं। बायोडाटा के सैंपल में से आपकी कंपनी के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुन सकती हैं। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाना भी एआइ आधारित सिस्टम से ही संभव है।

अगर आपसे कहा जाए कि ये मशीनें भी भेदभाव करती हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। हम में से कर किसी का यही तर्क होगा कि मशीनें किस आधार पर भेदभाव करेंगी। भेदभाव वाली सोच भला उनमें कैसे आ सकती है। लेकिन ऐसा हो रहा है। कोई एआइ सिस्टम किस आधार पर काम करेगा, इस पर उसे तैयार करने वालों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। वह किन परिस्थितियों और

हर काम संभव कर रही है एआइ। प्रतीकात्मक

कैसे लोगों के बीच तैयार हुआ, इससे यह तय होता है कि उसका झुकाव किस तरफ रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा आयोजित न्यू रूल्स समिट में विशेषज्ञों ने उदाहरण के साथ ऐसे कई मामले गिनवाए। विशेषज्ञों ने माना कि एआइ के परीक्षण के समय विविधता को ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। आंकड़ों और आसपास उपस्थित लोगों की एकरूपता नतीजों को प्रभावित कर सकती है।

मशीनें कर रहीं लैंगिक भेदभाव : एआइ सिस्टम पर काम करने वाले ज्यादातर पुरुष हैं। जहां इन्हें विकसित करने में महिलाओं की भूमिका है, वहां भी कार्यस्थल पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है। इसका सीधा असर एआइ सिस्टम की कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है। आवाज से काम करने वाले ज्यादातर एआइ सिस्टम का परीक्षण पुरुषों पर ही किया जाता है। इसका नतीजा यह है कि कुछ एआइ सिस्टम महिलाओं और बच्चों की आवाज पर उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।

रंगभेद भी हावी : एआइ का विकास अभी जिन देशों में हो रहा है, वहां टेक्नोलॉजी पर गोरे लोगों का वर्चस्व है। यह वर्चस्व भी मशीनों के काम पर असर डाल रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचान कर काम करने में सक्षम कुछ एआइ सिस्टम के मामले में देखा गया है कि ऐसे सिस्टम गोरे लोगों के मामले में जितना बेहतर नतीजा देते हैं, अपेक्षाकृत सांवले लोगों के मामले में उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहता।

नतीजा भी हो सकता है गलत : एआइ सिस्टम इस आधार पर काम करता है कि उसे सैंपल के रूप में कैसा डाटा दिया गया। इसकी खामी का बड़ा उदाहरण बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन में देखने को मिला था। कंपनी ने अपने यहां कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एआइ सिस्टम तैयार किया। इस दौरान एआइ सिस्टम को पिछले 10 साल में आए रिज्यूमे और चुने गए लोगों का डाटा मुहैया कराया गया था। उस दौर में ज्यादातर आवेदन पुरुषों का था, इसलिए नियुक्ति भी पुरुषों की हुई थी। इस सैंपल के आधार पर एआइ सिस्टम ने यह मान लिया कि पुरुष ज्यादा बेहतर काम करते हैं। उस सिस्टम ने ऐसे रिज्यूमे को दोयम माना, जिनमें महिला शब्द लिखा होता था। इसी तरह लोन के मामले में भरोसेमंद लोगों का पता लगाने के लिए तैयार एल्गोरिदम में भी यही हाल दिखा। लोन लेने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए डिफॉल्टरों में भी पुरुष ज्यादा थे।

आंखों के जरिये लोगों से संवाद कायम करते हैं कुत्ते

लंदन, प्रेट्र: कहते हैं कुत्ता सबसे वफादार और समझदार जानवरों में से एक है और ज्यादातर कुत्तों के चेहरे बड़े मासूम लगते हैं। मानव विकास प्रक्रिया के दौरान जब मनुष्य ने कुत्तों को पालना शुरू किया तो उस समय स्वाभाविक है कि कुत्ते अपेक्षाकृत खूंखार ही रहे होंगे। अब वैज्ञानिकों ने इनकी मासूमियत और मनुष्य से संवाद कायम करने के संबंध में अध्ययन कर दावा किया है कि कुत्तों ने हजारों वर्षों में अपने चेहरे और आंखों की मांसपेशियों को विकसित किया है जिससे वे प्यारे और मासूम लगते हैं। कुत्तों की यही मासूमियत उन्हें मनुष्यों के करीब लाती है और कुत्ते उनसे बेहतर संवाद कायम करने में सक्षम हो पाते हैं।

प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक यह अध्ययन कुत्तों और भेड़ियों के शरीर की संरचना और व्यवहार की तुलना करने वाला यह पहला विस्तृत विश्लेषण है।

कुत्ता वफादार जानवरों में से एक है। फाइल

ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के शोधकर्ताओं ने पाया कि शुरुआती दौर में दोनों प्रजातियों के चेहरे की मांसपेशियां आंखों के ऊपरी भाग के अलावा एक जैसी ही थी। कुत्तों में एक छोटी मांसपेशी होती है, जो उन्हें अपनी आंतरिक भौं (आइब्रो) को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन भेड़िये ऐसा नहीं कर पाते। शोधकर्ताओं का मानना है कि कुत्तों की भौं उठे होने से इनकी आंखें बड़ी और एक शिशु जैसी दिखाई देती हैं और दुखी होने पर कुछ समय के लिए ही सही पर लोगों में इन्हें देखकर खुशी का भाव आ जाता है।

टिक टॉक ने लॉच किया नया सुरक्षा फीचर

नई दिल्ली, आइएएनएस : शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म 'टिक टॉक एप' ने भारत में नया सुरक्षा फीचर 'डिवाइस मैनेजमेंट' लॉच किया है। इससे यूजर्स अपने अकाउंट पर पूरी तरह नियंत्रित रख पाएंगे। यूजर्स अपने खाते की सिक्योरिटी का भी बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के लिए टिक टॉक एप के सेशन को खत्म कर सकेंगे, साथ ही दूसरे डिवाइसों से भी अकाउंट को रिमूव कर पाएंगे। बता दें कि भारत में टिक टॉक के लगभग 20 करोड़ से अधिक यूजर हैं।

कंपनी के अनुसार, यह सुविधा यूजर्स के खातों को दुरुपयोग होने से बचाएगी। इसके जरिए यूजर्स को अपनी रचनात्मकता दिखाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। 'डिवाइस मैनेजमेंट' सर्विस टिकटॉक की मौजूदा 13 सुरक्षा सुविधाओं के अतिरिक्त इंस्टॉल की गई है। टिक टॉक ने दावा किया है कि एज गेट, रिस्ट्रिकटेड मोड, स्क्रीन-टाइम मैनेजमेंट, कॉमेंट फिल्टर और सेफ्टी सेंटर जैसी सुविधाएं यूजर्स को अपने वीडियो के माध्यम से अपनी रचनात्मकता दिखाने में मदद करेगी।

टिकटॉक के दुष्प्रभावों के सामने आने के बाद कंपनी ने यह नया फीचर लॉच किया है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु में दो बच्चों की मां ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके पति ने उसे टिकटॉक एप का इस्तेमाल करने से रोका था।

शोध अनुसंधान

मुंह की खराब सेहत से बढ़ता है लिवर कैंसर का खतरा

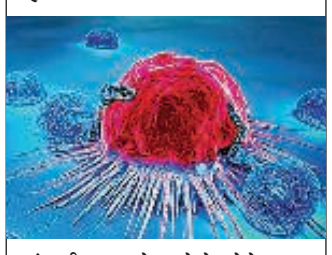

मुंह की खराब सेहत से हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा (एचसीसी) का खतरा 75 फीसद तक बढ़ जाता है। एचसीसी लिवर कैंसर का सबसे ज्यादा होने वाला प्रकार है। मुंह की सेहत और लिवर व आंतों के कैंसर के बीच संबंध जानने के लिए किए गए हालिया अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। मसूढ़ों में दर्द व खून आना, मुंह में अल्सर बनना और दांतों की कमजोरी को मुंह की खराब सेहत का लक्षण माना गया है। इसका संबंध हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी पाया जा चुका है। शोध के दौरान ब्रिटेन के 4,69,628 लोगों को शामिल किया गया था। मुंह की खराब सेहत वाले ज्यादातर प्रतिभागी युवा थे। ऐसे लोग अपने खानपान में फल-सब्जी का कम इस्तेमाल करते थे। वैज्ञानिक अभी यह नहीं जान पाए हैं कि मुंह की खराब सेहत से पेट और आंत के अन्य कैंसर की तुलना में लिवर के कैंसर का खतरा ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। -आइएएनएस

अल्जाइमर के इलाज में भी कारगर होगी बीपी की दवा

हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा को अल्जाइमर के इलाज में भी प्रयोग करने की उम्मीद जगी है। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, जिसमें मरीज की याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। नीदरलैंड्स की रेडबाउंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि हाई बीपी की दवा निल्वाडिपाइन अल्जाइमर के मरीजों में दिमाग के उस हिस्से तक खून का संचार बढ़ा देती है, जो याद रखने में भूमिका निभाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग के अन्य किसी हिस्से पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि अल्जाइमर के मरीजों में दिमाग के इस हिस्से में खून का संचार कम हो जाता है और बीपी की यह दवा इसे ठीक कर सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि खून का संचार बढ़ जाने से मरीज को किस हद तक फायदा हो सकता है। - प्रेट्र

नासा का दावा, चंद्रमा में छुपे हैं सूर्य के रहस्य

खुलेंगे राज ▶ जीवन के विकास को समझने में मिलेगी मदद

सूर्य की घूर्णन गति तेज होने के कारण ग्रहों पर हुए थे केमिकल रिएक्शन

वाशिंगटन, प्रेट्र : नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की सतह में सूर्य के प्राचीन रहस्यों का सुराग मिल सकता है जो जीवन के विकास को समझने में मददगार साबित हो सकता है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों की इस टीम में एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल हैं।

वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग चार अरब साल पहले सौरमंडल में कई ग्रहों में केमिकल रिएक्शन की वजह से विस्फोट हुआ था इसकी वजह से तीव्र विकिरण और अत्यधिक ऊर्जा के क्लाउड और पार्टिकल निकलकर पूरे सौर मंडल में फैल गए थे। अमेरिका में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के शोधकर्ताओं ने कहा कि इस घटना की वजह से पृथ्वी को गर्म और गीला दोनों तरह का वातावरण मिला और यहां पर जीवन संभव हो पाया, लेकिन यह रिएक्शन प्रत्येक ग्रह में जीवन नहीं लाया। कई ग्रहों के वातावरण को इसने तहस-नहस भी कर दिया। उन्होंने बताया कि सौर मंडल में यह केमिकल रिएक्शन इस पर निर्भर करता है कि सूर्य अपनी

नासा का मुख्यालय अमेरिका में है। फाइल

- अमेरिका में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन

धुरी में कितनी तेज घूम रहा था। वह जितनी तेज घूम रहा होगा उतनी तेज ही ग्रहों में रिएक्शन भी हुआ होगा। नासा के खगोल विज्ञानी प्रबल सक्सेना ने कहा कि इस घटना ने वैज्ञानिकों को बहुत परेशान किया है।

सूर्य का चंद्रमा से संबंध : खगोल विज्ञानी प्रबल सक्सेना ने बताया कि अपोलो मिशन द्वारा लाए गए चंद्रमा की सतह के नमूने और पृथ्वी पर चंद्रमा से आए उल्कापिंडों के अध्ययन के बाद से पता चलता है कि चंद्रमा की मिट्टी में पृथ्वी की तुलना से कम सोडियम और पोटेशियम कम है। यह बात चकित करती है, क्योंकि दोनों ग्रह एक जैसी ही सामग्री से ही बने हैं। कई वर्ष पूर्व यह सिद्धांत दिया गया था कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर किसी ग्रह के टकराने से ही टूटकर चंद्रमा बना है और नई खोज इस सिद्धांत को चुनौती देती है।

नासा के शोधकर्ताओं ने बताया कि शुरुआती समय में सूर्य के घूर्णन की गति धीमी थी। यह किसी नए तारे की तुलना में 50 गुना धीमे घूमता था और एक चक्कर में 9 से 10 दिन का समय लेता था। नासा के वैज्ञानिक सक्सेना और रोजमैरी किलेन ने सूर्य के घूर्णन की गति और उसकी केमिकल रिएक्शन के बीच में एक गणितीय संबंध स्थापित किया।

कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से बताया कि सूर्य के इस घूर्णन के कारण ही चंद्रमा में रिएक्शन हुआ और आवेशित आयनों में विस्फोट हो गया। जिसके बाद से चंद्रमा से सोडियम और पोटेशियम निकलकर अंतरिक्ष में फैल गए। इसके बाद यहां पर इन तत्वों की कमी हो गई।

हिंदी को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट के लिए नासा ने की फंडिंग

- भारत के प्राचीन स्थलों के निर्माण में प्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर तैयार किया गया वीडियो

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हिंदी को बढ़ावा देने वाले एक प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के बारे में वीडियो बनाए गए हैं। वीडियो को इन स्थलों के निर्माण में प्रयुक्त विज्ञान व प्रौद्योगिकी से जुड़े पहलुओं को समझाने और हिंदी सिखाने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

नासा ने हिंदी, अरबी, चीनी और अन्य भाषाओं की पढ़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकता में रखते हुए बढ़ावा देने के लिए स्टारटॉक कार्यक्रम चलाया है। इसी के तहत न्यूजर्सी में एजुकेटर्स सोसायटी फॉर हेरिटेज ऑफ इंडिया के निदेशक वेद चौधरी को 90,000 डॉलर (करीब 63 लाख रुपये) का अनुदान दिया गया है। चौधरी की अगुआई में भारत के ऐतिहासिक स्थलों के वैज्ञानिक पहलू पर वीडियो तैयार किए गए हैं। इनमें जयपुर स्थित आमेर का किला व हवा महल, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ व कुतुब मीनार और बांदीकुई स्थित चांद बावड़ी जैसे विभिन्न स्थलों के निर्माण में अपनाई गई वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में बताया गया है। इस प्रोजेक्ट से प्रमुख खोजकर्ता के रूप में जुड़े आलोक कुमार ने कहा, 'हर वीडियो को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मिडिल स्कूल से लेकर कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया है। इनकी मदद से छात्रों को उन्नत हिंदी सीखने का मौका भी मिलेगा।'

स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत आलोक कुमार ने हिंदू विज्ञान, गणित और औषधि विज्ञान पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का कहना है कि कुमार ने जिन स्थलों को चुना है, वहां विज्ञान के कई उच्च सिद्धांतों और तकनीकी जानकारियों का प्रयोग किया गया है।

सैंडसिटी की सैर

बेल्जियम के आस्टेंड में इन दिनों बालू की भव्य और जीवंत कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं। सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल 'ड्रीम्स' के तहत कलाकार आकृतियों को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं। इस फेस्टिवल की शुरुआत 22 जून से होगी जो आठ सितंबर तक चलेगी। इसमें दुनियाभर से 40 से अधिक सैंड आर्टिस्ट पहुंचे हैं और शानदार आकृतियां उकेर रहे हैं। इस आयोजन के लिए यहां लगभग 240 ट्रक विशेष बालू मंगाया गया है। लगभग 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में कुल 150 कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं। आयोजन के मद्देनजर आस्टेंड को सैंडसिटी नाम से भी पुकारा जाता है। रायटर

पेरिस एयर शो

फ्रांस में मंगलवार को 53वें पेरिस एयर शो में प्रदर्शित एक्सपेरिमेंटल फ्लाइंग टैक्सी। एयरबस की यह एयरटैक्सी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। सोमवार से शुरू यह एयर शो 23 जून तक चलेगा। इस शो में एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े करीब 2400 एक्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। एक्जिबिटर्स की संख्या और प्रदर्शनी के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसका पहला आयोजन 110 साल पहले 1909 में हुआ था। 1949 से हर दूसरे साल यह एयर शो आयोजित होता है। रायटर

स्क्रीन शॉट

निर्माता तुषार कपूर ने अपनाया 'एक चुप सौ सुख' का मंत्र

बहन एकता कपूर की राह पर चलते हुए तुषार कपूर ने फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' से निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। साउथ की हॉरर फिल्म 'मुनि 2 : कंचना' की इस हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में होंगे। पिछले दिनों यह फिल्म तब सुर्खियों में आ गई थी, जब फिल्म के निर्देशक राघव लॉरेंस को बिना बताए फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया था और राघव ने फिल्म से अलग होने का ऐलान कर दिया था। कुछ दिनों बाद अक्षय कुमार ने इस मामले को सुलझाया और राघव वापस आए। इस मामले पर निर्माता होने के बावजूद तुषार कपूर ने दूर रहना ही बेहतर समझा। चुप्पी साधने को लेकर तुषार ने बताया, 'मैं उस वक्त बोलता तो वह आग में घी डालने वाली बात हो जाती। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। दरअसल, उस समय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग बयानबाजी की थी। अगर मैं कुछ बोलता तो कुछ और ही बनकर ही सामने आ जाता। मैं 'एक चुप सौ सुख' में यकीन रखता हूं। समय पर सच खुद सामने आ जाता है। जहां तक बात है प्रमोशन की तो मैं एक्टर के तौर पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करता हूं, लेकिन निर्माता के तौर पर चाहता हूं कि फिल्म अपने बारे में खुद बात करे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी फिल्म बहुत ज्यादा नजर में आए। जब फिल्म रिलीज होगी, तो उसका प्रमोशन अपने आप होगा।'

सनी देयोल के बेटे की फिल्म के लिए अभी करना होगा इंतजार

इस साल डेब्यू करने वाले स्टार किड्स में सनी देयोल के बेटे करण देयोल का नाम भी शुमार है। फिल्म 'पल पल दिल के पास' से करण बॉलीवुड का सफर शुरू करने वाले हैं। अपने बेटे को एक परफेक्ट डेब्यू फिल्म देने के लिए सनी देयोल ने ही इस फिल्म के निर्देशन की बागडोर अपने हाथों में रखी है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सनी राजनीतिक कार्यों में खासे व्यस्त हो गए हैं। करण की यह फिल्म पहले 19 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता के चलते अब 20 सितंबर को रिलीज होगी। इस नई तारीख की घोषणा करण देयोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करते हुए लिखा, 'हमारी फिल्म 'पल पल दिल के पास' को एक नई तारीख मिल गई है। इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है, अब हम 20 सितंबर को आ रहे हैं।' फिल्म में करण के साथ अभिनेत्री सहर बाम्बा होंगी। 'पल पल दिल के पास' शीर्षक वर्ष 1973 में रिलीज हुई धर्मेंद्र की फिल्म 'ब्लैकमेल' के हिट गाने की यादें ताजा करता है।

आठ साल बाद किरण राव ने निर्देशन में की वापसी

वर्ष 2011 में फिल्म 'धोबी घाट' का निर्देशन करने के बाद उन्होंने ब्रेक लिया था। हालांकि आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्मों के साथ वह हमेशा से जुड़ी रही हैं। अब आठ वर्षों का इंतजार खत्म करते हुए उन्होंने एक बार फिर निर्देशन में वापसी की है। फेसबुक इंडिया की पहल थम्बस्टॉपर्स के साथ मिलकर उन्होंने मोबाइल के लिए दस-दस सेकेंड के दो शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। वीडियो में उन्होंने लैंगिक असमानता और घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों को खत्म करने का संदेश दिया है। शॉर्ट फॉर्म में कहानी दर्शाना किरण राव के लिए चुनौतीपूर्ण था। बकौल किरण, 'आजकल लोग टीवी से ज्यादा फोन देखते हैं। वीडियो का आइडिया मिलने के बाद इसे शूट करना मुश्किल था, क्योंकि हमें बड़े पर्दे के मुताबिक सोचने की आदत है। आठ फ्रेम के अंदर सारी भावनाएं दिखानी थी। इसलिए मैंने तय किया था कि वीडियो में कोई संवाद नहीं होंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर का काम देखकर प्रेरित हो रही हूं।'

...अब पछता रही हैं परिणीति

साल 2015 में शुजीत सरकार की फिल्म आई थी 'पीकू'। फिल्म में अमिताभ बच्चन, इरफान खान के अलावा दीपिका पादुकोण भी थीं। इसके बारे में दिलचस्प खबर यह है कि यह फिल्म पहले परिणीति चोपड़ा को ऑफर की गई थी, जिसे करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब वह इस बात को लेकर पछता रही हैं। इससे स्पष्ट है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म के लिए पहली च्वॉइस नहीं थीं। इस बात की जानकारी मिली है नेहा धूपिया के चैट शो से, जिसमें हाल ही में परिणीति मेहमान बनी थीं। उनके साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी इस शो का हिस्सा थीं। बहरहाल, शो के दौरान यह पूछे जाने पर कि कैसे परिणीति का नुकसान दीपिका के लिए फायदेमंद साबित हुआ, तब परिणीति ने जवाब दिया, 'मेरे पास जब इस फिल्म का ऑफर आया था, उस समय मैं दूसरी फिल्म में व्यस्त थी। असमंजस में ही मैंने 'पीकू' करने से मना कर दिया। लेकिन जो फिल्म मैं कर रही थी, वह बनी नहीं और मुझे नुकसान हो गया।'

राकेश ओमप्रकाश मेहरा बनाएंगे 'महाभारत' पर फिल्म

'बाहुबली' फेम एसएस राजामौली ने कहा था कि महाभारत पर फिल्म बनाना उनका सपना है। यह आमिर खान का भी सपना रहा है। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस में बड़े स्तर पर अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। आमिर खान अपने इस संभावित प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित भी थे, लेकिन अपने 54वें जन्मदिन पर उन्होंने हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' पर आधारित फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। अब

कुछ लोग कह रहे हैं कि आमिर खान ने महाभारत पर फिल्म बनाने का आइडिया फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। लेकिन ताजा खबर यह है कि राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने 'महाभारत' को प्रोड्यूस करने का निर्णय ले लिया है।

चिंताजनक

एंबिओ जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन के अनुसार, भारत में कई मछुआरे और व्यापारी शार्क संरक्षण के नियमों से अनजान हैं, इसके लिए जागरूक किए जाने की जरूरत है

भारत में गिर रही है शार्क मछलियों की संख्या

वास्को-द-गामा (गोवा), आइएसडब्ल्यू : भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शार्क मछली पालने वाला देश माना जाता है लेकिन मछुआरे और मछली व्यापारी शार्क संरक्षण के नियमों से अनजान हैं। इसके कारण पिछले कई वर्षों से यहां शार्क मछलियों की संख्या लगातार कम हो रही है। एंबिओ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, भारतीय मछुआरे प्रायः बड़ी शार्क मछलियां नहीं पकड़ते हैं, बल्कि दूसरी मछलियों को पकड़ने के लिए डाले गए जाल में बड़ी शार्क भी फंस जाती हैं। ज्यादातर मछुआरे और व्यापारी जानते हैं कि व्हेल शॉर्क को पकड़ना गैर- कानूनी है। लेकिन वे शार्क की अन्य प्रजातियों जैसे- टाइगर, हेमरहेड, बुकशार्क, पिगी शार्क आदि के लिए निर्धारित राष्ट्रीय शार्क संरक्षण मानकों से अनजान हैं।

शार्क मछलियों को उनके मांस और पंखों के लिए पकड़ा जाता है। इनके पंखों के अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति काफी हद तक अनियमित है। भारत में शार्क के मांस के लिए एक बड़ा घरेलू बाजार है। जबकि निर्यात बाजार छोटा है। यहां छोटे आकार और किशोर शार्क के मांस की मांग सबसे ज्यादा है। आमतौर पर एक मीटर से छोटी शार्क मछलियां ही पकड़ी जाती हैं और छोटी शार्क स्थानीय बाजारों में महंगी बिकती हैं। शार्क संरक्षण को लेकर किए

दुनिया में 4000 प्रजाति की शार्क पाई जाती हैं। फाइल

गए एक अध्ययन में ये बातें सामने आई हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, हरियाणा, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया और एलेस्मो प्रोजेक्ट, संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन में शार्क व्यापार के दो प्रमुख केंद्रों गुजरात के पोरबंदर और महाराष्ट्र के मालवन में सर्वेक्षण किया गया है। भारत में शार्क मछलियां पकड़ने में गुजरात और महाराष्ट्र का कुल 54 प्रतिशत योगदान है। शार्क मछलियां पकड़ने के लिए पोरबंदर में 65 प्रतिशत ट्राल नेटों और मालवन में 90 प्रतिशत गिलनेटों सहित हुक एंड लाइन मत्स्य पालन विधि का उपयोग होता है। अध्ययन से जुड़ीं अशोका यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता डॉ. दिव्या कर्नाड ने बताया कि बड़ी शार्क मछलियों की संख्या में लगातार गिरावट की जानकारी ज्यादातर मछुआरों और व्यापारियों को है और व्यापारी स्थानीय नियमों का पालन भी करते हैं। लेकिन, भारत में शार्क मछलियों की संख्या में गिरावट के सही मूल्यांकन के लिए बड़े पैमाने पर शोध करने होंगे।

शार्क के बाजार में गिरावट : शोधकर्ताओं के अनुसार, पिछले दस सालों में शार्क पंखों की अंतरराष्ट्रीय बिक्री में 95 प्रतिशत तक गिरावट हुई है। उत्तर-पश्चिमी भारत में शार्क मछलियों की संख्या और आकार में लगातार गिरावट का आर्थिक असर मछुआरों और व्यापारियों पर पड़ रहा है। अध्ययन के आंकड़े स्थानीय मछुआरों, नौका मालिकों, खुदरा विक्रेताओं और मछली व्यापारियों से साक्षात्कार के आधार पर एकत्रित किए गए।

पंखों का होता है विदेश में व्यापार : अध्ययन से पता चला है कि मछली पकड़ना भारतीय मछुआरों का प्राथमिक व्यवसाय है और शॉर्क व्यापार सिर्फ अतिरिक्त आमदनी का जरिया है। व्यापारी पूरी शार्क एक जगह से ही खरीदते हैं। लेकिन, उसके पंख और मांस अलग- अलग बेचते हैं। शार्क के पंख मालवन से मडगांव और मंगलूरु जैसे दो प्रमुख मछली व्यापार केंद्रों से होते हुए अंततः चीन और जापान में भेजे जाते हैं। इसी तरह, पोरबंदर से ओखा, वैरावल, मुम्बई, कालीकट और कोच्चि से होते हुए सिंगापुर, हांगकांग और दुबई व आबूधाबी तक शार्क के पंख भेजे जाते हैं।